{ विश्वास वही रफ्तार नई }

बालाघाट
शनिवार 22 अगस्त 2026
श्रावण शुक्ल 10 विक्रम सम्वत 2083
वर्ष 16, अंक 328
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 7.00

पद्मेश मीडिया समूह का प्रकाशन

बालाघाट एक्सप्रेस

हिन्दी दैनिक

सेंसेक्स - 77,540.83
निफ्टी - 24,252.00
सोना - 1,47,100
चांदी - 2,60,000
डॉलर - 95.69

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

राहुल के दबाव में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज

पैलेट गन फायरिंग में घायल हुए छात्र साहिल लोचब को न्याय दिलाने करीब 6 घंटे संसद मार्ग स्थित डीसीपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रियंका गांधी...

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर प्रदर्शनकारी छात्र साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन मामला अज्ञात पर दर्ज किया गया है। साहिल का आरोप है कि पैलेट छर्रे लगने से उसकी आंख की रोशनी चली गई। एफआईआर दर्ज करवाने तक राहुल थाने के बाहर ही बैठे रहे। वे शुक्रवार दोपहर करीब 12.30 बजे से संसद मार्ग थाने पहुंचे थे। जब उनकी मांग नहीं मानी गई, तो वे डीसीपी से मिले। बातचीत का नतीजा न निकलने पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा था कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, वे हटेंगे नहीं। इसके बाद 5.30 बजे पुलिस ने प्रोसेस शुरू की। यानी राहुल गांधी 6 घंटे धरने पर बैठे तब जाकर एफआईआर दर्ज की गई। इससे पहले राहुल ने साहिल को लगे छर्रे दिखाकर कहा था कि पैलेट गन चलने के सबूत हैं। ये छर्रे साहिल के शरीर से निकले हैं। अगर पुलिस ने गन नहीं चलाई तो किसने चलाई है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे। जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन के दौरान पेलेट गन से आंख गंवाने वाल साहिल लोचब और उनकी मां भी थीं। राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट सीपी नूपुर प्रसाद से मिलने पहुंचे थे, जिन्होंने हाल ही में अपना पदभार संभाला है। राहुल गांधी कई शिकायतें लेकर उनके पास गए और उन पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन तत्काल कोई फैसला नहीं हुआ। इसके बाद बाहर निकलकर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। उनके लिए कुर्सी लगाई गई और मौके पर मीडियाकर्मियों व सुरक्षाकर्मियों की भीड़ जुट गई। राहुल के साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद थे। अंतत- राहुल के दबाव में मामला बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत दर्ज किया गया है। धारा 118 खतरनाक हथियार या साधन से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ी है, जबकि धारा 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से संबंधित है। राहुल गांधी ने कहा कि ये न्याय का पहला कदम है।

अमित शाह और होम सेक्रेटरी पर लगाए आरोप

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमने बस एक भारतीय नागरिक उसके माता-पिता के लिए न्याय मांगा और इसमें आठ घंटे लग गए। आखिरी मंजूरी होम सेक्रेटरी और खुद अमित शाह से आनी थी। तो, आप समझ सकते हैं कि एफआईआर दर्ज होने से को कौन रोक रहा था। ये पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करना चाहते थे, लेकिन न्याय की प्रक्रिया को ऊपर से रोका जा रहा था।

कुचले जा रहे हैं संवैधानिक अधिकार

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि आज साहिल लोचब के साथ, उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचा। 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। छर्रों से बुरी तरह घायल साहिल की एक आंख की रौशनी खतरे में है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, एक गंभीर अपराध है। इस क्रूरता के लिए न गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को कोई सफाई दी, न प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगी। अब जब साहिल न्याय के लिए एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो वो भी नहीं करने दिया जा रहा। इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है।

ये न्याय की तरफ पहला कदम है- राहुल

एफआईआर लिखे जाने के बाद साहिल के परिवार के साथ बाहर आए राहुल गांधी ने कहा कि हमने यहां आकर कुछ नया नहीं किया। लेकिन हमें यहां 8 घंटे लग गए, अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए। ये न्याय की तरफ पहला कदम है। राहुल ने कहा कि पुलिसवाले शिकायत दर्ज करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऊपर से रोककर रखा गया था। कांग्रेस ने इस मामले में सवाल उठाया था कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। पार्टी ने कहा था कि अमित शाह और दिल्ली पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया था कि साहिल और उसकी मां लगातार एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही थी। हालांकि बाद में पुलिस ने शिकायत ले ली थी और बताया था कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी भी गठित हो चुकी थी और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। इससे पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी धरने पर बैठे थे, जहां से उन्हें हिरासत में लेकर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा समेत कई नेता भी मौके पर पहुंचे थे।

राहुल का प्रोटेस्ट मीडिया फुटेज के लिए- जेपी नड्डा

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर राहुल गांधी के धरने को लेकर कहा कि पूरा देश एक बार फिर उस तरह की सस्ती और ध्यान खींचने वाली राजनीति देख रहा है, जिसका प्रदर्शन राहुल गांधी ने आज किया। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय की मांग को लेकर। नड्डा के मुताबिक, यह कांग्रेस की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी की मीडिया में बने रहने की कोशिश का प्रतीक है।

वंदे मातरम के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश - रविशंकर

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के धरने को ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समझ आ गया है कि वंदे मातरम के मुद्दे पर उसका रुख गलत था। प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने रुख को लेकर फंस गई है और इसी से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल ने बिना अनुमति और पूर्व सूचना के प्रदर्शन किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मामले की जांच पहले से चल रही है, तो कांग्रेस ने जांच के दौरान प्रदर्शन क्यों किया। प्रसाद ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई उच्चाधिकार समिति के सामने भी है।

जाति आधारित आरक्षण के विरोध में जंतर-मंतर पर जुटे सैकड़ों लोग, इंस्टाग्राम अपील का दिखा असर

नई दिल्ली । नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुक्रवार को जाति आधारित आरक्षण के विरोध में सैकड़ों लोग जुटे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकारी योजनाओं और आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को बनाया जाए। यह प्रदर्शन 'रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन' नाम के इंस्टाग्राम पेज की अपील के बाद आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा, कोचिंग, छात्रवृत्ति और फीस में सहायता जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से जुड़े एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि सरकारी मदद जरूरत के आधार पर तय होनी चाहिए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की भी मांग की। उनका कहना था कि लंबे समय से लागू व्यवस्था के बावजूद इसके लाभ सबसे पिछड़े लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रदर्शन में क्रीमी लेयर का नियम लागू करने और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित नीतियों में बदलाव की मांग भी उठी। प्रदर्शनकारियों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तथा उच्च शिक्षा नीतियों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत जंतर-मंतर के आसपास पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी तथा बैरिकेडिंग की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सुबह जमा हुए लोगों को वहां से हटा दिया गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने इंटरनेट बाधित किए जाने का आरोप लगाया, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी।

खास खबर

मॉल की शटरिंग गिरी, तीन की मौत

मथुरा। मथुरा में शुक्रवार सुबह 7 बजे निर्माणाधीन ओमेक्स मॉल की शटरिंग गिर गई। हादसे के समय 4-5 काम कर रहे थे। उनमें से 4 मजदूर मलबे में दब गए। शटरिंग गिरते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसकी सूचना फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही थोड़ी देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान एक मजदूर को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी पहचान नेपाल के रहने वाले शिवराम (40) के रूप में हुई है। मलबा हटाने के दौरान तीन मजदूर घायल हालत में मिले। उन्हें फौरन एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां से हालत गंभीर होने पर बाद में उन्हें आगरा के एसएन मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया।

सीएम रेवंत को नहीं मिली अमेरिका दौरे की इजाजत

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई में तेलंगाना राइजिंग डेलिगेशन विदेश दौरे पर है. सीएम रेवंत की अगुवाई में लंदन गए डेलिगेशन को ब्रिटेन से 23 अगस्त को अमेरिका के बोस्टन जाना था. रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाले डेलिगेशन को विदेश मंत्रालय ने अमेरिका दौरे की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. विदेश मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली, ऐसे में सीएम रेवंत की अगुवाई वाला डेलिगेशन अब 23 अगस्त को लंदन से बोस्टन की जगह हैदराबाद के लिए उड़ान भरेगा. तेलंगाना सरकार ने प्रोटोकॉल के तहत सीएम की अगुवाई वाले डेलिगेशन के ब्रिटेन और अमेरिका दौरे के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी. केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर केवल ब्रिटेन दौरे के लिए ही मंजूरी दी. सीएम की अगुवाई वाले डेलिगेशन के ब्रिटेन पहुंचने के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से तेलंगाना सरकार को इस बात की जानकारी दी गई. अनुमति नहीं मिलने के कारण सीएम रेड्डी का अमेरिका दौरा ऐन मौके पर रद्द हो गया।

मंत्री के खिलाफ विधायकों ने खोला मोर्चा

नई दिल्ली। तेलंगाना कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के 18 विधायकों और एमएलसी ने मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुरेखा को पार्टी से निलंबित या बाहर करने की मांग की। इन नेताओं को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के समर्थक गुट का माना जा रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि कोंडा सुरेखा समेत कुछ वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं।

कुछ ना कहना

सिखों की रिहाई के लिए 7 घंटे पंजाब बंद

हाईवे के साथ पिज्जा शॉप-क्लब बंद कराए, पुलिस-प्रदर्शनकारियों में बहस

चंडीगढ़/मोहाली। कौमी इंसाफ मोर्चा की ओर से शुक्रवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पंजाब बंद रखा गया। मोर्चा सजा पूरी होने के बावजूद जेल में बंद सिखों की रिहाई और पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने की मांग कर रहा है। बंद के दौरान बसों के साथ सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहे। हालांकि ट्रेनों पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। खरड़-चंडीगढ़ हाईवे को बंद किया गया था। यहां ड्यूटी पर जाने वाले लोगों की मोर्चा के सदस्यों से बहस भी हुई। मोहाली में निहंगों ने पिज्जा शॉप बंद कराई। इसे साथ अमृतसर, पटियाला और लुधियाना में कौमी इंसाफ मोर्चा के सदस्यों ने खुली दुकानों को बंद करवाया। इससे पटियाला में माहौल तनावपूर्ण हो गया था।

जालंधर में प्रदर्शनकारी ने कार सवार को थप्पड़ मार दिया था। कार सवार अस्पताल जा रहा था। रास्ते में रोकने को लेकर विवाद हो गया। वहीं, फरीदकोट में प्रदर्शनकारियों ने आप विधायक डिंपी ढिल्लों की बस को रोक दिया था। बस को रोके जाने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उसे वापस बस स्टैंड भेज दिया। अमृतसर और मोहाली में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस भी हुई। इस बीच चंडीगढ़ भाजपा के स्टेट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ई-मेल में पंजाब बंद रखने और बंद के दौरान खुले रहने वाले शहरों में बम धमाके करने का भी जिक्र था। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं और जांच शुरू की।

अब एक साल वकालत कर भी बन सकेंगे जज

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बदले न्यायिक सेवा में प्रवेश के नियम

नई दिल्ली। न्यायिक सेवा में प्रवेश की तैयारी कर रहे कानून स्नातकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बदलाव किया है। कोर्ट ने निचली अदालतों में जज बनने के लिए वकालत की प्रैक्टिस को अनिवार्य रखने के अपने फैसले को बरकरार रखा है, लेकिन न्यूनतम प्रैक्टिस की अवधि तीन साल से घटाकर एक साल कर दी है। इसके साथ ही चयनित उम्मीदवारों के लिए कठोर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी तय की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायिक सेवा में आने वाले उम्मीदवारों के पास अदालत की कार्यप्रणाली और वकालत का व्यावहारिक अनुभव होना जरूरी है। हालांकि, तीन साल की अनिवार्य प्रैक्टिस की शर्त से कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं के लिए न्यायिक सेवा में प्रवेश का रास्ता लंबा हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए अवधि घटाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के अनुसार न्यायिक सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले एक साल का गहन प्रशिक्षण लेना होगा। यह प्रशिक्षण राज्य की न्यायिक अकादमी में दिया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को कुल एक साल की क्लर्कशिप भी करनी होगी। इसमें छह महीने जिला जज या उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी के साथ और अगले छह महीने हाईकोर्ट के मौजूदा जज के साथ काम करना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य नए न्यायिक अधिकारियों को अदालत की वास्तविक कार्यप्रणाली, मामलों की सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया का व्यावहारिक अनुभव देना है।

तीन साल की जगह अब एक साल की प्रैक्टिस

मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश स्तर के न्यायिक पदों के लिए वकील के तौर पर कम से कम तीन साल की प्रैक्टिस अनिवार्य की थी। इस फैसले के खिलाफ कई समीक्षा याचिकाएं दाखिल की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने रुख में संशोधन करते हुए प्रैक्टिस की न्यूनतम अवधि एक साल कर दी है। यानी कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उम्मीदवार को कम से कम एक साल अदालत में सक्रिय वकालत का अनुभव हासिल करना होगा। इसके बाद वह न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए पात्र होगा।

कटनी जमीन घोटाला मामले में सीएम डॉ. मोहन का बड़ा एक्शन

सीएसपी नेहा पच्चीसिया सस्पेंड, सख्त कार्रवाई के निर्देश

कटनी/भोपाल। मध्य प्रदेश के कटनी में जमीन से जुड़े मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने मामले में कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया के विरुद्ध तत्काल निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है।

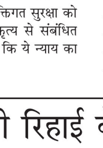

दरअसल, कटनी में जमीन से जुड़े एक मामले में सीएसपी नेहा पच्चीसिया का नाम सामने आया है। आरोप है कि एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत की जमीन को दबाव बनाकर करीब 18 लाख रुपये में खरीदा गया। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में लापरवाही या किसी तरह की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध तत्काल निलंबन की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि इस मामले में पहले ही सीएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वहीं कार्रवाई जारी है।

नेहा पच्चीसिया समेत तीन पर दर्ज हुई थी एफआईआर

कटनी के कुठला थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 61, 198, 199, 308(7) और 318(4) के तहत नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बारापत्रे और मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ गुरुवार प्रकरण दर्ज किया था। शिकायतकर्ता आकाश उर्फ रमेश लोधी का आरोप है कि उनके पिता रमेश लोधी पर दबाव बनाकर ग्राम कन्हवारा की जमीन की रजिस्ट्री 15 अप्रैल 2026 को मारूफ अहमद हनफी के नाम करा दी गई। वहीं, शिकायत के मुताबिक जमीन का सौदा 1.07 करोड़ रुपये में तय हुआ था, लेकिन रजिस्ट्री 18.20 लाख रुपये में कराई गई। आरोप है कि 15 लाख रुपये का चेक और 3.20 लाख रुपये नकद दिए गए, जबकि बाकी की राशि का भुगतान नहीं किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि रमेश लोधी के जेल में रहने के दौरान खरीदार के पक्ष में जमीन का नामांतरण भी करा दिया गया। शिकायत में सीएसपी नेहा पच्चीसिया पर यह आरोप भी लगाया गया है कि उन्होंने रमेश लोधी को दो दिन तक अपने घर पर रखा और सरकारी वाहन से रजिस्ट्री कार्यालय ले जाया गया। पुलिस ने इन आरोपों की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की है। हालांकि आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। अब इस पूरे मामले में पुलिस की जांच का सबसे अहम पहलू 15 अप्रैल 2026 को मारूफ अहमद हनफी के खाते में पहुंचे 15 लाख रुपये का बैंक ट्रांजेक्शन माना जा रहा है।

सीजेपी प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं से मारपीट का मामला गरमाया, 48 घंटे का अल्टीमेटम

दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन

जयपुर। बगरू क्षेत्र के रामपुरा कंवरपुरा गांव में शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके साथियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सीजेपी की टीम राजकीय प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने उनका विरोध किया और कथित तौर पर उनके साथ धक्का-मुक्की व मारपीट की। टीम की गाड़ियों पर पथराव किए जाने का भी आरोप है। घटना में आशुतोष रांका समेत सीजेपी के पांच कार्यकर्ताओं के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही गई है, जबकि सात अन्य लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए जयपुर के स्रूस् अस्पताल लाया गया।

जानकारी के मुताबिक, सीजेपी कार्यकर्ता शुक्रवार सुबह स्कूल का निरीक्षण करने रामपुरा कंवरपुरा पहुंचे थे। इससे पहले सुबह करीब 8 बजे ही कुछ कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच धक्का-मुक्की हुई थी। ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव से बाहर निकाल दिया। इसके बाद ग्रामीण स्कूल के बाहर सीजेपी के विरोध में धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने गांव के मुख्य रास्ते पर ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर रास्ता घेर दिया और आने-जाने वाले वाहनों की जांच भी शुरू कर दी। बाद में जब सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ स्कूल पहुंचे तो विवाद बढ़ गया।

गाड़ियां और मोबाइल तोड़े

आशुतोष रांका ने हमले का आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया है। उनका कहना है कि हमले के दौरान उनकी गाड़ी के शीशे और मोबाइल तोड़ दिए गए। एक महिला समर्थक के साथ मारपीट की गई और उसकी शर्ट फाड़ दी गई। सीजेपी टीम के एक सदस्य के हाथ में फ्रैक्चर होने की भी बात कही गई है। रांका ने कहा कि पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर हमले के पीछे होने का आरोप लगाते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उनकी मांग है कि हमले में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाए और स्कूल निरीक्षण रोकने का आदेश वापस लिया जाए।

नियुक्ति दिनांक से दिया जाए सत प्रतिशत वेतनमान का लाभ, जबरन वसूली पर भी लगे रोक

वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन, 10 साल से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों ने गिनाई समस्याए

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न लंबित मांगों और कर्मचारियों के साथ हो रही वेतन विसंगति के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संघ ने वर्ष 2019 से वन विभाग में नियुक्त हो रहे कर्मचारियों को प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत और तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत वेतन दिए जाने की व्यवस्था समाप्त कर नियुक्ति दिनांक से ही शत-प्रतिशत वेतनमान दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही संघ ने वन राजस्व हानि के नाम पर कर्मचारियों से कथित तौर पर की जा रही जबरन वसूली पर रोक लगाने, गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणियों की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने तथा वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को न्याय दिलाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई है

वनों को नुकसान पहुंचाए कोई और, वसूली कर्मचारी से क्यों?

ज्ञापन में संघ ने वन राजस्व हानि के मामले को भी गंभीरता से उठाया है।बताया गया कि वनों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी और निस्तार के लिए होने वाली गतिविधियों के साथ ही चरवाहों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा कई बार जंगलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। इससे वन राजस्व की हानि होती है। ऐसे मामलों में बेगुनाह कर्मचारियों पर आर्थिक भार न पड़े, इसके लिए राज्य शासन द्वारा क्षतिपूर्ति की व्यवस्था बनाई गई है। इस व्यवस्था के तहत वन राजस्व हानि को लेखन करने के लिए निर्धारित अधिकार दिए गए हैं। संघ के अनुसार वन मंडल अधिकारी को 2 हजार रुपए तक, वन संरक्षक को 5 हजार रुपए तक तथा 5 हजार रुपए से अधिक की राजस्व हानि के मामलों में राज्य शासन की अनुमति लेकर कार्रवाई करने की व्यवस्था है।इसके बावजूद संघ ने आरोप लगाया कि कई मामलों में अधिकारियों द्वारा वन कर्मचारियों से कथित तौर पर जबरन वसूली की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि जिन मामलों में उनकी व्यक्तिगत गलती या संलिप्तता नहीं होती, उनमें भी आर्थिक दंड का भार उन पर डाला जा रहा है।

समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो

संघ पदाधिकारियों ने बताया है कि वन विभाग में नवनियुक्त कर्मचारी भी नियुक्ति के साथ ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी क्षमता के साथ करते हैं। ऐसे में उन्हें कई वर्षों तक पूर्ण वेतन से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है। संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वेतन विसंगति को दूर करते हुए शीघ्र आदेश जारी किए जाएं, ताकि नवनियुक्त कर्मचारियों को समानता और न्याय मिल सके।

बिना सूचना गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी का आरोप

संघ ने ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन में बिना पूर्व सूचना प्रतिकूल टिप्पणी किए जाने का मुद्दा भी उठाया। पदाधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों को कई बार यह जानकारी तक नहीं दी जाती कि उनके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की गई है। बाद में यही टिप्पणियां उनके सेवाकाल और पदोन्नति के अवसरों को प्रभावित करती हैं।संघ ने मांग की है कि गोपनीय प्रतिवेदन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और कर्मचारी को उसके विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणी की जानकारी देकर नियमानुसार अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाए।

लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 में संशोधन की मांग

संघ ने ज्ञापन में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करने की मांग भी की है। संघ ने उप नियम 10 (2) के अनुसार लघु शास्ति के अंतर्गत वसूली की प्रभावशीलता अवधि को एक वर्ष रखने संबंधी व्यवस्था को समाप्त करने की मांग उठाई है।इसके अलावा उप नियम 11 (6.2) के अंतर्गत गोपनीय प्रतिवेदन के अंक 12 के स्थान पर पूर्व की व्यवस्था के अनुसार 10 अंक किए जाने की मांग की गई है। संघ ने मांग की है कि जिन कर्मचारियों को बिना किसी गंभीर गलती के वसूली या वसूली प्रस्तावित होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, उन्हें पात्रता के आधार पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए।

न्यायोचित मांगों पर शीघ्र निर्णय की अपेक्षा

संघ पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं और इनका सीधा प्रभाव वन विभाग के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों पर पड़ रहा है। वेतन विसंगति समाप्त कर नियुक्ति से शत-प्रतिशत वेतनमान देने, अनुचित वसूली पर रोक लगाने और पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए शासन को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ के महासचिव नारायण सिंह टेकाम, कोषाध्यक्ष संतोष मस्करे सहित वेतन विसंगति और पदोन्नति से प्रभावित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

तीन साल तक कम वेतन से कर्मचारियों में नाराजगी-श्रीराम घरते

ज्ञापन को लेकर की गई चर्चा के दौरान संघ के जिलाध्यक्ष श्रीराम घरते ने बताया कि वर्तमान वेतन व्यवस्था के कारण एक ही विभाग में समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच आर्थिक असमानता और वेतन विसंगति की स्थिति निर्मित हो रही है। वर्ष 2019 से नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत भुगतान किया जा रहा है। लंबे समय से चली आ रही इस व्यवस्था के कारण नवनियुक्त कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं विभाग के कर्मचारियों में असंतोष भी बढ़ रहा है। संघ ने शासन से मांग की है कि कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय लेते हुए 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन भुगतान की व्यवस्था को समाप्त किया जाए और नियुक्ति की तारीख से ही पूर्ण 100 प्रतिशत वेतन प्रदान किया जाए।

प्रमुख मांगें एक नजर में

वर्ष 2019 से लागू 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन व्यवस्था समाप्त की जाए।

नवनियुक्त वन कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से शत-प्रतिशत वेतनमान दिया जाए।

वन राजस्व हानि के मामलों में बेगुनाह कर्मचारियों से की जा रही कथित जबरन वसूली पर रोक लगे।

गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी से पहले कर्मचारियों को सूचना और पक्ष रखने का अवसर दिया जाए।

10 वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को न्याय मिले।

लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के उप नियम 10 (2) और 11 (6.2) में आवश्यक संशोधन किए जाएं।

केवल वसूली अथवा वसूली प्रस्तावित होने के कारण पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की जाए।

10 साल से पदोन्नति की प्रतीक्षा, छोटी-छोटी वसूली बनी बाधा-पडवार

संभागीय अध्यक्ष रोशन लाल पडवार ने बताया की विभाग के अनेक कर्मचारी करीब 10 वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन वन राजस्व हानि के नाम पर की गई छोटी-छोटी वसूली अथवा वसूली प्रस्तावित होने के कारण कई कर्मचारी पदोन्नति के लिए अपात्र हो गए हैं।उन्होंने इस व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा कि बिना किसी गंभीर गलती के केवल वसूली या वसूली प्रस्तावित होने के आधार पर कर्मचारियों को वर्षों तक पदोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं है। इससे कर्मचारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और उनके कैरियर की प्रगति बाधित हो रही है।

जबलपुर से गोंदिया दोहरी रेल लाइन का जल्द शुरू किया जाए निर्माण

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जबलपुर से गोंदिया के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य शीघ्र शुरू किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। ज़ोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी (जेडआरयूसी), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर एवं पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर के पूर्व सदस्य ओमप्रकाश कुकासे ने इस संबंध में प्रधानमंत्री भारत सरकार को पत्र लिखकर जबलपुर-गोंदिया रेल मार्ग के दोहरीकरण कार्य को यथाशीघ्र शुरू कराने की मांग की है।पूर्व जेडआरयूसी सदस्य कुकासे ने पत्र में उल्लेख किया है कि वर्तमान में इस महत्वपूर्ण रेलखंड पर यात्री एवं मालगाड़ियों का अत्यधिक दबाव बना हुआ है। रीवा-हड़पसर पुणे एक्सप्रेस 20152, रीवा-इतवारी एक्सप्रेस 11753 सहित बड़ी संख्या में गुड्स ट्रेनों के आवागमन के कारण रेल यातायात व्यस्त रहता है। एकल रेल लाइन होने के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों को समय पर ट्रैक उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके चलते यात्रियों को घंटों विलंब का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में रेल परिचालन विभाग भी सीमित संसाधनों के कारण मजबूर रहता है।ओमप्रकाश कुकासे ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि रेल मंत्री को जबलपुर-गोंदिया दोहरी रेल लाइन निर्माण कार्य जल्द शुरू एवं पूर्ण कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएं। उनका कहना है कि इस मार्ग का दोहरीकरण होने से यात्री ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार होगा, मालगाड़ियों का संचालन सुचारू होगा तथा जबलपुर, बालाघाट और गोंदिया के बीच रेल यातायात को गति मिलेगी।

गोंदिया स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 6 का भी किया उल्लेख

पत्र में कुकासे ने गोंदिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 6 के निर्माण का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले उन्होंने और गोंदिया के तत्कालीन जेडआरयूसी सदस्य रमन मेठी ने बिलासपुर के महाप्रबंधक से गोंदिया रेलवे स्टेशन पर नया प्लेटफार्म क्रमांक 6 निर्मित कराने का अनुरोध किया था। इसका उद्देश्य बालाघाट की ओर से आने वाली तथा जबलपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों का आवागमन स्टेशन के बाहरी हिस्से से अधिक सुगमता से कराना था।यह प्लेटफार्म निर्मित भी हो चुका है। हालांकि, कुकासे ने वर्तमान व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कई बार इस ट्रैक पर गुड्स ट्रेनों को खड़ा कर दिया जाता है, जिससे यात्री ट्रेनों के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। उन्होंने इसे यात्रियों के हित में उचित नहीं बताते हुए सुझाव दिया कि बिलासपुर से पुणे, नागपुर और मुंबई की ओर जाने वाली यात्री ट्रेनों को प्लेटफार्म क्रमांक 1 एवं 2 से सीधे रवाना किया जाए, जबकि गुड्स ट्रेनों को स्टेशन के आउटर पर रोका जाए।

पहले भी भेजा जा चुका है निवेदन पत्र

पूर्व जेडआरयूसी सदस्य ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में पूर्व में भी प्रधानमंत्री को निवेदन पत्र भेजा था, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय के स्टाफ द्वारा भारतीय रेलवे बोर्ड को अग्रेषित किया गया था। इसकी पावती उन्हें पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई थी। अब उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री से जबलपुर-गोंदिया रेलखंड के दोहरीकरण को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है।कुकासे का कहना है कि जबलपुर से गोंदिया तक दोहरी रेल लाइन का निर्माण केवल बालाघाट और गोंदिया क्षेत्र के यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि इस पूरे महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। दोहरीकरण से ट्रेनों की लेटलतीफी कम होने के साथ ही यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और समयबद्ध रेल सेवा मिल सकेगी।

1450 रुपये के लेनदेन को लेकर मारपीट- पिता-पुत्रों सहित तीन पर मामला दर्ज

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। किरनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम दीगोदा में महज 1450 रुपये के लेन-देन को लेकर एक व्यक्ति को तीन लोंगों ने अपने घर के सामने रोककर मारपीट कर घायल कर दिये और रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। घायल का व्यक्ति जागेंद्र पिता भैया लाल राहंगडाले 52 वर्ष। का इलाज किरनापुर अस्पताल में कराया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम दीगोदा निवासी जागेंद्र राहंगडाले खेती किसानी के साथ दूध बेचने का व्यवसाय करते हैं। उनके बेटे मोनू राहंगडाले का गांव के ही अखिलेश बांगरे के साथ पैसों का लेन-देन था। मोनू को अखिलेश को 1450 रुपये देना था। इसी बात को लेकर अखिलेश पहले भी दो-तीन बार जागेंद्र के घर आकर गाली-गलौज कर चुका था। 20 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे जब जागेंद्र दूध बेचकर अपने घर वापस लौट रहे थे तभी गांव में अखिलेश बांगरे, उसके भाई कमलेश बांगरे और पिता सालिकराम बांगरे ने उन्हें अपने घर के सामने रोक लिया। तीनों कहने लगे कि तुम्हारा लड़का पैसे नहीं दे रहा है इसी बात पर गाली-गलौज करने लगे। जागेंद्र ने गाली देने से मना किया तो तीनों ने आवेश में आकर अश्लील गालियां देते हुए हाथ-बुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर मोहल्ले-पड़ोस के लोग दौड़े और बीच-बचाव किया। मारपीट में जागेंद्र घायल हो गए। इसके बाद तीनों ने रुपये नहीं देने पर जान से खत्म करने की धमकी दी।घायल जागेंद्र अपने बेटे मोनू के साथ किरनापुर थाने पहुंचे और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। किरनापुर पुलिस ने घायल जागेन्द्र का इलाज और मुलाइज अपने यहां के अस्पताल में करवाये । जागेंद्र की रिपोर्ट पर आरोपी अखिलेश बांगरे, कमलेश बांगरे और पिता सालिकराम बांगरे के विरुद्ध अश्लील गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

सँयुक्त क्रांति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष समरीते ने प्रधानमंत्री सड़क योजना में लगाया अनियमितताओं का आरोप

जांच व वैधानिक कार्रवाई की करी मांग, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लगाए गंभीर आरोप

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लांजी के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने प्रधानमंत्री (भारत सरकार) को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की विशेष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।इस संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति में सँयुक्त क्रांति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समरीते ने बताया कि मप्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना में अनिमियता बरती गई है।उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं परियोजना संचालक द्वारा निर्धारित मापदंडों और नियमों की अनदेखी की गई है।समरीते के अनुसार, बालाघाट जिले की तहसील लांजी के ग्राम लोढ़ामा से मुण्डीदादर एवं हर्राडेही से केराडेही मार्ग के निर्माण कार्य में एक कंपनी कथित अनियमितताएं की गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोढ़ामा से मुण्डीदादर मार्ग में करीब 3364 पेड़ों की कटाई तथा हर्राडेही से केराडेही मार्ग में लगभग 1500 पेड़ काटे गए। आरोप है कि कटे हुए पेड़ों की लकड़ी को छत्तीसगढ़ राज्य में बेच दिया गया, जो गंभीर अनियमितता का मामला है।पूर्व विधायक समरीते ने कहा कि पेड़ों की कटाई की अनुमति और सड़क निर्माण की स्वीकृति वन विभाग द्वारा जारी की गई थी, लेकिन निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी, मुरम और गिट्टी के परिवहन को दर्शाकर कथित रूप से दूसरे स्थानों पर खर्च दिखाया गया, जबकि सड़क निर्माण में आवश्यक साइड का मटेरियल भी खोदकर उपयोग में लाया गया।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी उपभोक्ता प्रमाण-पत्र नहीं लिया गया है फर्जी प्रमाण पत्र लगाया गया है। हर्राडेही से केराडेही मार्ग पर करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र में सड़क का निर्माण नहीं किया गया, वहीं बिना घाट कटिंग किए घाट कटिंग का पैसा निकाले जाने का भी आरोप लगाया गया है।किशोर समरीते ने पूरे मामले को गंभीर एवं प्रमाणित बताते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय से विशेष जांच कराने की मांग की है।उन्होंने मांग की है कि मामले में अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित कर दोषियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाए, ताकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हुई कथित गड़बडियों का खुलासा हो सके।

बदहाल जिला अस्पताल पुलिस चौकी का डेढ़ माह से शौचालय है बंद

छत से टपकता पानी और बंद शौचालय ने बढ़ाई परेशानी
अस्पताल प्रबंधन के आश्वासन के बावजूद नहीं हुआ समाधान

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। भगत सिंह शासकीय जिला अस्पताल परिसर में संचालित पुलिस चौकी इन दिनों अव्यवस्थाओं का शिकार है। चौकी की छत से बरसात का पानी टपकने की समस्या के बीच पिछले करीब डेढ़ माह से शौचालय खराब पड़ा है। शौचालय बंद होने के कारण चौकी में तैनात पुलिस कर्मचारियों को दैनिक निस्तार के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस कर्मचारियों द्वारा समस्या से अस्पताल प्रबंधन को अवगत कराने के बावजूद अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया है।

दिन में किसी तरह काम चलता है- रात में बढ़ जाती है मुश्किल

चौकी में तैनात कर्मचारियों के मुताबिक दिन के समय वे जिला अस्पताल परिसर में संचालित सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन रात होते ही स्थिति मुश्किल हो जाती है। सार्वजनिक सुलभ शौचालय बंद हो जाने के बाद रात्रि ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों के सामने लघुशंका और दीर्घशंका के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं रहती। मजबूरी में उन्हें अपने क्वार्टर तक जाना पड़ता है। इससे न केवल उन्हें व्यक्तिगत परेशानी होती है बल्कि ड्यूटी के दौरान चौकी छोड़कर जाना भी पड़ता है।

बार-बार बताने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि चौकी के शौचालय की खराब स्थिति और इससे हो रही परेशानी की जानकारी जिला अस्पताल प्रबंधन को दी जा चुकी है। इसके बावजूद न तो खराब शौचालय की मरम्मत कराई गई और न ही वैकल्पिक व्यवस्था की गई। कर्मचारियों का कहना है कि जब भी वे अपनी समस्या लेकर अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंचते हैं तो उन्हें नई अस्पताल बिल्डिंग में पुलिस चौकी के लिए कमरा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया जाता है।लेकिन यह आश्वासन अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया है।

चौकी की छत भी बनी परेशानी का कारण

सिर्फ शौचालय ही नहीं बरसात के दौरान चौकी की छत से पानी टपकने की समस्या भी कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। बारिश के समय चौकी के अंदर पानी आने से पुलिसकर्मियों को ड्यूटी करने में दिक्कत होती है। ऐसे में एक ओर जहां पुलिसकर्मी अस्पताल परिसर की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें चौकी में बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है।

जिम्मेदारों की अनदेखी पर सवाल

जिला अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी का होना सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां तैनात पुलिसकर्मी अस्पताल में होने वाली घटनाओं, विवादों और अन्य पुलिस संबंधी मामलों में तत्काल कार्रवाई करते हैं। इसके बावजूद चौकी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव और लंबे समय से शौचालय की खराब स्थिति जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है।

शौचालय की तत्काल मरम्मत की जाए

पुलिस कर्मचारियों ने मांग की है कि चौकी के खराब शौचालय की तत्काल मरम्मत कराई जाए, बरसात के दौरान छत से पानी टपकने की समस्या दूर की जाए और नई अस्पताल बिल्डिंग में पुलिस चौकी के लिए प्रस्तावित कक्ष शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। इससे रात्रि ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भी सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।

नाम सुधार सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम आदित्य राणा है जो कि त्रुटिवश मेरी एल.आई.सी. पालिसी में मेरा नाम प्रहलाद दर्ज हो गया है, आदित्य राणा और और प्रहलाद दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः मुझे मेरे नाम आदित्य राणा पिता राजेन्द्र राणा, ग्राम मंगराटोला (परतापुर) पोस्ट घुनाड़ी, थाना लामता, तह. लामता, जिला बालाघाट के नाम से ही जाना पहचाना जाये।

वास्ते सूचनार्थ
आदित्य राणा

बारबेड वायर (कांटेदार तार)
एवं चेन लिंक जाली
उचित दाम पर उपलब्ध
लघु उद्योग निगम भोपाल से संबद्ध
निर्माता
तिरूपति इंजीनियरिंग वर्क्स
मयूर टॉकिज के सामने हनुमान चौक, बालाघाट
फोन:- 07632-243531
मो:- 8989976858, 9425139998

न्यूज गैलरी

50 साल पुराने कुएं से निकल रहा गर्म पानी, गांव में मचा कौतूहल,

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जनपद पंचायत किरनापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत ग्राम नेवरगांव कला में करीब 50 वर्ष पुराने कुएं से पिछले 10 दिनों से गर्म पानी निकलने की जानकारी सामने आई है। अचानक पानी

गर्म आने की खबर फैलने के बाद गांव में कौतूहल का माहौल है और आसपास के लोग भी इस कुएं को देखने पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत नवेगांव कला के वार्ड क्रमांक 12 निवासी मुरलीधर कुतराहे पिता नोहरलाल कुतराहे के घर स्थित करीब 50 वर्ष पुराने कुएं से पिछले लगभग 10 दिनों से गर्म पानी निकल रहा है। लंबे समय से सामान्य पानी देने वाले इस कुएं से अचानक गर्म पानी आने की जानकारी ग्रामीणों के लिए हैरानी का विषय बनी हुई है। इस मामले में ग्राम पंचायत नेवरगांव कला के सचिव विकेश बावनकर से दूरभाष पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि उन्हें कुएं से गर्म पानी निकलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद उन्होंने स्वयं मौके पर पहुंचकर कुएं और पानी की स्थिति देखी। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पानी का सैंपल जांच के लिए पीएचसी भेजा गया। पंचायत सचिव के अनुसार पानी की जांच में फिलहाल इसे पीने योग्य बताया गया है। हालांकि पानी गर्म आने के पीछे क्या कारण है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कुएं के पानी का तापमान सामान्य से अधिक क्यों हो गया है, इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर आगे जांच की आवश्यकता है। गांव में जैसे ही कुएं से गर्म पानी निकलने की जानकारी फैली, आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचने लगे। ग्रामीणों के बीच यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग कुएं का पानी देखकर इसकी वजह जानने को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं। पंचायत सचिव ने बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी जनपद पंचायत किरनापुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी दी गई है। अब प्रशासन की ओर से मामले में आगे क्या जांच कराई जाती है और पानी के गर्म होने का वास्तविक कारण क्या सामने आता है, यह देखना होगा। फिलहाल पानी की जांच में उसके पीने योग्य होने की जानकारी सामने आने के बावजूद कुएं से अचानक गर्म पानी निकलना ग्रामीणों के लिए रहस्य बना हुआ है। प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि पानी गर्म होने के पीछे प्राकृतिक कारण है या कोई अन्य वजह।

अब खुले में कचरा फेंकने वालों तक पहुच रही नपा.की टीम, कचरे से पहचान कर दुकानों में जाकर काटे जा रहे चालान

शहर के बाहर खाली प्लाटों और डेंजर रोड पर मिले दुकानों के कचरे से खुल रही पोल

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

शहर को साफ रखने के लिए नगर पालिका बालाघाट ने अब कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का तरीका बदल दिया है। नगर पालिका की टीम अब केवल मकान, दुकान या निजी प्रतिष्ठान के सामने गंदगी मिलने पर ही चालान नहीं काट रही, बल्कि शहर के बाहर खाली प्लाटों, डेंजर रोड सहित अन्य खुले स्थानों पर फेंके गए कचरे की पहचान कर संबंधित दुकानदार और प्रतिष्ठान तक पहुंच रही है। कचरे में मिले रैपर, बिल, कंपनी के नाम वाली सामग्री और अन्य पहचान के आधार पर संबंधित दुकान और शोरूम का पता लगाया जा रहा है और फिर नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंचकर चालान की कार्रवाई कर रही है। पहले कई लोग रात के समय और मौका देखकर दुकानों और शोरूम का कचरा शहर के बाहरी हिस्सों में फेंक देते थे, लेकिन अब नगर पालिका की टीम उसी कचरे में मौजूद पहचान के माध्यम से संबंधित प्रतिष्ठान तक पहुंच रही है। इसी क्रम में नगर पालिका बालाघाट ने शहर के दो प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की है। नगर पालिका की टीम को एक स्थान पर साइन बजाज एजेंसी से संबंधित कचरा मिला। कचरे में एजेंसी की पहचान होने के बाद नगर पालिका कर्मचारी संबंधित एजेंसी पहुंचे और वहां 3 हजार रुपए का चालान काटने की कार्रवाई की। इसी तरह एक पार्सल कंपनी के नाम और पहचान वाली बोरियां एवं अन्य कचरा शहर के अलग-अलग हिस्सों में मिलने के बाद नगर पालिका की टीम पार्सल कंपनी के शोरूम तक पहुंची और 2 हजार रुपए का चालान बनाया।

गोंदिया रोड स्थित हनुमान चौक के आगे संचालित पार्सल कंपनी का मामला नगर पालिका की कार्रवाई के दौरान काफी चर्चा में रहा। बताया गया कि कंपनी के

कर्मचारियों द्वारा पार्सल में इस्तेमाल होने वाली लेवल लगी बोरियों को करीब एक महीने से शहर के अलग-अलग हिस्सों और खाली स्थानों पर फेंका जा रहा था। इन बोरियों के हवा में उड़कर सड़क तक पहुंचने और जगह-जगह जमा होने की शिकायतें भी नगर पालिका को मिल रही थीं। शिकायत के बाद नगर पालिका की टीम ने ऐसे स्थानों का निरीक्षण किया और वहां मिले कचरे में पार्सल कंपनी से संबंधित पहचान सामने आने के बाद टीम सीधे कंपनी के शोरूम पहुंच गई। नगर पालिका ने कंपनी पर 2 हजार रुपए का चालान बनाया, लेकिन शुरुआत में कंपनी के कर्मचारियों ने चालान की राशि जमा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारियों तथा कंपनी के कर्मचारियों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। मामला करीब दो से तीन घंटे तक चलता रहा और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि नगर पालिका अमले ने शोरूम को सील करने की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान नगर पालिका द्वारा कंपनी के दस्तावेज और ट्रेड लाइसेंस की भी जानकारी ली गई। जांच में ट्रेड लाइसेंस से संबंधित कमी सामने आने के बाद नगर पालिका की कार्रवाई और गंभीर हो गई। करीब दो से तीन घंटे की बातचीत और कार्रवाई के बाद आखिरकार पार्सल कंपनी के कर्मचारियों ने ऑनलाइन माध्यम से 2 हजार रुपए का चालान जमा कराया। चालान की राशि जमा होने की पुष्टि के बाद तत्काल विवाद समाप्त हुआ। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के दौरान गोंदिया रोड पर नगर पालिका और कंपनी के बीच चल रही बातचीत लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। नगर पालिका कर्मचारियों का कहना है कि शहर में कचरा फैलाने वालों के खिलाफ अब केवल मौके पर गंदगी मिलने के आधार पर ही कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रतिष्ठान का कचरा शहर के किसी खुले स्थान पर मिलता है और उसमें संबंधित दुकान, एजेंसी या कंपनी की पहचान होती है तो उस प्रतिष्ठान तक पहुंचकर चालान की कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका शहर से निकलने वाले कचरे को नियमित रूप से उठाकर निर्धारित ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाती है। इसके बावजूद यदि दुकानदार या प्रतिष्ठान अपना कचरा खुले मैदान, खाली प्लाट या सड़क किनारे फेंकते हैं तो इससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। हवा के साथ कचरा वापस सड़कों और रहवासी क्षेत्रों तक पहुंच जाता है, जिससे गंदगी के साथ पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी पैदा होती है। नगर पालिका की इस कार्रवाई से अब व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए भी स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि दुकान और शोरूम का कचरा शहर के बाहर फेंककर जिम्मेदारी से बचना आसान नहीं होगा। कचरे में मौजूद किसी भी तरह की पहचान संबंधित प्रतिष्ठान तक नगर पालिका को पहुंचा सकती है। नगर पालिका अधिकारियों का कहना है कि शहर को साफ रखना केवल नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है। दुकानदारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और नागरिकों को भी अपने स्तर पर कचरे का उचित निपटान करना होगा। खुले में कचरा फेंकने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई और तेज की जा सकती है। साइन बजाज एजेंसी पर 3 हजार रुपए और पार्सल कंपनी पर 2 हजार रुपए की कार्रवाई के बाद अब नगर पालिका की निगाह शहर के बाहर कचरा फेंकने वाले अन्य प्रतिष्ठानों पर भी बनी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में कचरे से पहचान कर और कितने दुकानदारों या कंपनियों तक नगर पालिका की टीम पहुंचती है, यह देखने वाली बात होगी।

छात्रवृत्ति के भरोसे कर रहे पढ़ाई, ढेड़ वर्षो से विघार्थियों को नही मिली छात्रवृत्ति

एलएलबी के विघार्थियों में मचाया हंगामा, पीजी कॉलेज का प्रवेश द्वार बंद कर किया प्रदर्शन, 15 हजार रुपए की द्वितीय वर्ष की फीस जमा करने में आर्थिक परेशानी, 10 दिन में छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले के अग्रणी शासकीय पीजी कॉलेज में एलएलबी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को करीब डेढ़ साल से छात्रवृत्ति नहीं मिलने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। छात्रवृत्ति की राशि लंबित होने से नाराज लॉ विद्यार्थियों ने शुक्रवार को कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार को सांकेतिक रूप से बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का कहना है कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और अब एलएलबी द्वितीय वर्ष की करीब 15 हजार रुपए की फीस जमा करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है।छात्रवृत्ति ना मिलने पर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने अपना आक्रोश जताते हुए कॉलेज प्रबंधन को 10 दिनों के अल्टीमेटम के साथ एक ज्ञापन सौपा है। जिसमें उन्होंने समय सीमा के भीतर छात्रवृत्ति न मिलने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है।

छात्रवृत्ति आने तक फीस नहीं भरने का लिया फैसला

उधर प्रदर्शनकारी लॉ के विघार्थियों ने अपना आक्रोश जताते हुए स्पष्ट किया कि जब तक लंबित छात्रवृत्ति की राशि उनके खातों में नहीं पहुंचती, तब तक वे द्वितीय वर्ष की फीस जमा नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के अनुसार, छात्रवृत्ति की समस्या को लेकर प्राध्यापकों से चर्चा की गई, जिस पर उन्हें आश्वस्त किया गया है कि छात्रवृत्ति आने तक फीस जमा नहीं करने पर भी विद्यार्थियों को परेशानी नहीं होगी। इसी आश्वासन के बाद विद्यार्थियों ने अपना सांकेतिक आंदोलन समाप्त कर दिया।

छात्रवृत्ति की वेबसाइट में दिख रहा चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का उल्लेख- ऋषभ

लॉ विघार्थियों ने विश्वविद्यालय व महाविद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डेढ़ साल बीत जाने के बावजूद लॉ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी है। वहीं छात्रवृत्ति की वेबसाइट में चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का उल्लेख दिखाई दे रहा है, जिसे उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर की गंभीर तकनीकी एवं प्रशासनिक त्रुटि बताया।बताया गया कि छात्रवृत्ति की समस्या से महाविद्यालय प्राचार्य एवं संबंधित आयुक्त को अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस निराकरण नहीं किया गया है। इससे साफ है कि विद्यार्थियों की इस गंभीर समस्या को लेकर महाविद्यालय प्रबंधन गंभीर नहीं है।

विद्यार्थियों पर पड़ रहा आर्थिक बोझ- आशुतोष

विरोध प्रदर्शन कर रहे एलएलबी प्रथम वर्ष के छात्र आशुतोष ने बताया कि लॉ की पढ़ाई करने वाले अधिकांश पात्र विद्यार्थी गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं। ऐसे में डेढ़ साल से छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति के अभाव में द्वितीय वर्ष की फीस जमा करने के लिए विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

10 दिन में निराकरण नहीं,हुआ तो होगा उग्र प्रदर्शन-ऋषभ

छात्रवृत्ति की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी विघार्थियों का नेतृत्व कर रहे विधायक प्रतिनिधि ऋषभ सहारे ने बताया कि छात्रवृत्ति की इस मांग को लेकर सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन कर 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है।यदि आगामी 10 दिनों के भीतर लॉ विद्यार्थियों की लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया तो कॉलेज के अन्य विद्यार्थियों को साथ लेकर बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। लॉ छात्रों के प्रदर्शन के बाद अब नजर इस बात पर टिकी है कि लंबे समय से लंबित छात्रवृत्ति की समस्या का निराकरण कब तक किया जाता है।

जंतर-मंतर की कार्रवाई के खिलाफ बालाघाट में कांग्रेस का प्रदर्शन

घायल छात्र साहिल लोचव को न्याय दिलाने की मांग, पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने कांग्रेस ने उठाई आवाज

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित रूप से पेलेट गन और लाठी-डंडों से की गई कार्रवाई के विरोध में बालाघाट शहर कांग्रेस कमेटी ने धरना-प्रदर्शन किया। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित प्रदर्शन में घायल छात्र साहिल लोचव को न्याय दिलाने और कार्रवाई के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के

खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई गई। धरने को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर इस तरह की पुलिस कार्रवाई लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर प्रहार है। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई में साहिल लोचव गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनकी एक आंख की रोशनी जाने का खतरा बताया जा रहा है। इसके बावजूद घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचने पर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना गंभीर चिंता का विषय है। श्याम पंजवानी ने कहा कि पूरे मामले में जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस घटनाक्रम को लेकर जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ऐसे में यदि पुलिस कार्रवाई के लिए केंद्रीय स्तर से कोई निर्देश दिए गए थे तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और यदि बिना किसी निर्देश के कार्रवाई की गई तो संबंधित पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग भी की। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। पंजवानी ने कहा कि सरकार एक ओर लोकतंत्र और संविधान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पेलेट गन और लाठी-डंडों का इस्तेमाल किया जाता है। यह सरकार की कथनी और करनी के बीच अंतर को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पीड़ित छात्र की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना भी अपने आप में गंभीर विषय है। कांग्रेस का कहना है कि घायल छात्र को न्याय मिलना चाहिए और पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। श्याम पंजवानी ने कहा कि जब तक साहिल लोचव को न्याय नहीं मिलता और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक कांग्रेस का लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे संघर्ष के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश और देशभर में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जिला संगठन मंत्री शफकत खान ने कहा कि यह लड़ाई केवल साहिल लोचव को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के शांतिपूर्ण प्रदर्शन और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है और जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक संघर्ष जारी रखा जाएगा।उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवा, किसान और आम जनमानस सरकार की नीतियों से परेशान हैं और आने वाले समय में जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पर संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ जनआंदोलन खड़ा करने में कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाएंगे। धरना-प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साहिल लोचव को न्याय दिलाने, दोषी पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शन में श्याम पंजवानी, शफकत खान, कारो लिल्हारे, जीतू बर्वे, राजेश ठाकुर, अफरोज खान, राहुल बेस, मयूर मोटवानी, प्रवीण मदनकर, श्रीकृष्णा डींगरू, अल्लाह रखा, फिरोज खान, प्रकाश पप्पू मदनकर, साबिर मंसूरी, कपिल बर्वे, अनिल बनोटे, पन्ना शर्मा, शोएब अली, राकेश रामटेक, डॉ. मुकेश वरकडे, सुरेश बरमाते, धर्मेंद्र बोपाचे, रिजवान खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

झोलाछाप डॉक्टर और पंडा के इलाज के बाद 6 वर्षीय मासूम की मौत

मर्ग जांच के बाद अज्ञात झोलाछाप के खिलाफ मामला दर्ज

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। बिरसा थाना क्षेत्र की मछुरदा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम लालपुर में झोलाछाप डॉक्टर एवं पंडा द्वारा किए गए कथित लापरवाहीपूर्ण इलाज के बाद 6 वर्षीय मासूम की मौत का मामला सामने आया है। मर्ग जांच के बाद बिरसा पुलिस ने बिना किसी वैध चिकित्सकीय डिग्री के इलाज करने और लापरवाही बरतने के आरोप में ग्राम खैरटोला निवासी अज्ञात झोलाछाप पंडा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम लालपुर निवासी कुंवर सिंह धुर्वे का छह वर्षीय पुत्र राहुल धुर्वे पिछले चार पांच दिनों से बीमार था। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की टीम को मिलने के बाद 17 अगस्त को बिरसा खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. निमिश गौतम के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इसी बीच उपचार के दौरान 19 अगस्त को राहुल की मौत हो गई।राहुल के शव का बिरसा में पोस्टमार्टम कराया गया।जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। मर्ग जांच के दौरान पुलिस के समक्ष यह बात सामने आई कि ग्राम खैरटोला के एक झोलाछाप व्यक्ति जो पंडा के रूप में भी इलाज करता था है।जिसके द्वारा बिना किसी वैध चिकित्सकीय डिग्री के राहुल का इलाज किया जा रहा था। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया इलाज में लापरवाही एवं अपेक्षित सावधानी नहीं बरते जाने की बात सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अपराध दर्ज किया गया है।

क्षेत्र में बीमारी का प्रकोपबच्चों को जिला अस्पताल लाया जा रहा

बिरसा विकासखंड के कई गांवों में इन दिनोंबीमारी का प्रकोप बना हुआ है। बीमार बच्चों को उपचार के लिए जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती कराया जा रहा है। वही दो दर्जन बच्चों की मौत हो गई। ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता के इलाज करने वाले झोलाछापों की सक्रियता चिंता का विषय बनी हुई है।स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और जागरूकता के अभाव में कई परिवार बीमारी की स्थिति में नीम-हकीम और झोलाछापों के भरोसे चले जाते हैं। राहुल की मौत की घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अवैध उपचार पर प्रभावी कार्रवाई और लोगों को समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत को उजागर किया है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल का 22 अगस्त को बालाघाट आगमन

बिरसा विकासखंड के बीमारी से प्रभावित ग्रामों का करेंगे भ्रमण

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल का 22 अगस्त को बालाघाट आगमन हो रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल 22 अगस्त प्रातः 07 बजे जबलपुर से बैहर के लिए प्रस्थान करेंगे और सुबह 10:15 बजे बैहर पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल 10:30 बजे बैहर से मछुरदा के लिए प्रस्थान करेंगे तथा 11:40 बजे मछुरदा पहुंचेंगे तथा 11:55 बजे मछुरदा से कुंडेकसा के लिए प्रस्थान करेंगे तथा 12:15 बजे कुंडेकसा पहुंचेंगे। 12:45 बजे कुंडेकसा से मलाजखंड तथा 2:30 बजे मलाजखंड से जबलपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल शाम 6:30 बजे जबलपुर पहुँच शाम 07 बजे रीवा के लिए प्रस्थान करेंगे।

यात्री बस और कार की आमने-सामने भिड़ंत, 5 युवक घायल, 3 की हालत गंभीर

लालबर्रा-सिवनी मार्ग पर कंजई मोड़ाई घाट के पास घटी घटना, बालाघाट से पचमढ़ी जा रहे थे कार सवार युवक

रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। लालबर्रा।

लालबर्रा-सिवनी मार्ग स्थित कंजई मोड़ाई के पास शुक्रवार दोपहर करीब 3.30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सिवनी की ओर से आ रही अनियंत्रित यात्री बस ने लालबर्रा की तरफ से आ रही कार को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी तेज थी कि बस कार को लगभग 10 फीट तक पीछे घसीटते हुए ले गई। हादसे में कार सवार सभी 5 युवक घायल हो गये, जिनमें से 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जिनका लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक उपचार कर सभी घायलों को बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रिफर किया गया है।

पचमढ़ी भ्रमण पर जा रहे थे युवक

प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट निवासी राहुल बरेले अपने साथी अनीस सिंह, लोकेश कुर्वे, हिमांशु, आशीष हनवत के साथ शुक्रवार को दोपहर में कार से पचमढ़ी घूमने के लिए निकले थे। जैसे ही उनकी कार कंजई के आगे स्थित घाट मोड़ाई के समीप पहुंची, तभी सामने (सिवनी की ओर) से आ रही निजी यात्री बस के चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए कार को सामने से टक्कर मार दी। जिससे कार में सवार युवक घायल हो गये। वहीं यात्री बस की टक्कर से कार का सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रगस्त हो चुका है। घटना के बाद चीख-पुकार सुनकर मार्ग से गुजर लोग एकत्रित हुए और पुलिस को घटना की जानकारी दिये। जिसके बाद कड़ी मशक्कत कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया और सभी घायलों को लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाकर भर्ती किया गया जहां सभी का प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रिफर किया गया। इस दुर्घटना में बस का सामने का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि बस में सवार सभी यात्री बाल-बाल बच गये। वहीं यह सड़क हादसा मोड़ाई में घटित हुआ है, जिस ओर से कार गुजर रही थी उस साइड में गहरी खाई है। अगर बस के टक्कर होने के बाद अगर कार अनियंत्रित होकर पलट कर खाई में जाती तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके में पहुंची और बस एवं कार सड़क के बीच में फंस जाने से यातायात बाधित हो गया था, जिसे पुलिस ने बहाल करवाया, जिसके बाद आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो गया। वहीं दुर्घटनाकारित बस में सवार यात्रीगणों को दुसरे बस से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

जांच कर की जायेगी वैधानिक कार्यवाही - राजमल

थाना प्रभारी राजमल दायमा ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर में सूचना मिली थी कि कंजई के आगे यात्री बस एवं कार में भिड़त हो गई है और कार में सवार युवक घायल हो गये है। जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पहुंचकर कार में सवार 5 युवकों को लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाकर भर्ती किया। जहां चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार कर उन्हे बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय फिर किया है। श्री दायमा ने बताया कि बस में सवार यात्रीगण दुसरी बस में अपने गंतव्य तक पहुंच गये है एवं पीड़ितों की शिकायतों के आधार में मामले की जांच कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

क्षेत्र के विकास में बाधक बने जिला पंचायत सीईओं श्री सराफ का हुआ स्थानांतरण, अब विकास कार्यों को मिलेगी गति - डुलेन्द्र

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। जिले के ग्रामीण अंचलों में पंचायती राज के तहत होने वाले विकास कार्यों में बाधक को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान के बीच जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अभिषेक सराफ का शासन द्वारा स्थानांतरण कर दिया गया है। उनके तबादले की खबर आते ही जिला पंचायत सहित पंचायत प्रतिनिधियों ने राहत की सांस ली है। जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति डुलेन्द्र ठाकरे ने सीईओं के स्थानांतरण पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के हित में लिया गया एक सकारात्मक कदम बताया है।

जिला पंचायत सभापति डुलेन्द्र ठाकरे ने विज्ञप्ति जारी कर अपने वक्ताओं में पूर्व सीईओं अभिषेक सराफ के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किये है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिषेक सराफ द्वारा जानबूझकर पंचायती राज के विकास कार्यों में बाधा पहुंचाई जा रही थी। श्री ठाकरे ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा जनहित में लाये गये ऐसे कई प्रस्ताव, जो शासन के सभी नियमों, तकनीकी मापदंडों और योग्यताओं को पूरी तरह से पूर्ण करते थे, उन्हें भी स्वीकृति नहीं दी जाती थी। सीईओ के इस असहयोगात्मक और अड़ियल रवैये के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य महीनों से लंबित पड़े थे। अधिकारी की इस कार्यशैली से न केवल चुने हुए जनप्रतिनिधियों में भारी निराशा और आक्रोश था, बल्कि आम जनता को भी विकास से वंचित रहना पड़ रहा था। श्री ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभिषेक सराफ जिले के विकास में एक बड़े बाधक के रूप में काम कर रहे थे। अब उनके स्थानांतरण के बाद पंचायत प्रतिनिधियों में एक नई उम्मीद जगी है। श्री ठाकरे ने विश्वास जताया है कि इस बदलाव के बाद पंचायती राज संस्थाओं के रूके हुए कार्यों की फाइलों को जल्द मंजूरी मिलेगी। नये अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में विकास कार्य में गति आयेगी और ग्रामीण विकास को एक नई गति प्राप्त होगी।

सात गांवों से एक साथ निकलेगी कांवड़ यात्रा 23 को

पद्मेश न्यूज। बेहरई/लालबर्रा। जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कनकी, बेहरई, मांझापुर, छतेरा, लवादा, चंदपुरी, गर्रा से एक साथ बोल बम सेवा समिति के तत्वाधान में 23 अगस्त को भव्य कांवड़ यात्रा निकलेगी। चर्चा में बोल बम सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सावन माह के पावन अवसर पर 23 अगस्त को सात ग्राम कनकी, बेहरई, मांझापुर, छतेरा, लवादा, चंदपुरी व गर्रा से एक साथ भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जायेगी। यह कांवड़ यात्रा अपने-अपने गांव से निकल कर वैनगंगा नदी से जल लेकर एक साथ पैदल यात्रा एवं भजन करते हुए और बोल बम नारे लगाते हुए डीजे के साथ लांजी कोटेश्वर महादेव धाम के लिए प्रस्थान करेगी। आगे बताया कि 24 अगस्त को सभी कांवड़ियें लांजी स्थित कोटेश्वर धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे और भगवान भोलेनाथ से सुख समृध्दि का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वहीं कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले सभी कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो सके। इसके लिए आयोजन समिति के द्वारा समय-समय पर पानी एवं फलाहार के लिए जगह-जगह पर स्टाल लगाये जायेगें। इस अवसर पर क्षेत्रीय श्रध्दालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील बोल बम सेवा समिति के पदाधिकारियों ने की है।

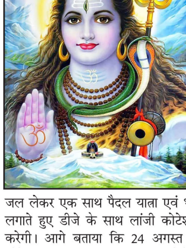

जाम और पांढरवानी में धूमधाम से निकली कलश वंदन यात्रा

संत रविदास महाराज की 650 वीं जयंती पर विभिन्न ग्रामों में हो रहे विविध कार्यक्रम

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। संत शिरोमणि श्री संत रविदास महाराज जी की 650 वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 20 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक कलश वंदन यात्रा एवं समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 21 अगस्त को लालबर्रा विकासखंड के ग्राम जाम में दोपहर 1 बजे और लालबर्रा के पांढरवानी (वार्ड नंबर 18) स्थित रविदास मंदिर के पास दोपहर दोपहर 3.30 बजे भव्य कलश वंदन यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सामाजिक महिलाओं ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर पूजित कलश धारण कर पैदल यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान समुचा माहौल 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' और संत रविदास महाराज जी के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में समरसता, एकता और संत रविदास जी के लोककल्याणकारी विचारों का प्रसार करना है।

संत रविदास जी के बताये मार्ग पर चलने का किया गया आव्हान

वहीं मंचीय कार्यक्रम जाम एवं पांढरवानी के रविदास मंदिर में संपन्न हुई। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा संत रविदासजी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्र'वलित कर माल्यार्पण कर उन्हे नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सभापति झामसिंह नागेश्वर ने कहा कि संत रविदास जी ने समाज से छुआछूत और भेदभाव को मिटाकर भाईचारे का संदेश दिया। जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 20 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक कलश वंदन यात्रा एवं समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान संत जी के समरस समाज के सपने को साकार करने की एक अनुठी पहल है। वहीं कार्यक्रम को पांढरवानी सरपंच अनीस खान, जाम सरपंच सुरेंद्र बलोने, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रसन्न अवधिया और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरिता माते ने भी विचार व्यक्त करते हुए संत रविदास जी के जीवन चरित, उनकी भक्ति भावना और सामाजिक सरोकारों पर प्रकाश डालते हुए सभी से उनके बताये मार्ग पर चलने का आव्हान किया। इस अवसर पर रविदास समाज ब्लॉक अध्यक्ष दीपक चौधरी, ब्लॉक सचिव कमलेश खरोले, देवराज ठकरेले, अयूब भारती, संजीव अवधिया, वेदसिंह ठाकुर, नरेंद्र तरवरे, रमेश झाड़ेकर, नरेंद्र तरवरे, गेंदलाल तरवरे, सोहनलाल छिपे, केशव महोबे, अशोक महोबे, मंडल संयोजक श्री वासनिक, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी घनश्याम भालेकर, खंड पंचायत अधिकारी चंदनसिंह मर्सकोले, छात्रावास अधीक्षक टीसी टांडेकर, छात्रावास अधीक्षिका सविता ठक्कर, रीता पांचे सहित स्वजातीय बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

पांढरवानी सरपंच एवं पंचायतकर्मियों ने कलश वंदन यात्रा का किया स्वागत

ग्राम जाम का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद कलश वंदन यात्रा नगर मुख्यालय पहुंची। इस दौरान लालबर्रा थाने के समीप स्थित मेडिकल के सामने ग्राम पंचायत पांढरवानी सरपंच अनीस खान एवं पंचायतकर्मियों के द्वारा कलश वंदन यात्रा का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पांढरवानी सरपंच अनीस खान ने कहा कि समरसता संकल्प अभियान के तहत निकाली जा रही और 20 अगस्त से चल रही यह यात्रा संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज के विचारों और संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने का सराहनीय प्रयास है। साथ ही यह भी कहा कि ग्रामीणों एवं सामाजिक स्तर पर लोगों ने ग्राम पंचायत में संत रविदास जी के मंदिर/चबूतरा निर्माण के लिए आवेदन दिया था, इसे पंचायत द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया। श्री खान ने कहा कि यहां संत रविदास जी की प्रतिमा स्थापित की जायेगी तथा मंदिर व सभा मंच का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आने वाले समय में संत रविदास जी की जयंती सामाजिक स्तर पर सभी लोगों के साथ मिलकर धूमधाम से मनाई जायेगी। समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। इस अवसर पर सरपंच अनीस खान सहित पंचायतकर्मी उपस्थित रहे।

महाविद्यालय में "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत किया गया वृक्षारोपण

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा में शुक्रवार को "एक पेड माँ के नाम"अभियान अन्तर्गत महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉ. संगीता मेश्राम के निर्देशन में महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में आम, अमरूद व लीची के पौधो का रोपण किया गया। "एक पेड़ माँ के नाम" भारत सरकार का जन सहयोग एवं सामुदायिक सहयोग से पूर्ण होने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान जिसका शुभारंभ वर्ष 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को एक पौधा रोपित कर किया गया। जैव विविधता के समर्थन में देशी प्रजातियों के वृक्षों को ही पौधा रोपित करते समय प्राथमिकता दी गई है। "एक पेड़ माँ के नाम" पौधा रोपण कार्यक्रम में पौधारोपण के साथ ही वायुदूत मोबाईल ऐप पर फोटो अपलोड किया जाना है। "एक पेड़ माँ के नाम" वृक्षारोपण अभियान की संयोजक डॉ. कामाक्षा बिसेन एवं सहसंयोजक डॉ. आशा कारे है। उक्त वृक्षारोपण अभियान में पौधा रोपित करने में महाविद्यालय के प्राध्यापक सुमन बरवा, डॉ. सुरेन्द्र कुमार खण्डायत, डॉ. प्रदीपकुमार भिमटे, डॉ. निर्मल कीर्ति गेडाम, डॉ. देवराज चौरे, नरेश सौलखे, श्रीमती संध्या भलावे, श्रीमती भूमेश्वरी ठाकरे, मनीष शिवहरे, श्रीमती अनिभा शरणागत, पीतम मुरते, यादोराव राजुरकर, व्यंकटरमन नगपुरे, श्रीमती सरिता एड़े, रामदयाल मथारे, लकेश गेडाम, श्रीमति वंदना कुर्वे, मिनेश पंचेश्वर, निशांत तलवरे, प्रसिक हुमनेकर एवं विद्यार्थियों का सराहनीय योगदान रहा।

लालबर्रा कालेज में प्रवेश नवीनीकरण एवं त्रुटिपूर्ण डेटा संशोधन की प्रक्रिया 31 तक

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय स्थित शासकीय महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश नवीनीकरण के प्रक्रिया प्रारंभ है। पात्र विद्यार्थी प्रवेश नवीनीकरण की विभागीय ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से अपने नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करे तथा विस्तृत जानकारी हेतु महाविद्यालय के हेल्प डेस्क से भी सम्पर्क कर सकते है। चर्चा में महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्या ने बताया कि शासन द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नवीनीकरण की समय सीमा में वृध्दि करते हुए अब अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। उक्त तिथि तक अनिवार्य रूप से अपना नवीनीकरण करवायें। आगे बताया कि ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया 2026-27 के अन्तर्गत महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को अवगत हो की जो विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके है तथा किन्हीं करणवश प्रवेश निरस्त करना चाहते है वे अपना प्रवेश निरस्त कर प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते है। साथ ही जो भी विद्यार्थी अपने विषय में परिवर्तन, पाठ्यक्रम में परिवर्तन, संकाय में परिवर्तन एवं प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु महाविद्यालय स्थानांतरण की प्रक्रिया तथा प्रवेशित विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन की प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करे। जिससे की विद्यार्थी के उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए बेहतर स्थिति निर्मित हो सके।

नदीटोला स्कूल भवन डिस्मेंटल, नवीन भवन की स्वीकृति अधर में

एक ही हॉल में चल रहीं ५ कक्षाएं विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुदबुदा के नदीटोला स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में इन दिनों प्रशासनिक उपेक्षा और बदहाली का शिकार है। पुराने और जर्जर भवन को डिस्मेंटल किए जाने के बाद से ही स्कूल का संचालन परिसर में बने एक ही अतिरिक्त कक्ष में किया जा रहा है। नवीन भवन की स्वीकृति नही मिलने के कारण कक्षा १ से ५वीं तक के छात्र छात्राएं एक ही कमरे में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं।

एक कमरे में ३३ बच्चे और ३ शिक्षक

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य बस्ती से करीब ४ किलोमीटर दूर नदी के दूसरे छोर पर बसे नदी टोला में प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। वर्ष २०२५ में शिक्षा विभाग के द्वारा कराए गए निरीक्षण में स्कूल भवन को जर्जर पाते हुए डिस्मेंटल करने की रिपोर्ट दी गई थी। इसके बाद २१ अगस्त से भवन को गिराने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन नए भवन का निर्माण तो दूर अब तक शासन से इसकी स्वीकृति भी नहीं मिल पाई है। वर्तमान सत्र २०२५ और २०२६ में दर्ज ३३ विद्यार्थियों को ३ शिक्षकों के द्वारा एक ही हॉल में एक साथ पढ़ाया जा रहा है जिससे अध्यापन कार्य में भारी अव्यवस्था हो रही है। एक ही जगह पर अलग.अलग कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई होने से ना केवल एकाग्रता प्रभावित हो रही है, बल्कि विद्यार्थियों के रिजल्ट पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। इस अव्यवस्था से परेशान होकर कई अभिभावकों ने अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में करा दिया है। हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार आज भी बच्चों को इसी अव्यवस्थित वातावरण में भेजने को विवश हैं। यदि समय रहते पुराने भवन का उचित रखरखाव और मरम्मत की जाती तो वह कुछ और वर्षों तक उपयोग में आ सकता था। वर्तमान में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और प्रशासनिक ढिलाई के कारण बच्चों का शैक्षणिक भविष्य खतरे में है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि नदी टोला में जल्द से जल्द नवीन भवन की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए।

भवन नही होने से बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित- कमलसिंह पटले

ग्रामीण कमल सिंह पटले ने बताया कि नदीटोला स्कूल की स्थिति जर्जर हो गई है एक हाल में सभी बच्चे बैठाल कर पढ़ाई करवाई जा रही है। स्कूल भवन यहां पर है नहीं आगे भवन बने तो अच्छा होगा वरना बहुत समस्या होने वाली है। ग्राम के कुछ लोग तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं फिर भी कुछ बच्चे यहां पढ़ने आते हैं। हम यही चाहते हैं कि अच्छे से स्कूल भवन बन जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई गुणवत्ता पूर्वक हो सके।

शिक्षा विभाग की लापरवाही का दंश झेल रहे बच्चे- उमेन्द्र जमरे

उपसरपंच उमेन्द्र जमरे ने बताया कि कक्षा १ से ५ वीं तक की प्राथमिक स्कूल हमारे यहां है उसके भवन की दीवार मजबूत है यदि मरम्मत करते तो आगे और चल जाता। किंतु मरम्मत की जगह डिस्मेंटल कर दिया गया है तोड़ना आज से चालू हुआ है। पांच कक्षा एक कमरे में तीन शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई जा रही है एक तरफ पढाई तो दूसरी तरफ हल्ला होता है। इन्होंने पहले भवन स्वीकृत कर डिस्मेंटल करना था तो स्कूल भवन बनने की आस लगी रहती। यहां पर गरीब और सभी स्तर के बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल अच्छा है परंतु भवन से विद्यार्थियों के प्रवेश कम हो रहे हैं। पढ़ाई अच्छी होती है परंतु शासन की यह व्यवस्था खराब है अब यथाशीघ्र भवन स्वीकृत किया जाए अन्यथा इसका प्रभाव विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम पर पड़ेगा।

भवन नही होने से सभी बच्चे एवं शिक्षक एक साथ पढ़ते पढ़ाते है-दिनेश भगत

प्रधान पाठक दिनेश भगत ने बताया कि वर्ष २०२५ में ही स्कूल भवन डिस्मेंटल कर दिया गया था तब से हम अतिरिक्त कक्ष में पांच कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। दिक्कत तो हो रही है सभी बच्चे एवं शिक्षक एक साथ पढ़ते पढ़ाते हैं नया भवन की अभी कोई जानकारी नहीं है। मरम्मत के लिए पहले भी हमने आवेदन अधिकारियों को किया था उन्होंने आकर देखा डिस्मेंटल कर दिया। यह दूसरा सत्र अतिरिक्त कक्ष में संचालित हो रहा है।

इनका कहना हैं

दूरभाष पर चर्चा में बताया कि विभागीय निरीक्षण में पीडब्लूडी की रिपोर्ट पर स्कूल भवन को डिस्मेंटल कर दिया गया है। हमारे द्वारा नवीन भवन की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है।

सतेन्द्र शरणागत
बीआरसी वारासिवनी

खेल मैदान ना होने के चलते परेशानियों से जूझ रहे सांदीपनि के विद्यार्थी

विधायक विवेक पटेल ने खैरलांजी सांदीपनि विद्यालय का औचक निरीक्षण किया

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। विधायक विवेक पटेल ने शुक्रवार को खैरलांजी सांदीपनि विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। विधायक विवेक पटेल स्कूल पहुंचते ही सीधे छात्र छात्राओं के क्लास रूप पहुंचे। जहां उन्होंने छात्र छात्राओं से सीधे संवाद किया और उनसे पढ़ाई में होने वाली परेशानी पूछी। जिसके बाद उन्होंने लगभग ३३ करोड़ रुपयों की लागत से बनी बिल्डिंग का निरीक्षण किया और अधूरे पड़े निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश संबंधित ठेकेदार को दिए। जिसके बाद उन्होंने विद्यालय परिसर में स्कूली छात्र.छात्राओं के साथ वृक्षारोपण किया। इस दौरान बीआरसी अनिल माहुले,सांदीपनि स्कूल के प्राचार्य शैलेंद्र सहारे,खैरलांजी सरपंच ज्योति नगपुरे,जिला पंचायत सदस्य सुनीता बहेटवार, राकेश वर्मा,अमित थोटे,विकास कृपगये, सोनिया नगपुरे,विक्की लिल्हारे,अजबसिंह कृपगये,पलाश बिसेन,दीपक पटले,अक्षय मस्करे,मानसिंह बहेटवार, टेकराम दमाहे,कैलाश सोनवाने मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान स्कूल के शौचालय में गंदगी देख और गंदा पानी दिखाई देने और जहां वहां बेवजह पड़े सामनों को देखकर विधायक विवेक पटेल ने प्राचार्य को तत्काल व्यवस्थित करने परिसर में साफ सफाई नियमित करने के निर्देश दिए। वहीं छात्र.छात्राओं के बैठक के लिए बैंच की कमी को देखते हुए ठेकेदार को जल्द बच्चों के बैठने के लिए बैंच उपलब्ध करवाने को कहा। स्कूल में अध्ययन ग्यारहवीं क्लास के छात्र.छात्राओं ने विधायक विवेक विक्की पटेल को अवगत कराया कि हमें ग्यारहवीं क्लास में भी अंग्रेजी की किताबें नहीं मिली और अब पास होकर बारहवीं क्लास में पहुंच गए। दो माह से अधिक हो गया और अभी तक अंग्रेजी माध्यम की बुक नहीं मिली है। जिससे हमें पढ़ाई करने काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विधायक पटेल ने जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा कर जल्द पुस्तके दिलवाने का आदेश दिया। ठेकेदार के द्वारा नवीन बिल्डिंग तो बना दी गई है मगर बच्चों के लिए खेल का मैदान अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। जिससे छात्र छात्राओं को ना ही खेल का सामान मिल रहा है और ना ही खलने खेल मैदान है। जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल रहा है। वहीं छात्र.छात्राओं ने विधायक विवेक पटेल से कहा कि अगर कोई स्कूली छात्र बेहोश हो जाता है तो शासकीय हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर समय पर उपस्थित नहीं रहते है।

वारासिवनी पुलिस थाने में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान आयोजित

आईजी ललित शाक्यवार ने नागरिकों से संवाद कर जानीं पुलिसिंग की जमीनी हकीकत

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी पुलिस थाना परिसर स्थित सभा कक्ष में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत एक विशेष संवाद कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बालाघाट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ललित शाक्यवार उपस्थित रहे। साथ ही सीएसपी मयंक तिवारी, एसडीओपी विवेक शर्मा, थाना प्रभारी अनूप कुमार उइके एवं क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिकों व व्यापारियों की गरिमामयी मौजूदगी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ आईजी ललित शाक्यवार के द्वारा थाना परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के साथ हुआ। तत्पश्चात सभा कक्ष में औपचारिक बैठक शुरू की गई जिसमें उपस्थित जनों के परिचय के बाद पुलिस और जनता के बीच व्यावहारिक एवं विस्तृत चर्चा संपन्न हुई। बैठक के दौरान थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली व्यवहार और संवेदनशीलता पर खुलकर विचार.विमर्श किया गया। उपस्थित नागरिकों एवं व्यापारियों ने शहर की प्रमुख समस्याओं को प्रमुखता से उठाया की नगर में दिन.ब.दिन बढ़ती ट्रैफिक की समस्या। अपराधों की रोकथाम और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की सतत निगरानी। स्कूलों की छुट्टी व लगने के समय होने वाले ट्रैफिक्र जाम और सुरक्षा के इंतजाम। पुलिस प्रशासन के प्रति जनता के सकारात्मक व नकारात्मक अनुभव। संवाद के दौरान आमजन एवं व्यापारियों की ओर से पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव दिए गए। आईजी ललित शाक्यवार ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और प्राप्त सुझावों में से कुछ अति.आवश्यक बिंदुओं पर तत्काल अमल करने हेतु मातहत पुलिस अमले को मौके पर ही कड़े निर्देश जारी किए। वहीं अन्य जटिल सुझावों पर योजनाबद्ध तरीके से विचार कर त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया। इस आयोजन से पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा पारदर्शी पुलिसिंग की दिशा में एक सकारात्मक पहल देखने को मिली।

आपके सुझावों पर जल्द अमल किया जायेगा-आईजी

आईजी ललित शाक्यवार ने चर्चा में बताया कि मुख्यमंत्री कि यह पहल है जो कारगर है। जन विश्वास अभियान का यह तीसरा सप्ताह अधिकारी व्यक्तिगत जाकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं। जनता की परेशानी पुलिस का व्यवहार एवं इसके लिए यह एक चौपाल रखी गई थी। जिसमें सुझाव दिए गए हैं चर्चा में जानकारी मिली है कि पुलिस की पूर्व और वर्तमान कार्य प्रणाली में सुधार हुआ है,हर व्यक्ति को आदर दिया जा रहा हैं समस्या सुनी जा रही है। यहां जो बातें रखी गई उसमें कुछ समस्या पर जल्द निराकरण होगा जैसे स्कूल कॉलेज की छुट्टी समय ट्रैफिक्र की समस्या और अन्य विषय पर हम अमल करेंगे। इस अभियान की सार्थकता तब है जब इन सभी सुझावों पर अमल किया जा सके पुलिस और जनता के बीच सामंजस्य बनाना और आम जनता युवा वर्ग को संदेश देना कि वह अपने भविष्य पर ध्यान दें क्या करना है क्या नहीं करना है कहां जाना है कहां खड़े रहना है यह वह जरूर समझे सुरक्षित रहे। वह हर वारदात से दूर रहे पुलिस बल की जो कमी बताई जा रही है उसके लिए समीक्षा की जाएगी।

बन्दर के काटने से ५० वर्षीय महिला घायल

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम लड़सड़ा निवासी ५० वर्षीय श्यामकला दमाहे बंदर के काटने से घायल हो गई। जिसका उपचार सिविल अस्पताल में किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्यामकला पति कोदूराम दमाहे उम्र ५० वर्ष लड़सडा निवासी मंगलवार को मैहर गये थे। जहाँ गुरुवार की शाम अचानक एक बन्दर ने हमला कर हाथ में काट दिया। इसके बाद उनके द्वारा वापस आकर २१ अगस्त को सिविल अस्पताल वारासिवनी में जांच कराई गई। जहां डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार कर उन्हें लगने वाले इंजेक्शन का शेड्यूल बनाकर दे दिया गया है।

9 साल बाद भी सेवानिवृत्ति राशि का भुगतान नहीं, शिक्षक एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी हो रहे परेशान

शिक्षक समस्याओं को लेकर आल प्रगतिशील पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। शिक्षक एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ऑल प्रगतिशील पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौपा है।संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त कलेक्टर दीपक राणा से मुलाकात कर उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया जिसके उपरांत लंबित मामलों के निराकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।संगठन पदाधिकारियों ने स्कूल शिक्षा विभाग बालाघाट के जिला अधिकारी एवं कार्यालय स्टाफ की मनमानी और उदासीन कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का समय पर निराकरण नहीं होने से उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।संगठन के बी.डी. मेश्राम ने बताया कि वह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरवेली से 30 जून 2018 को सेवानिवृत्त हुए हैं। सामान्य प्रशासन कार्यालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के अनुसार उन्हें 94 दिनों का महंगाई अथवा वेतनवृद्धि से संबंधित लाभ दिया जाना था, लेकिन आदेश जारी होने के बावजूद आज तक उनका भुगतान नहीं किया गया है। श्री मेश्राम ने बताया कि उनकी अस्वस्थता को देखते हुए संबंधित प्रकरण के शीघ्र निराकरण के लिए आग्रह किया गया है। वहीं संगठन की एक प्रति तत्काल उच्च कार्यालय भोपाल को भी भिजवाई गई है।वही संगठन अध्यक्ष टी.एल. भालेकर ने अधिकारियों के समक्ष सभी लंबित मामलों और संगठन की समस्याओं को विस्तार से रखा। उन्होंने संबंधित कार्यालय अधिकारियों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। साथ ही कार्यालयीन कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर लंबित मामलों के त्वरित निराकरण की मांग की गई।प्रतिनिधिमंडल में संगठन के जिला अध्यक्ष टी.एल. मालेकर, जिला उपाध्यक्ष के.आर. सोनवाने, बी.डी. मेश्राम, जिला संगठन सचिव सुरेश बरौड़, मीडिया प्रभारी संतोष मेश्राम, जे.आर. मेश्राम, एस.एल. डहारे सहित मंडल स्तर के प्रतिनिधि शामिल रहे।

ई-टीपी की अवधि समाप्त होने के बाद मैगनीज परिवहन करते ट्रक जब्त

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले के मलाजखंड, तहसील बिरसा क्षेत्र में खनिज अमले द्वारा वाहन जांच के दौरान मैगनीज के अवैध परिवहन का मामला सामने आया है। जांच के दौरान ट्रक क्रमांक ष्टत्र08्र त्र-4435 को मैगनीज खनिज का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। उप संचालक खनित सुश्री फरहत जहॉ ने बताया कि खनिज अमले द्वारा वाहन में भरे मैगनीज के संबंध में ई-टीपी की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित वाहन की ई-टीपी की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी, इसके बावजूद वाहन द्वारा मैगनीज खनिज का परिवहन किया जा रहा था। नियम विरुद्ध खनिज परिवहन पाए जाने पर खनिज अमले ने उक्त ट्रक को जब्त कर पुलिस थाना मलाजखंड की अभिरक्षा में रखा है। मामले में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत खनिज नियमों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सड़क पर पैदल चलना भी मौलिक अधिकार, फिर फुटपाथ क्यों बेहाल?

सड़क पर पैदल चलना मौलिक अधिकार है, लेकिन आज भारत के कई शहरों में पैदल चलना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। दरअसल, आज भी बहुत से शहरों में फुटपाथ या तो बने ही नहीं हैं, या उन पर अतिक्रमण, पार्किंग और निर्माण सामग्री के कारण लोगों के चलने की जगह नहीं बचती। ऐसे में यहां पर प्रश्न यह उठता है कि जब किसी व्यक्ति के पास सड़क पर सुरक्षित रूप से पैदल चलने की जगह ही नहीं है, तो उसे वास्तव में आवागमन की आजादी कैसे मिल सकती है? उक्त संदर्भ में यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ समय पहले ही यानी कि 19 जून 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह कहा है कि सुरक्षित और निर्धारित पैदल मार्ग पर चलना भी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत आवागमन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। वास्तव में, यह मामला उस दुखद घटना से जुड़ा हुआ था, जिसमें पांच साल के एक बच्चे की सड़क पर टैंकर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वहां न फुटपाथ था और न ही सड़क पार करने की सुरक्षित व्यवस्था। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज कई भारतीय शहरों में फुटपाथ पर अतिक्रमण, टूटे या गायब फुटपाथ, सड़क पार करने के लिए अपर्याप्त क्रॉसिंग, तेज रफ्तार वाहन और यातायात नियमों का उल्लंघन पैदल यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ाते हैं और हमारे देश में पैदल यात्रियों की सुरक्षा अभी भी एक गंभीर चुनौती है। आंकड़ों की बात करें तो सरकारी भारत में सड़क दुर्घटनाएँ–2023 के अनुसार, वर्ष 2023 में 35,221 पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई, जो कुल सड़क दुर्घटना मौतों का 20.4त्न थी।सच तो यह है कि आज पर्याप्त पैदल यात्री बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है?। यहां पाठकों को बताता चलूं कि फुटपाथों का निर्माण और रखरखाव मुख्यत: राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के दायरे में आता है, इसलिए सरकारों और संबंधित निकायों को इन पर ध्यान देना चाहिए। यहां पाठकों को बताता चलूं कि वैसे विश्व में सड़क की गुणवत्ता, फुटपाथ, पैदल पार-पथ, ट्रैफिक नियंत्रण और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के मामलों में नीदरलैंड को दुनिया के सबसे अच्छे उदाहरणों में गिना जाता है। सच तो यह है कि नींदरलैंड पैदल चलने के लिए दुनिया में एक अग्रणी देश है, जहां पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए अलग एवं सुरक्षित मार्ग, कम गति वाले क्षेत्र और बेहतर सड़क डिजाइन उपलब्ध हैं। नींदरलैंड के बाद डेनमार्क विशेषकर कोपेनहेगन में पैदल यात्रियों के लिए सुव्यवस्थित फुटपाथ, क्रॉसिंग और ट्रैफिक–शांत क्षेत्र हैं। वहीं पर स्वीडन विश्व में कम पैदल मृत्यु दर और मजबूत सड़क–सुरक्षा व्यवस्था के कारण अग्रणी देशों में शामिल है।नॉर्वे(यूरोप में) तथा फिनलैंड भी पैदल मार्गों और सड़क पार करने की सुरक्षित व्यवस्था के मामले में विश्व में अहम् और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाल फिलहाल, यहां यह कहना चाहूंगा कि 19 जून 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क पर पैदल चलने के संदर्भ में जो फैसला दिया है,इस फैसले का सीधा सा संदेश यही है कि सरकार और स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि ये लोगों को सुरक्षित फुटपाथ और सड़क पार करने की उचित सुविधा उपलब्ध कराएं। वास्तव में,सच तो यह है कि नगर निगम, नगरपालिका, शहरी विकास प्राधिकरण और पंचायतों को आगे आकर इस दिशा में गंभीरता और संवेदनशीलता से काम करना होगा।बहरहाल, यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो, आंकड़े हमारी चिंताएं बढ़ाते हैं।

डिजिटल भारत में सर्पदंश का कहर-स्कूल में सर्पदंश से तीन मासूम बच्चों की मौत की गूँज

वैश्विक स्तरपर भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की महत्वाकांक्षी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधुनिक चिकित्सा, टेलीमेडिसिन डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और अत्याधुनिक संचार व्यवस्था के इस दौर में देश की विकास –गाथा तभी पूर्ण मानी जा सकती है,जब एक गरीब, ग्रामीण,आदिवासी अथवा दूरदराज के परिवार की जिंदगी भी उतनी ही मूल्यवान समझी जाए जितनीकिसी महानगर में रहने वाले नागरिक की। इसी कसौटी पर सर्पदंश आज भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने एक असहज लेकिन अत्यंत गंभीर प्रश्न बनकर खड़ा है।अनुमानित रूप से भारत में हर वर्ष लाखों लोग सर्पदंश का सामना करते हैं और लगभग 50 हजार या उससे अधिक मौतों का अनुमान लगाया गया है; उपलब्ध शोध भारत को वैश्विक सर्पदंश मृत्यु–भार के लगभगआधे से जोड़ता है?।हालांकि सरकारी निगरानी के आंकड़े इससे बहुत कम हैं,और यही अंतर बताता है कि समस्या केवल मृत्यु की नहीं,बल्कि अंडर–रिपोर्टिंग, समय पर उपचार न मिलने और कमजोर निगरानी व्यवस्था की भी है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह जानकारी देना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने 18 अगस्त 2026 (मंगलवार) को सर्पदंश को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित बीमारी घोषित किया है और इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन (अधिसूचना) जारी हो चुका है। मार्च 2026 में संसद में दिए गए उत्तर के अनुसार उस समय आठ राज्यों,कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय, नागालैंड त्रिपुरा, केरल,ओडिशा और अब महाराष्ट्र में सर्पदंश को अधिसूचित किया गया है सवाल उठता है कि, केंद्री व बाकी राज्यों द्वारा इसको सूची में समाहित की घोषणा कब की जाएगी? क्या वहां किसी घटना का इंतजार किया जा रहा है? इस संकट की भयावहता को महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले के धानोरा तालुका स्थित जपतलाई की अनुदानित आदिवासी आश्रमशाला की घटना ने एक बार फिर देश के सामने ला खड़ा किया है। अगस्त 2026 में इस आवासीय विद्यालय के छात्रावास में रात के समय विषैले सांप के काटने से छह छात्राएं प्रभावित हुईं।उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार तीन छात्राओं 8, 12 और 14 वर्ष की मृत्यु हो गई,जबकि तीन अन्य छात्राओं का उपचार किया गया। घटना के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू की और आश्रमशाला की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। यह केवल तीन परिवारों की त्रासदी नहीं है; यह उस भारत के सामने खड़ा प्रश्न है जो 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है। यदि हमारे आवासीय विद्यालयों में सो रहे बच्चों की सुरक्षा सर्पदंश जैसी रोकथाम योग्य और उपचार योग्य आपातस्थिति के सामने सुनिश्चित नहीं हो सकती, तो विकास के हमारे मॉडल को केवल डिजिटल कनेक्टिविटी से नहीं,बल्कि जीवन– सुरक्षा की अंतिम मील तक पहुंच से भी परिभाषित करना होगा। होली पर मेरी पूरी नजर लगी हुई थी महाराष्ट्र सरकार लगातार एक्शन ले रही थी और अब 18 अगस्त 2026 को अधिचित बीमारी की सूची में डालने का नोटिफिकेशन जारी किया जो सराहनीय कार्यवाही है। साथियों बात अगर हम सर्पदंश की त्रासदी का दूसरा पहलू और भी चिंताजनक है इसको समझने की करें तो अंधविश्वास और उपचार में देरी।आज भी अनेक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सांप के काटने के बाद पीड़ित को अस्पताल ले जाने के बजाय ओझा,तांत्रिक, झाड़– फूंक या पारंपरिक उपचार के लिए ले जाने की प्रवृत्ति मौजूद है।इसके पीछे केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संस्थानों से दूरी,परिवहन की कमी, एंटी– स्नेक वेनम की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता और चिकित्सा व्यवस्था पर अविश्वास जैसे कारण भी हैं। परिणाम यह होता है कि वह महत्वपूर्ण समय, जिसमें मरीज को जीवनरक्षक चिकित्सा मिल सकती थी, समाप्त हो जाता है। इसलिए सर्पदंश को केवल सांप और इंसान के बीच की घटना मानना गलत होगा; यह स्वास्थ्य व्यवस्था, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, परिवहन, डिजिटल निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा बहुआयामी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। साथियों बात अगर हम यहीं सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी बनाने की आवश्यकता सामने आती है इसको समझने की करें तो, अधिसूचना का मूल महत्व यह है कि स्वास्थ्य संस्थानों में दर्ज होने वाले मामलों और मौतों की व्यवस्थित सूचना सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी तंत्र तक पहुंचे। कर्नाटक ने फरवरी 2024 में इस दिशा में ऐतिहासिक पहल की और सर्पदंश के मामलों तथा मौतों की रिपोर्टिंग को अनिवार्य किया। राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों तथा चिकित्सा संस्थानों को मामलों को इंटेग्राटेड हेल्थइनफार्मेशन प्लेटफार्म पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया।कर्नाटक का अनुभव यह दिखाता है कि अधिसूचना के बाद आंकड़े बढ़ते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि सर्पदंश अचानक बढ़ गया है; बेहतर रिपोर्टिंग के कारण पहले छिपे हुए मामले सामने आने लगते हैं। जुलाई 2026 की एक रिपोर्ट में कर्नाटक में 2023 से 2025 के बीच रिपोर्ट किए गए मामलों में तेज वृद्धि का उल्लेख करते हुए बताया गया कि बेहतर सर्वेलेंस और डेथ ऑडिट ने समस्या की वास्तविक तस्वीर सामने लाने में मदद की। साथियों बात अगर हम भारत सरकार ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, इसको समझने की करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12 मार्च 2024 को नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रेवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेकबाईट इनवेनोमिंग (एनएपी –एसई) लॉन्च किया। इसका घोषित विजन 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और विकलांगता को आधा करना है। योजना में उपचार की उपलब्धता, स्वास्थ्यकर्मियों की क्षमता– वृद्धि, रेफरल व्यवस्था, जन– जागरूकता और सर्पदंश की निगरानी जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भी सर्पदंश निगरानी, स्वास्थ्यकर्मियों के प्रशिक्षण, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आपात सेवाओं को मजबूत करने, एंटी–स्नेक वेनम की उपलब्धता की डिजिटल मैपिंग तथा सामुदायिक जागरूकता को प्रमुख रणनीतियों में रखता है।लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रश्न है। यदि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक मृत्यु और विकलांगता को आधा करना है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देशभर में विश्वसनीय और तुलनीय डेटा भी चाहिए। साथियों,मार्च 2026 में लोकसभा में दिए गए सरकारी उत्तर के अनुसार 2023, 2024 और 2025 में आईडीएसपी –आईएचआईपी के माध्यम से रिपोर्ट की गई सर्पदंश मौतें क्रमश:183, 370 और 431 थीं।उसी उत्तर में केंद्र सरकार ने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों के अंतर्गत सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की सलाह दी गई है। इन आंकड़ों और अनुमानित वास्तविक भार के बीच का विशाल अंतर अपने आप में एक चेतावनी है, सरकारी सर्वेलेंस में दर्ज आंकड़े ही पूरी समस्या नहीं हैं।इसलिए केंद्र सरकार के लिए अब अगला कदम केवल सलाह जारी करना नहीं, बल्कि राज्यों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय, एकरूप और बाध्यकारी सर्वेलेंस फ्रेमवर्क तैयार करना होना चाहिए। स्वास्थ्य मुख्यत: राज्य का विषय होने के बावजूद सर्पदंश का प्रभाव राज्य की सीमाओं में सीमित नहीं है। सांपों का प्राकृतिक आवास, ग्रामीण आजीविका, कृषि क्षेत्र, जंगल, प्रवासी श्रमिक, आदिवासी आबादी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच,ये सभी अंतरराज्यीय आयाम रखते हैं। केंद्र सरकार राज्यों को उनके संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हुए एक समान न्यूनतम मानक, डिजिटल रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल, उपचार प्रोटोकॉल, एंटी– वेनम की उपलब्धता और इमरजेंसी रेफेरल व्यवस्था के लिए स्पष्ट ऑपरेशनल फ्रेमवर्क दे सकती है। साथियों बात अगर हम सर्पदंश को अधिसूचित करने का सबसे बड़ा लाभ सटीक डेटा है,इसको समझने की करें तो, जब सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों से मामलों की व्यवस्थित सूचना आएगी तो सरकार यह जान सकेगी कि कौन–से जिले,तहसील, गांव और मौसम सर्पदंश के लिहाज से अधिकसंवेदनशील हैं।इसके आधार परस्नेकबाईट हॉटस्पॉट्स का डिजिटल मानचित्र तैयार किया जा सकता है।यही डेटा यह तय करने में मदद करेगा कि किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में कितना एंटी–स्नेक वेनम उपलब्ध होना चाहिए,कहां एम्बुलेंस नेटवर्क मजबूत करना है और किन क्षेत्रों में विशेष जन– जागरूकता अभियान चलाना है।सर्पदंश के बाद प्राथमिक उपचार के संबंध में भी देशव्यापी वैज्ञानिक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।पीड़ित को शांत रखना, काटे गए अंग की अनावश्यक मूवमेंट रोकना, अंगूठी,घड़ी और अन्य कसाव वाली वस्तुएं हटाना तथा उसे तत्काल ऐसे चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाना जहां उचित उपचार उपलब्ध हो,जीवन बचाने में महत्वपूर्ण है।

इसके विपरीत घाव काटना, मुंह से जहर चूसना, बर्फ या बिजली का प्रयोग करना, घरेलू लेप लगाना अथवा कसकर टूरनिक्वेट बांधना नुकसानदायक हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश स्पष्ट होना चाहिए, झाड़ –फूंक में समय न गंवाएं; सर्पदंश एक चिकित्सा आपातस्थिति है। एंटी–स्नेक वेनम और आवश्यक सपोर्टिव केयर तक शीघ्र पहुंच जीवन बचाने की कुंजी है। साथियों बात अगर हम सर्पदंश की रोकथाम बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको समझने की करें तो, खेतों, जंगलों और झाड़ियों में जाने वाले लोगों को उचित जूते पहनने, रात में टॉर्च का इस्तेमाल करने,घास या झाड़ियों में कदम रखने से पहले सावधानी बरतने और घर के आसपास कूड़ा,लकड़ी, पत्थर तथा अनावश्यक ढेर न जमा करने की जानकारी दी जानी चाहिए।चूहों कानियंत्रण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सांपों के लिए भोजन का स्रोत बन सकते हैं।स्कूलों और आश्रमशालाओं के लिए इससे आगे बढ़कर विशेष स्नेकबाईट सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए,बेड/सोने की सुरक्षित व्यवस्था, कमरे और परिसर की नियमित जांच, दरवाजों–खिड़कियों की सुरक्षा, रात में रोशनी, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र से इमरजेंसी लिंकेज और कर्मचारियों की प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण अनिवार्य किया जा सकता है। साथियों बात अगर हम डिजिटल भारत के पास इस समस्या से लड़ने के लिए साधन भी मौजूद हैं, इसको समझने की करें तो मोबाइल– आधारित रिपोर्टिंग , जीपीएस –इनेबलड हॉटस्पॉट मैपिंग, रियल टाइम दशबोर्ड्स अस्पतालों में एएसवी स्टॉक अलर्टस, एम्बुलेंस ट्रैकिंग, टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन और स्थानीय भाषाओं में व्हाट्सएप्प अथवा अन्य डिजिटल जागरूकता अभियान सर्पदंश नियंत्रण को नई गति दे सकते हैं।

-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

कब तक जारी रहेगा जहरीली शराब का जानलेवा कहर?

-मनोज कुमार अग्रवाल

भारत में जहरीली शराब से होने वाली मौतें एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती बनी हुई हैं, जिसमें ड्राई स्टेट शराबबंदी वाले राज्यों से लेकर अन्य राज्यों तक लगातार दुखद घटनाएं सामने आती रहती हैं। ताजा मामला अगस्त 2026 में गुजरात के भावनगर का है, जहां नकली विदेशी शराब के नाम पर बेची गई जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जहरीली शराब का यह जानलेवा सिलसिला देश के विभिन्न हिस्सों में समय–समय पर देखने को मिलता है एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती बना हुआ है। ट्रांसनेशनल अलायंस टू कॉम्बैट इलिसिट ट्रेड जैसी संस्थाओं के अनुसार, भारत में अवैध शराब की खपत दुनिया के सबसे बड़े अवैध बाजारों में से एक है। यह न केवल सरकारी राजस्व को भारी चोट पहुँचाता है, बल्कि इसके कारण हर साल सैकड़ों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।देश भर में आए दिन जहरीली और नकली शराब से होने वाली मौतें अब केवल दुर्घटनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि ये घटनाएं हमारी व्यवस्था, कानून और समाज के सामने एक गंभीर सवाल हैं । कुछ दिन सप्ताह माह के अन्तराल पर देश के किसी न किसी हिस्से से खबर आती है कि नकली शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी, कई अस्पताल पहुंचे और कुछ ने दम तोड़ दिया। प्रशासन सक्रिय होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, जांच बैठती है, मुआवजे की घोषणा होती है और कुछ समय बाद मामला ठंडे बस्ते में पहुंच जाता है। फिर किसी दूसरे शहर, गांव या राज्य में वही कहानी दोहराई जाती है। सवाल यही है, आखिर यह सिलसिला कब थमेगा ? आपको बता दें कि ताजा मामला गुजरात के भावनगर जिले का है। गुजरात उन राज्यों में है जहां लंबे समय से शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद भावनगर में कथित नकली शराब पीने के बाद कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की घटना सामने आई है। स्थानीय प्रशासन ने चार लोगों की मौत की जानकारी दी थी, जबकि अन्य लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा था। शुरुआती रिपोटों में मौतों की संख्या कम थी, जो बाद में बढ़ी। यह घटना इसलिए भी अधिक गंभीर है, क्योंकि जिस राज्य में शराब की बिक्री और सेवन पर कानूनी प्रतिबंध है, वहां नकली शराब लोगों तक पहुंच कैसे रही है? पुलिस की शुरुआती जांच में एक लोकप्रिय ब्रांड के नाम पर डुप्लीकेट शराब बेचे जाने और इसके मध्य प्रदेश से लाए जाने की आशंका सामने आई है। पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े लोगों को हिरासत में भी लिया है। लेकिन भावनगर कोई पहली घटना नहीं है।हाल ही में मई माह में महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी–चिंचवड़ त्रासदी इलाकों में जहरीली शराब पीने से 14 से 18 लोगों की जान चली गई। पुलिस जांच के अनुसार, अवैध रूप से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड का घातक मेथनॉल मिक्स किया गया था।मई माह में ही पंजाब के अमृतसर के पांच गांवों में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात ने जुलाई 2022 में भी भयावह शराब त्रासदी देखी थी। बोटाद और आसपास के इलाकों में जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उस समय भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, अधिकारियों का तबादला हुआ और अवैध शराब के नेटवर्क को तोड़ने के दावे किए गए थे। सवाल है कि चार वर्ष बाद भी यदि नकली शराब लोगों तक पहुंच रही है तो पिछली कार्रवाई से हमने आखिर सीखा क्या? यह समस्या केवल गुजरात तक सीमित नहीं है। पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्य समय–समय पर ऐसी त्रासदियों के गवाह बने हैं। तमिलनाडु के कालाकुरिची में जून 2024 में मेथेनॉल मिली अवैध शराब ने दर्जनों परिवारों को उजाड़ दिया था। आधिकारिक कार्रवाई के दौरान अवैध शराब जब्त हुई, गिरफ्तारियां हुई और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में भी अवैध एवं नकली शराब के सेवन से होने वाली मौतों को अलग श्रेणी में दर्ज किया जाता है। उपलब्ध एनसीआरबी आधारित डेटा 2012 से 2024 तक राज्य वार ऐसी मौतों का हवाला देता है। इससे इतना तो साफ है कि यह किसी एक राज्य या एक क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही एक खतरनाक चुनौती है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अक्सर इन घटनाओं में मरने वाले लोग समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल कमजोर वर्ग से आते हैं। सस्ती शराब की तलाश उन्हें ऐसे अवैध कारोबारियों तक पहुंचा देती है जिन्हें न गुणवत्ता की चिंता होती है, न कानून का भय और न इंसानी जीवन की कीमत का एहसास। अधिक नशा पैदा करने या लागत कम रखने के लिए शराब में मेथेनॉल जैसे जहरीले रसायनों की मिलावट जानलेवा साबित हो सकती है। कल्लाकुरिची मामले में भी मेथेनॉल मिश्रित शराब की पुष्टि सामने आई थी। अधिकरत देखा जाता है कि हर बड़ी आसदी के बाद प्रशासन की एक परिचित तस्वीर सामने आती है। छापेमारी शुरू होती है, अवैध ठिकाने बंद किए जाते हैं, संदिग्ध गिरफ्तार होते हैं और पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा जाता है। लेकिन असली चुनौती घटना के बाद कार्रवाई करने की नहीं, घटना होने से पहले नेटवर्क को समाप्त करने की है। अवैध शराब का कारोबार अकेले किसी गली या गांव में बैठा व्यक्ति नहीं चला सकता। कच्चा माल कहां से आता है? बोतलें कहां बनती हैं? लोकप्रिय कंपनियों के नाम और लेबल की नकल कैसे होती है? माल एक जिले से दूसरे जिले और कई बार एक राज्य से दूसरे राज्य तक कैसे पहुंचता है? परिवहन, भंडारण और बिक्री की जानकारी स्थानीय स्तर पर किसी को क्यों नहीं मिलती? यदि वर्षों तक कारोबार चलता रहता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही, स्थानीय संरक्षण या भ्रष्ट तंत्र भी इसका रास्ता आसान कर रहा है। शराबबंदी वाले राज्यों के लिए यह समस्या और बड़ी चुनौती है। केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं होता। यदि वैध बिक्री बंद होने के बाद अवैध बाजार पैदा हो जाए और उसकी निगरानी कमजोर रहे तो तस्करों को अधिक मुनाफे का अवसर मिलता है। शराबबंदी का उद्देश्य समाज को नशे से बचाना है, लेकिन यदि उसी व्यवस्था के भीतर जहरीली शराब का संगठित बाजार फलने लगे तो नीति की समीक्षा और क्रियान्वयन दोनों जरूरी हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि शराबबंदी गलत है या शराब की खुली बिक्री समाधान है। असली प्रश्न नीति से अधिक उसके प्रभावी क्रियान्वयन का है। जहां प्रतिबंध है वहां अवैध सप्लाई पर कठोर निगरानी होनी चाहिए और जहां शराब की कानूनी बिक्री है वहां नकली उत्पादों की पहचान और वितरण व्यवस्था पर नियंत्रण मजबूत होना चाहिए। सरकारों को अब प्रत्येक त्रासदी के बाद केवल मुआवजा देने और कुछ लोगों को निलंबित करने से आगे बढ़ना होगा। अवैध शराब के मामलों में सप्लाई चेन की तह तक जांच, औद्योगिक मेथेनॉल की बिक्री और परिवहन की निगरानी, नकली ब्रांड और पैकेजिंग बनाने वालों पर कार्रवाई तथा बार–बार अवैध कारोबार में पकड़े जाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जरूरी है।यह सारा अवैध कारोबार बिना सरकारी तंत्र की मिलीभगत के सम्भव नहीं है स्थानीय पुलिस और आबकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसके साथ ही ग्रामीण और गरीब बस्तियों में जागरूकता बढ़ानी होगी। लोगों को बताया जाना चाहिए कि अनजान स्रोत से खरीदी गई शराब जानलेवा हो सकती है। संदिग्ध शराब पीने के बाद उल्टी, चक्कर, दृष्टि धुंधली होने वा अन्य परेशानी के मामलों में तुरंत अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी है। कई बार इलाज में देर भी मौतों की संख्या बढ़ा देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहरीली शराब से हुई हर मौत को महज एक आंकड़ा समझने की मानसिकता बदलनी होगी। मरने वाला किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य, बेटा, पिता या भाई होता है।

बुजुर्गों की अनदेखी नहीं, सम्मान ही सभ्य समाज की असली पहचान

बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है, जहां व्यक्ति को सबसे अधिक सहारे, सम्मान और अपनत्व की आवश्यकता होती है। जिस माता–पिता ने अपने बच्चों को पालने, पढ़ाने और उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसी उम्र में यदि उन्हें अपने ही घर में उपेक्षा, अपमान या असुरक्षा का सामना करना पड़े तो यह केवल एक परिवार की समस्या नहीं रह जाती, बल्कि पूरे समाज के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। इसी संवेदनशील मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी ने देश का ध्यान बुजुर्गों की गरिमा और सुरक्षा की ओर खींचा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और भरण–पोषण सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कानून के तहत ट्रिब्यूनल जरूरत पड़ने पर बच्चों को माता–पिता की संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दे सकता है। अदालत ने कहा कि बढ़ती उम्र का अर्थ असुरक्षा, उपेक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवनभर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। यह टिप्पणी केवल कानूनी अधिकारों की व्याख्या नहीं है, बल्कि परिवार और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी है।

बुजुर्ग परिवार की जिम्मेदारी नहीं, अनुभव की विरासत हैं

आज के बदलते पारिवारिक ढांचे में बुजुर्गों को कई बार केवल देखभाल की जरूरत रखने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगता है। यह सोच बेहद संकीर्ण है। बुजुर्ग परिवार के अनुभव, परंपराओं, संस्कारों और सामूहिक स्मृतियों के वाहक होते हैं। उन्होंने अपने जीवन के उतार–चढ़ाव से जो अनुभव हासिल किए हैं, वह किसी किताब में आसानी से नहीं मिल सकता। एक समय था जब संयुक्त परिवारों में दादा–दादी और नाना–नानी बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा होते थे। घर के निर्णयों में उनकी राय को महत्व दिया जाता था। आज परिवार छोटे हो गए हैं, कामकाज का दबाव बढ़ा है और पीढ़ियों के बीच संवाद कम हुआ है। इसका असर बुजुर्गों पर भी पड़ा है। कई वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद भावनात्मक अकेलेपन का सामना करते हैं और कई ऐसे भी हैं जिन्हें अपने ही घर में सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आया मामला लखनऊ के विकास नगर निवासी रवि कांत गुप्ता की अपील से जुड़ा था। गुप्ता ने अपने बेटे को मकान से बाहर करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया था। यह मकान उनकी स्वयं की खरीदी हुई संपत्ति थी। मामले की संवेदनशीलता इस तथ्य से भी सामने आती है कि उनकी 81 वर्षीय मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। एसडीएम ने नवंबर 2022 में बेटे की बेदखली का आदेश दिया था। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने भी उस आदेश को बरकरार रखते हुए बेटे और बहू को मकान खाली करने का निर्देश दिया। हालांकि, बेटे और बहू ने इन आदेशों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने बेदखली का आदेश रद्द करते हुए माना था कि 2007 का कानून बुजुर्गों को अपनी संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का अधिकार नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि बुजुर्गों की सुरक्षा और भरण–पोषण के लिए आवश्यक होने पर ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश दे सकता है। अदालत ने कानून के उद्देश्य को व्यापक रूप से देखते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना इस कानून की मूल भावना है। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का उद्देश्य केवल बुजुर्गों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं है। इसका व्यापक उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। कानून के तहत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक अपने भरण–पोषण के लिए संतान से सहायता मांग सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वे मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का सहारा ले सकते हैं। यदि किसी बुजुर्ग ने इस उम्मीद में अपनी संपत्ति बच्चों को दी है कि बच्चे उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन बाद में उनकी उपेक्षा की जाती है, तो कानून उन्हें राहत पाने का रास्ता भी देता है। ऐसे मामलों में संपत्ति हस्तांतरण को रद्द कराने की व्यवस्था भी कानून में है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब बुजुर्ग की सुरक्षा और गरिमा का सवाल हो, तब संपत्ति से बच्चे को हटाना भी कानूनी संरक्षण का एक आवश्यक उपाय हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर पारिवारिक विवाद में बच्चों को घर से बाहर किया जाएगा। मामला परिस्थितियों, बुजुर्ग की सुरक्षा और कानून के उद्देश्य के आधार पर देखा जाएगा।

घर में होने वाला अत्याचार हमेशा दिखाई नहीं देता

बुजुर्गों के साथ होने वाला घरेलू अत्याचार केवल मारपीट तक सीमित नहीं है। कई बार उन्हें लगातार अपमानित करना, उनकी बातों को महत्व न देना, आर्थिक रूप से निर्भर बनाना, संपत्ति के लिए दबाव डालना, घर से अलग कर देना या उनकी मूलभूत जरूरतों की उपेक्षा करना भी अत्याचार का स्वरूप ले सकता है। सबसे दुखद स्थिति तब होती है जब बुजुर्ग शिकायत करने से भी डरते हैं। उन्हें भय रहता है कि शिकायत करने से परिवार टूट जाएगा या समाज में उनकी बदनामी होगी। कई माता–पिता अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करने से इसलिए बचते हैं क्योंकि उनके मन में आज भी बच्चों के प्रति ममता और परिवार बचाने की इच्छा सबसे ऊपर होती है। लेकिन सम्मान और सुरक्षा किसी भी बुजुर्ग पर परिवार की कृपा नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। बच्चों का कर्तव्य केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं होना चाहिए। बुजुर्गों को भावनात्मक सुरक्षा, सम्मान और निर्णयों में स्थान देना भी परिवार की जिम्मेदारी है।

सभ्य समाज की पहचान बुजुर्गों के व्यवहार से होती है

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण सामने रखा कि किसी सभ्य समाज का स्तर इस बात से भी तय होता है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यह बात केवल अदालत या कानून के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार के लिए आत्ममंथन का विषय है। जिस घर में बुजुर्गों को सम्मान मिलता है, वहां बच्चों को भी रिश्तों की कीमत समझ आती है। वहीं जिस घर में माता–पिता की उपेक्षा होती है, वहां अगली पीढ़ी भी वही व्यवहार सीख सकती है। आज जो बच्चे अपने माता–पिता को सम्मान देते हुए देखते हैं, कल वे भी उसी संस्कार को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान केवल परंपरा निभाना नहीं है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सामाजिक संस्कार तैयार करना भी है। क्योकि संपत्ति रिश्तों से बड़ी नहीं हो सकती है।बुजुर्गों से जुड़े कई विवादों की जड़ में संपत्ति दिखाई देती है। घर, जमीन और विरासत को लेकर परिवारों में मतभेद बढ़ते हैं। कई बार संपत्ति पाने के बाद बच्चों का व्यवहार बदल जाता है और माता–पिता को यह महसूस होने लगता है कि उनकी उपयोगिता केवल संपत्ति तक सीमित थी। ऐसी परिस्थितियां परिवार के लिए बेहद चिंताजनक हैं। संपत्ति जीवन की सुविधा दे सकती है, लेकिन वह रिश्तों की जगह नहीं ले सकती। माता–पिता ने बच्चों को संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण चीज दी होती है, वह है जीवन, शिक्षा, संस्कार और संघर्ष से मिली सीख। कानून का हस्तक्षेप तभी सामने आता है जब पारिवारिक व्यवस्था बुजुर्गों को सुरक्षा देने में असफल हो जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि विवाद अदालत या ट्रिब्यूनल तक पहुंचने से पहले परिवार के भीतर संवाद और संवेदनशीलता से हल किए जाएं। आज बुजुर्गों की सबसे बड़ी जरूरत हमेशा पैसा या महंगी सुविधाएं नहीं होतीं। कई बार उन्हें केवल कुछ समय बातचीत करने वाला अपना व्यक्ति चाहिए। उनकी बात सुनना, उनके अनुभव पूछना, उन्हें परिवार के निर्णयों में शामिल करना और यह एहसास कराना कि वे आज भी परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। बुजुर्गों की भावनाओं को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ सामाजिक दायरा सीमित हो सकता है। ऐसे समय में परिवार ही उनका सबसे बड़ा सहारा बनता है। यदि परिवार ही उनसे दूरी बना ले तो अकेलापन और असुरक्षा गहरी हो सकती है। सम्मान की शुरुआत घर से होनी चाहिए।सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका सबसे बड़ा संदेश सामाजिक है। अदालतें अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं, कानून सुरक्षा दे सकता है और प्रशासन शिकायत पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन बुजुर्गों को वास्तविक सम्मान परिवार ही दे सकता है। हमें यह समझना होगा कि बुढ़ापा जीवन का बोझ नहीं, जीवनभर के अनुभवों का परिणाम है। आज के युवा जिस उम्र में अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, उसी तरह उनके माता–पिता ने कभी उनके भविष्य के लिए अपना वर्तमान समर्पित किया था। इसलिए जब जीवन का अंतिम पड़ाव आता है तो उन्हें अकेला छोड़ देना मानवीय संवेदनाओं के विपरीत है। बुजुर्गों के साथ सम्मानजनक व्यवहार केवल उनका अधिकार नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। यदि परिवार अपने बुजुर्गों का हाथ थामे रहे तो कई विवाद अदालत तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो सकते हैं। कानून की जरूरत तब पड़ती है जब संवेदना कमजोर पड़ जाती है। इसलिए समाज को ऐसी स्थिति आने ही नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का संदेश स्पष्ट है कि उम्र बढ़ने के साथ किसी व्यक्ति की गरिमा कम नहीं होती। बल्कि जीवन के अनुभवों के कारण उसका सम्मान और बढ़ना चाहिए।

-कांतिलाल मांडोत

इंदौर बाजार भाव

इंदौर। एजेंसी। मुहूर्त के अभाव में शुक्रवार को किराना में सोयाबीन चटकार बोला गया। खाद्य तेलों में सुस्ती रही। दालभाव में उड़द बाजार बढ़त पर [illegible] ... भाव इस प्रकार रहे-

किराना- शक्कर 6400-6550, खोपरा गोला 370-420, खोपरा बूरा 3200-6800 (15 कि.ग्रा.), जीरा राजस्थान 280-285, ... हल्दी निजामाबाद 210-230, सांगली 275-280, ... बैरा 6000-6100, ... नारियल 1150-1250, ... [illegible]

तेल- ... मूंगफली 1720-1740, मुम्बई 1750, राजकोट 2700, ... [illegible]

खली- कपास्या खली (60 कि.ग्रा.) इंदौर 2690, देवास-उज्जैन 2690, खंडवा-बुरहानपुर 2660, अकोला 3950 (प्रति क्विंटल)

तिलहन- सरसों 8000-8200, रामतिल 7200-7400, सोयाबीन 6000, ... अलसी 8500-9000, ... 7200-7500,

दलहन- चना कांटेवाला बेस्ट 6600-6650, ... विशाल 6350-6425, ... काबुली चना डॉलर 7000-8300, ... मसूर बेस्ट 6000-6050, ... मूंग ... तुअर निमाड़ी बेस्ट 7200-7400, ... उड़द गर्मी 8400-8800, ... हल्की 4000-6000,

दाल- चना दाल एवरेज 7400-7500, ... तुअर दाल 7300-7600, ... मसूर दाल 6800-7100, मूंग दाल 8700-8900, ... उड़द दाल 9900-10300, ... 10800-11000,

अनाज- गेहूं मिल क्वालिटी 2500-2550, लोकवन एवरेज 2550-2650, बेस्ट 2750-2800, मालवराज 2600-2650, गेहूं पूर्णा एवरेज 2400-2550, बेस्ट 2650-2750, मक्का पीली 1975-2000,

चावल- बासमती ... 2900-3100, ... 3400-3500, दुबराज 4500-5500, ... [illegible] ... मोगरा 5000-7000, तिबार 10500-11800, बासमती (921) 12000-13000, ... पोहा 4500-5100,

साबूदाना- इंदौर 340, उज्जैन 280, रतलाम 275, रु. प्रति किलो।

इंदौर सराफा बाजार

इन्दौर। एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बनी तेजी के बाद घरेलू बाजार में दोनों ही मूल्यवान धातुओं में उछाल पर रहे। भाव इस प्रकार रहे -

चांदी (9999) 242000, चांदी (99) 241800, टंच 241200, सिक्का 2600, सोना 10 ग्राम 156000,

रुपया बढ़त के साथ बंद

मुंबई। एजेंसी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को भारतीय रुपया 5 पैसे की बढ़त के साथ 95.69 पर बंद हुआ। ... 95.65 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। ... [illegible] ... 95.74 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद

मुंबई। एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को हल्की बढ़त पर बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच ही उतार-चढ़ाव बनी रहने से बाजार पर अंकुश लगा रहा। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भी बाजार पर दबाव आया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से भी घरेलू बाजार पर दबाव बना। दिनभर के कारोबार के बाद दोनों प्रमुख सूचकांक सपाट बंद हुए। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स केवल 3.11 अंक की हल्की बढ़त के साथ ही 77,540.83 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी केवल 20.15 अंक बढ़कर 24,252.00 के स्तर पर बंद हुआ। आज कई शेयरों में कमजोरी रही पर छोटे और मध्यम शेयरों में

अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 0.1 फीसदी की बढ़त रही। वहीं निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक 0.69 फीसदी बढ़कर बंद हुआ। इससे साफ है कि खुदरा निवेशकों का भरोसा छोटे शेयरों में बना हुआ है। आज के कारोबार में धातु और निजी बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा चमक रही। इन दोनों सेक्टरों ने बाजार को सहारा देने का काम किया जबकि, एफएमसीजी, ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा और इन्होंने बाजार के शुरुआती बढ़त को कमजोर किया। आज सबसे अधिक गिरावट मारुति सुजुकी और इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में रही। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार हल्की बढ़त के साथ खुला। मुंबई सेंसेक्स 82.30 अंक बढ़कर 77,620.03 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी भी 18.65 अंक, की बढ़त के साथ 24,250.50 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। व्यापक मार्केट में मिलाजुला रुख दिखा। निफ्टी मिडकैप में 0.04 फीसदी की मामूली गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 0.44 फीसदी की अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था।

पीएनबी की चेतावनी, निष्क्रिय खाते बंद होने का खतरा, तुरंत करें केवायसी अपडेट

मुंबई। एजेंसी। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने लाखों ग्राहकों के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है। बैंक ने ऐसे निष्क्रिय खातों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है जिनमें लंबे समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है और जिनका बैलेंस शून्य है। ग्राहकों को सिर्फ तब कार्रवाई करने की सलाह दी गई है, ताकि उनके खाते बंद होने से बच सकें। पीएनबी के अनुसार, ऐसे बैंक खाते जिनमें पिछले तीन साल से कोई लेनदेन दर्ज नहीं हुआ है और खाते में कोई राशि भी नहीं है, उन्हें बंद किया जा सकता है। बैंक ने यह कदम खातों के गलत इस्तेमाल और उनसे जुड़े धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया है। पीएनबी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया माध्यमों पर भी यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसमें खाताधारकों को सचेत किया गया है। निष्क्रिय खाताधारक अपने खाते को बंद होने से बचाने के लिए नजदीकी शाखा में अपने केवायसी दस्तावेज जमा कराकर इसे दोबारा सक्रिय करा सकते हैं। केवायसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राहक बैंक की सेवाओं का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे। बैंक ने यह भी सलाह दी है कि कोई भी ग्राहक अपना खाता बंद करने का निर्णय लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह ईएमआई, सब्सिडी, और बीमा या किसी अन्य महत्वपूर्ण भुगतान से जुड़ा न हो। पीएनबी ने ग्राहकों से समय-समय पर अपने खाते में लेनदेन करने और अपनी केवायसी जानकारी अपडेट रखने का आग्रह किया है। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए ग्राहक पीएनबी के आधिकारिक हेल्पलाइन माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं।

बंगाल का औद्योगिक सपना, दशकों का सफर और अनसुलझी तस्वीर

नई दिल्ली। एजेंसी। पश्चिम बंगाल ने पिछले तीन दशकों में अपनी औद्योगिक और आर्थिक छवि को बदलने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। 1994 में वाम मोर्चा सरकार द्वारा निजी निवेश के द्वार खोलने से लेकर आज तृणमूल कांग्रेस के आईटी हब के प्रयासों तक, राज्य ने निवेश आकर्षित करने और अपनी छवि सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। हालांकि, चमकदार शहरी विकास के बावजूद, राज्य की औद्योगिक तस्वीर अभी भी कई चुनौतियों से घिरी हुई है। सितंबर 1994 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने मुख्यमंत्री ज्योति बसु के नेतृत्व में, निजी निवेश के लिए द्वार खोलते हुए एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। ... [illegible] ... हालांकि, सॉल्ट लेक और राजारहाट जैसे क्षेत्रों में आईटी कंपनियों के परिसर, ... [illegible] ... राज्य की औद्योगिक छवि में अभी बदलाव अधूरा प्रतीत होता है।

आज का राशिफल

मेष- आज आपको एक जरूरी बात समझ आएगी कि कामों के साथ पैसों का संतुलन भी उतना ही जरूरी है। खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए दिखावे पर पैसा खर्च करने से बचें, वरना बजट प्रभावित हो सकता है। अच्छी बात यह है कि आपकी मेहनत की तारीफ होगी और अधिकारी भी आपके प्रदर्शन से खुश नजर आएंगे। पारिवारिक कामों को लेकर थोड़ी चिंता होगी, लेकिन आखिरकार समाधान निकल सकता है।

वृषभ- आज आपकी कार्यकुशलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। भाग्य का साथ मिलने से जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता की उम्मीद रहेगी। पुराने कर्ज को चुकाने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। दोस्तों से कुछ बड़ा फैसला भी संभव है। भाई-बहनों के साथ अगर किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी, तो उसे खत्म करने का अच्छा मौका मिलेगा।

मिथुन- आज अपनी बुद्धि और समझदारी का सही इस्तेमाल करने का दिन है। आपके कुछ फैसले आसपास के लोगों को चौंका सकते हैं, लेकिन उनका असर सकारात्मक रह सकता है। सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी और लोगों का समर्थन बढ़ेगा। घर के छोटे बच्चे आपसे कोई खास चीज मांग सकते हैं और उनकी इच्छा पूरी करके आपको भी खुशी मिलेगी।

कर्क- आज आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते दिखाई दे सकते हैं, हालांकि मन में हल्का तनाव भी बना रह सकता है। परिवार में किसी मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। हर बात में दखल देने के बजाय कुछ मामलों में चुप रहना ही बेहतर होगा।

सिंह- आज आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिल सकते हैं, लेकिन अचानक आने वाले खर्च आपकी योजना को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। पिताजी की सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे मन बेहद खुश होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में जितना ज्यादा फोकस करेंगे, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी।

कन्या- आज अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान दें। आपकी कही हुई एक छोटी सी बात भी सामने वाले पर बड़ा असर डाल सकती है। माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा और वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम होंगी। सेहत का असर मेहनत पर पड़ सकता है, इसलिए लापरवाही न करें। आप काफी समय से घूमने का प्लान बना रहे थे, तो आज उसके पूरा होने की संभावना है।

तुला- आज कोई अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। कारोबार में कोई बड़ी डील फायदेमंद हो सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चों को खुश करने के लिए उनके लिए कुछ नया खरीद सकते हैं या उनके साथ घूमने जा सकते हैं। सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने से सम्मान और पहचान बढ़ेगी। हालांकि, आज भावनाओं में बहने के बजाय दिमाग से फैसला लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक- आज अपनी बातों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। गलत समय पर कहा गया एक शब्द रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर फैसला न लें, वरना नुकसान हो सकता है। संतान की नौकरी को लेकर चल रही चिंता कम होने के संकेत हैं। मन से किया हुआ कोई वादा आज पूरा करना पड़ सकता है। परिवार में तालमेल की कमी से बहस हो सकती है, इसलिए शांत रहकर बात संभालें। सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है।

धनु- आज अचानक कोई लाभ मिल सकता है और ऐसी चीज हाथ लग सकती है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। हालांकि, अपनी बातों पर संयम रखना जरूरी होगा। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन से खुशियों का माहौल बनेगा। जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आप खुद को पहले से ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और अपनी क्षमता के बल पर आप उसे अच्छी तरह निभाएंगे। इससे प्रमोशन की राह भी खुल सकती है।

मकर- आज आपकी मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बनेगी। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी और साथी के साथ खूबसूरत पल बिताने का मौका मिलेगा। संतान की पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण फैसले में दोस्तों की सलाह आपके लिए उपयोगी रहेगी।

कुंभ- आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल नजर आ रहा है। लंबे समय से अटका पैसा वापस मिलने की अच्छी संभावना है। किसी रिश्तेदार के घर शुभ कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि चोट लगने की आशंका बन रही है।

मीन- आज परिवार के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा। आपके दिमाग में कई नए विचार आएंगे और अगर उन्हें सही समय पर अमल में लाया, तो अच्छा फायदा मिल सकता है। सेहत को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, इसलिए शरीर के संकेतों को गंभीरता से लें। कोई पुराना अटका काम आज पूरा हो सकता है।

शब्दजाल - 8357

शब्दजाल में बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, तिरछे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं 10 शहरों के नाम ढूंढिए, शब्द छुपे हैं। [illegible]

मेलघाट, खाईड़, रणथंभौर, हाथीपुर, कान्हा, पलामू, तुंगभद्रा, सरिस्का, दुधवा, इंद्रावती

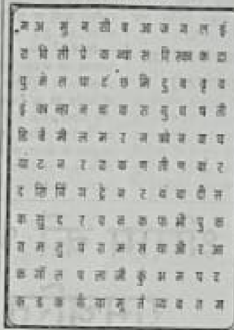

शब्दजाल - 8356 का हल

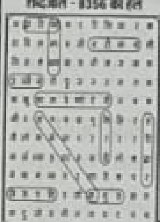

किस्मत वर्ग पहेली - 7301

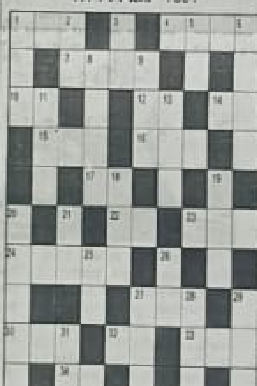

ऊपर से नीचे - [illegible]

बाएं से दाएं- [illegible]

किस्मत वर्ग पहेली - 7300

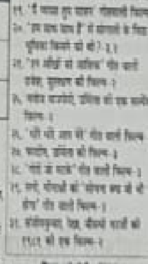

दैनिक पंचांग

[illegible]

प्रसंगवश: राष्ट्रपति का बड़प्पन

[illegible]

सुडोकू सवाल - 7610

3				8				9
		8	6		9	5		
6	5			4			7	1
	4						2	
1	2			6			9	8
		6	4		5	8		
9				1				7

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति के एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रहे।
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
■ पहेली का केवल एक ही हल है।

सुडोकू सवाल - 7609 का हल

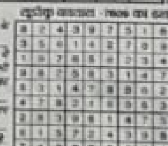

शब्द पहेली - 8825

बाएँ से दाएँ

1. हट,जिद,धैर्य-4
4. आयुर्वेद के जनक-3
6. चीरा हुआ-2
7. तालाब(अंग्रेजी-2)
9. लैटिन करना -4
11. चोप,अनुभव-3
12. आसरा-3
13. ज्वालामुखी से निकला गर्म द्रव-2
14. अनाज पकने से पहले हरा- दाल बीज-2
15. नर मोक्ष करना-3
17. अनुमान लगाना-3
19. उदाहरण,बहुमान-4
21. गाथा,कहानी -2
23. जनश्रुति-2
24. विज्ञापन,प्रचार-3
25. राजा,सम्राट-4

ऊपर से नीचे

1. हकूक,आलपल्य-4
2. भाव,पराक्रम-2
3. बोलने का तरीका-3
4. अपेक्षित-3
5. आर्द्र,हुआ-2
8. गुनाह,अपराध-3
9. अटक-अटक कर बोलना-4
10. नजर,खुमार,नशा, घमंड-2
12. समाचार-4
15. अभिनेता,कप्तान-3
16. आनंद बोधक शब्द-2
18. सम्राट,राजा-4
19. ब्याह,परिहास-3
20. गुलाबजल-3
22. पराग,बड़ी चालें-2
23. हलवा,एक मिष्ठान-2

शब्द पहेली - 8824 का हल

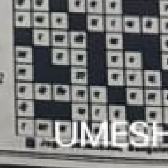

UMESH

वैज्ञानिक तरीके से होगा गंदे पानी का उपचार, नगर परिषद ने शुरू किया सर्वेक्षण

पद्मेश न्यूज। लांजी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत उपयोगिता जल प्रबंधन परियोजना के सफल क्रियान्वयन और नगर के विभिन्न स्थानों पर गंदे पानी के वैज्ञानिक तरीके से उपचार की दिशा में नगर परिषद लांजी ने पहल शुरू की है। इसी क्रम में 21 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर के पर्यावरण विशेषज्ञों और नगर परिषद की टीम ने नगर के विभिन्न वार्डों का संयुक्त तकनीकी एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान नगर के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता जल के प्रबंधन और उपचार की संभावनाओं का प्राथमिक अध्ययन किया गया। विशेषज्ञों ने गंदे पानी को वैज्ञानिक तकनीक से शोधित करने, व्यवस्थित रूप से साफ करने तथा उसके उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक बिंदुओं का अवलोकन किया। इस दौरान नीरी नागपुर के विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉ. विशेष रितेश विजय, अभियंता अभिषेक बिसारिया, अभियंता आकाश पटवा एवं अभियंता शोभित जैन के साथ नगर परिषद लांजी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मयूर वाहने, नोडल अधिकारी एवं उपयंत्री अमित नगपुरे, क्षेत्रीय अभियंता अंकुर बिसेन एवं विजय महोबिया उपस्थित रहे।

वैज्ञानिक आधार पर तैयार होगी कार्ययोजना

नगर परिषद के अनुसार सर्वेक्षण के आधार पर आगामी चरण में परियोजना की रूपरेखा एवं तकनीकी नक्शा तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही नगर में गंदे पानी के वैज्ञानिक शोधन एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था विकसित की जाएगी। सर्वे के दौरान मल-कीचड़ के उपचार तथा जैव शौचालयों की स्थापना से संबंधित कार्यों पर भी विशेषज्ञों और नगर परिषद की टीम के बीच चर्चा हुई। परियोजना के माध्यम से नगर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने, गंदे पानी का उचित प्रबंधन करने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। नगर परिषद लांजी ने बताया कि तकनीकी एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बाद विशेषज्ञों की अनुशंसा के आधार पर आगामी कार्ययोजना तैयार कर परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा।

सेन समाज ने नंदू दादा की पुण्यतिथि पर पौधारोपण कर दी श्रद्धांजलि

पद्मेश न्यूज। लांजी। सेन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश राज्य केश शिल्पी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा) स्वर्गीय नंदकिशोर वर्मा उर्फ 'नंदू दादा' की प्रथम पुण्यतिथि पर शुक्रवार को लांजी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेन शक्ति महा संगठन एवं सेन समाज विधानसभा लांजी के तत्वावधान में मां काली मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में समाजबंधुओं ने उनके सामाजिक योगदान को याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत संत शिरोमणि सेन जी महाराज की पूजा-अर्चना एवं आरती के साथ हुई। इसके बाद स्वर्गीय नंदकिशोर वर्मा के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित समाजबंधुओं ने उनके जीवन, सामाजिक सक्रियता और सेन समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को याद किया

स्वर्गीय नंदकिशोर वर्मा सेन समाज के प्रमुख सामाजिक नेताओं में शामिल रहे। वे भारतीय सेन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मध्यप्रदेश राज्य केश शिल्पी बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। समाज से जुड़े कार्यक्रमों में वे केश शिल्पियों के हित, सामाजिक एकजुटता और समाज के विकास की आवाज प्रमुखता से उठाते रहे। उन्होंने केश शिल्पी बोर्ड के माध्यम से समाज के लोगों को शासन की योजनाओं से जोड़ने तथा सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए लगातार प्रयास किया। इसी सामाजिक भावना को आगे बढ़ाते हुए उनकी पुण्यतिथि पर 'एक पेड़ नंदू दादा के नाम' अभियान के तहत मां काली मंदिर के गेट तथा सेन चौक में प्रस्तावित सेन मंदिर की भूमि पर पौधारोपण किया गया तथा समाजबंधुओं ने लगाए गए पौधों की देखभाल का संकल्प लेते हुए इसे नंदू दादा की स्मृति को जीवंत रखने का सार्थक प्रयास बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संतोष श्रीवास, प्रतिनिधि केश शिल्पी बोर्ड मध्यप्रदेश शासन, नगर परिषद लांजी एवं जबलपुर संभाग अध्यक्ष सेन शक्ति महा संगठन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष लक्ष्मण श्रीवास ने की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष राकेश श्रीवास, युवा जिला अध्यक्ष शुभम श्रीवास, शिवम श्रीवास, दुर्गा श्रीवास, कमलेश चांडिल, भोला श्रीवास, छोटा श्रीवास, बाबू श्रीवास सहित बड़ी संख्या में सेन समाज के महिला-पुरुष एवं समाजबंधु उपस्थित रहे। अंत में विधानसभा अध्यक्ष राकेश श्रीवास ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी समाजबंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

मिशन शक्ति के तहत महिलाओं व बच्चों को किया जागरूक

देवलगांव में सुरक्षा, अधिकार, कानूनी प्रावधान और शासकीय योजनाओं की दी जानकारी

पद्मेश न्यूज। लांजी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत विकासखंड लांजी के ग्राम देवलगांव स्थित प्राथमिक शाला आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक-01 एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जन-जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।कलेक्टर सत्यम कुमार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेन्द्र कुमार सुंद्रियाल के मार्गदर्शन तथा वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक रचना चौधरी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, महिला श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।

कानूनी अधिकारों और सहायता सेवाओं की दी जानकारी

कार्यशाला में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181, वन स्टॉप सेंटर, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सहित महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। विद्यालय की छात्राओं को साइबर सुरक्षा, बाल अधिकार तथा हिंसा या शोषण की स्थिति में उपलब्ध सहायता सेवाओं के प्रति भी जागरूक किया गया। वक्ताओं ने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या शोषण की स्थिति में चुप रहने के बजाय उपलब्ध सहायता सेवाओं का उपयोग करना चाहिए।

स्वच्छता और संक्रमण से बचाव का संदेश

कार्यक्रम के दौरान वर्षा ऋतु में होने वाले संक्रमण से बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा आसपास साफ-सफाई बनाए रखने के संबंध में भी जानकारी दी गई। महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यशाला में धीरज वहाने, पैरा लीगल वॉलेंटियर, सुश्री हाफिजा मिर्जा, समाज सेविका, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और शासन की सहायता योजनाओं का लाभ उठाने का संदेश दिया गया।

श्रीराम की भक्ति में डूबा पालडोंगरी, अखण्ड रामचरित मानस पाठ में सेवा का संदेश

पद्मेश न्यूज। लांजी। लांजी-किरनापुर क्षेत्र के ग्राम पालडोंगरी में अखण्ड श्रीरामचरित मानस पाठ समिति, ग्राम समितियों एवं अभिनंदन लाइफ फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित अखण्ड श्रीरामचरित मानस पाठ का 20 अगस्त को शुभारंभ हुआ, जिसका 21 अगस्त को विश्रांति के साथ समापन किया गया। धार्मिक आयोजन के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती, नशामुक्ति एवं सामाजिक जागरूकता से जुड़ी गतिविधियां भी आयोजित की गईं। राम यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने घरों के सामने दीप सजाकर भगवान श्रीराम, माता सीता एवं लक्ष्मण का श्रद्धापूर्वक स्वागत किया। बैंड-बाजे और भजनों के साथ निकली यात्रा में ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बना। आयोजन के दौरान पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। ग्रामीणों को जैविक खेती, प्लास्टिक मुक्त अभियान और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया गया। योग शिविर में लोगों को नियमित योग एवं प्राणायाम अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। महिलाओं ने हल्दी-कुमकुम कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समरसता एवं संस्कार का संदेश दिया, वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा, अनुशासन और संस्कारों की सीख दी।

स्वास्थ्य शिविर में 295 ग्रामीणों की जांच

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में सुप्रीम हॉस्पिटल गोंदिया की टीम द्वारा 295 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं। वहीं मोतियाबिंद नेत्र जांच शिविर में 153 लोगों की जांच की गई, जिनमें 65 लोगों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। आयोजकों ने कहा कि धार्मिक आयोजनों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और समाज सेवा से जोड़कर समाज के सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ना उद्देश्य है। सावन माह में क्षेत्र के 30 गांवों में अखण्ड श्रीरामचरित मानस पाठ एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

बड़गांव में भी अखण्ड पाठ शुरू

इसी क्रम में ग्राम बड़गांव (म) में 21 अगस्त को संगीतमय अखण्ड श्रीरामचरित मानस पाठ का शुभारंभ हुआ। इसका समापन 22 अगस्त को स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क मोतियाबिंद जांच, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान एवं महाप्रसाद के साथ किया जाएगा।

असाटी समाज बालाघाट द्वारा संगीतमय पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक सम्पन्न

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। असाटी समाज बालाघाट की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए असाटी वैश्य विकास समिति बालाघाट द्वारा नए श्री राम मंदिर में भव्य एवं संगीतमय पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक का आयोजन श्रद्धा, आस्था एवं भक्तिभाव के साथ किया गया। धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में समाजजनों ने सहभागिता की और भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सभी के सुख-समृद्धि, शांति एवं मंगलमय जीवन की कामना की।कार्यक्रम में शीतला रामायण भजन मंडल 'भोले के दीवाने', आमगांव द्वारा मधुर एवं संगीतमय भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। भजनों, शिव स्तुति एवं भगवान भोलेनाथ के जयकारों से पूरा श्री राम मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रुद्राभिषेक किया और भगवान शिव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की।

भगवान भोलेनाथ की भव्य आरती के साथ हुआ कार्यक्रम का समापन

रुद्राभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सभी परिवारों में सुख-शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सद्भाव एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं एवं वरिष्ठजनों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही।कार्यक्रम के समापन अवसर पर भगवान भोलेनाथ की भव्य आरती की गई। इसके पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। संपूर्ण आयोजन श्रद्धा, भक्ति, संस्कार एवं सामाजिक एकता का सुंदर उदाहरण रहा।असाटी वैश्य विकास समिति बालाघाट ने आयोजन में सहभागिता करने वाले सभी समाजजनों, शीतला रामायण भजन मंडल 'भोले के दीवाने', आमगांव के सदस्यों एवं आयोजन में सहयोग प्रदान करने वाले सभी सहयोगियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया

नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ाना भी प्रमुख उद्देश्य- श्री असाटी

असाटी वैश्य विकास समिति बालाघाट के अध्यक्ष संजय लखनलाल असाटी ने बताया कि हमारे समाज की पहचान केवल सामाजिक एकता से नहीं, बल्कि हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक मूल्यों से भी है। ऐसे धार्मिक आयोजन समाज को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य करते हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना हमें सेवा, समर्पण, संयम और सद्भाव की प्रेरणा देती है। हमारा प्रयास है कि धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से नई पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ा जाए।उन्होंने बताया कि समाज के सभी वर्गों की सहभागिता एवं सहयोग से आयोजित इस प्रकार के आयोजन आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता को और मजबूत करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी समाजजनों के प्रति आभार व्यक्त किया।

दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में तीन घायल- एक जिला अस्पताल में भर्ती

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। रूपझर थाना क्षेत्र की सोनगुड्डा पुलिस चौकी अंतर्गत डाबरी रोड पर ग्राम कोद्दापार के पास शुक्रवार को दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में तीन लोग घायल हो गए। इनमें गंभीर रूप से घायल शिवकुमार पिता मोतीराम टेकाम 35 ग्राम कोद्दापार निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उसके पिता मोतीराम टेकाम 56 और दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार सुखचंद पिता कुंजीलाल धुर्वे 35 निवासी ग्राम बकरकट्टा थाना लांजी निवासी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवकुमार अपने माता-पिता के साथ खेती-किसानी करता है। 21 अगस्त सुबह शिवकुमार अपनी मां सोनवती और पिता मोतीराम के साथ मोटरसाइकिल से इलाज कराने बिठली गया था। दोपहर में इलाज कराने के बाद तीनों मोटरसाइकिल से अपने गांव कोद्दापार लौट रहे थे। इसी दौरान सोनगुड्डा के आगे डाबरी रोड पर ग्राम कोद्दापार के पास सुखचंद धुर्वे सहित तीन युवक दूसरी मोटरसाइकिल से सोनगुड्डा की ओर जा रहे थे। दोनों मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर हो गई।दुर्घटना में शिवकुमार उसके पिता मोतीराम और दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार सुखचंद घायल हो गए। सुखचंद के साथ मौजूद दो युवक बिसन टेकाम और बाजीराव धुर्वे दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गए।सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचाया गया। गंभीर चोटों के कारण शिवकुमार को जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है, जबकि मोतीराम और सुखचंद को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मामले की जांच सोनगुड्डा पुलिस द्वारा की जा रही है।

ग्वालियर, सतना नगर निगम के कमिश्नर बदले

32 आईएएस सहित चार राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले

भोपाल। मोहन सरकार ने प्रदेश में आईएएस अफसरों की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2016 से 2024 बैच तक के अधिकारियों के तबादले किए हैं। 10 जिलों के सीईओ जिला पंचायत बदले गए हैं। इसके साथ ही ग्वालियर और सतना नगर निगम के आयुक्तों का भी तबादला किया गया है। तबादला आदेश में कई अधिकारियों को सीईओ जिला पंचायत, अपर कलेक्टर और एसडीएम की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कुछ अधिकारियों को राज्य शासन के विभिन्न विभागों में उप सचिव और नगर निगमों में आयुक्त व अपर आयुक्त बनाया गया है।

2018 बैच के अभिषेक चौधरी को सीईओ जिला पंचायत धार से नगर निगम ग्वालियर का आयुक्त बनाया गया है। वहीं ग्वालियर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय को सीईओ जिला पंचायत सिंगरौली की जिम्मेदारी दी गई है। 2019 बैच के डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा को सीईओ जिला पंचायत खंडवा से नगर निगम सतना का आयुक्त बनाया गया है। उन्हें सीईओ स्मार्ट सिटी सतना का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

इन जिलों के जिला पंचायत सीईओ बदले

सागर के जगदीश कुमार गोमे, सिंगरौली के संघ प्रिय, देवास के नवीन कुमार धुर्वे, सीधी के सौम्या आनंद, बड़वानी के अर्पित गुप्ता, बालाघाट की तनुश्री मीणा, श्योपुर के कार्तिकेय जायसवाल, टीकमगढ़ के विशाल धाकड़ और खंडवा के ईश्वर्य वर्मा को बदला गया है। वहीं धार के अभिषेक चौधरी का तबादला नगर निगम ग्वालियर में आयुक्त के पद पर किया गया है। वहीं 2016 बैच की संजना जैन को अपर कलेक्टर मैहर से उप सचिव, जल संसाधन विभाग बनाया गया है। जगदीश कुमार गोमे को सीईओ जिला पंचायत सिंगरौली से सीईओ जिला पंचायत सागर भेजा गया है। 2018 बैच में अक्षय कुमार तेजपाल को सीईओ जिला पंचायत दतिया से अपर आयुक्त, नगर निगम भोपाल बनाया गया है। ज्योति शर्मा को सीईओ जिला पंचायत देवास से उप सचिव और अंजली जोसेफ जोनाथन को सीईओ जिला पंचायत हरदा से उप सचिव, लोक निर्माण विभाग बनाया गया है।

2019-2021 बैच में भी फेरबदल

2019 बैच की काजल जावला को सीईओ जिला पंचायत बड़वानी से अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल भेजा गया है। अनिल कुमार डामोर को अपर कलेक्टर विदिशा से उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग बनाया गया है। 2020 बैच के अभिषेक सराफ को सीईओ जिला पंचायत बालाघाट से अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल भेजा गया है। वहीं विवेक के.डी. को सीईओ जिला पंचायत सागर से सीईओ, जबलपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया है। 2021 बैच की सौम्या आनंद को सीईओ जिला पंचायत सीधी की जिम्मेदारी दी गई है।

2022 बैच के अफसर भी बदले

2022 बैच के ईश्वर्य वर्मा को सीईओ जिला पंचायत खंडवा, कार्तिकेय जायसवाल को सीईओ जिला पंचायत श्योपुर और विशाल धाकड़ को सीईओ जिला पंचायत टीकमगढ़ बनाया गया है। आशीष को अपर आयुक्त, नगर निगम इंदौर की जिम्मेदारी दी गई है। सोनाली देव को एसडीएम बिछिया से उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन बनाया गया है। वहीं अर्पित गुप्ता को एसडीएम बैहर से सीईओ जिला पंचायत बड़वानी और तनुश्री मीणा को एसडीएम पेटलावद से सीईओ जिला पंचायत बालाघाट बनाया गया है।

2024 बैच के 9 सहायक कलेक्टर अब एसडीएम

2024 बैच के कई सहायक कलेक्टरों को एसडीएम की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष कुमार बीना, अनिकेत शांडिल्य बैहर, आकाश अग्रवाल मझौली, पाटिल आशीष अशोक कुक्षी, सुशील श्रीकृष्ण श्रीराम देवसर, कुलदीप पटेल बिछिया, जमादार फरहान इरफान शाहपुरा, ठाकुर ॠत्विक विजय बिजावर, नवकीरण कौर उदयपुरा और श्रद्धा शुक्ला को अपर कलेक्टर खंडवा बनाया गया है। 2022 बैच की श्रद्धा शुक्ला को फिलहाल पदस्थापना की प्रतीक्षा में रखते हुए अपर कलेक्टर, जिला खंडवा के पद पर पदस्थ किया गया है। आदेश में उनके लिए कनिष्ठ वेतनमान का भी उल्लेख किया गया है।

आरक्षक ने एसपी पर लगाये अवैध वसूली के आरोप

- पहले विधायक की शिकोयत पर किया गया था लाइन अटैच

- बाद में विधायक को चेतावनी देने पर एसपी ने किया निलंबित

भोपाल/ भिंड। भिंड के मिहोना थाने में चालक के पद पर पदस्थ रहे आरक्षक आलोक राठौड़ ने मंगलवार-बुधवार की रात लहार विधायक को चेतावनी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। मामला सामने आने के बाद एसपी सूरज कुमार वर्मा ने बुधवार शाम आरक्षक को निलंबित कर दिया। इसके कुछ घंटे बाद रात करीब 9 बजे आरक्षक ने फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए अपने निलंबन के लिए लहार एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी को जिम्मेदार बताने के साथ ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए है। जानकारी के अनुसार आरक्षक के खिलाफ लगातार शराब के नशे में रहने और लोगों से अभद्र व्यवहार करने की शिकायतें विधायक अंबरीश शर्मा और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची थी। शिकायतों के बाद 14 अगस्त को आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया गया था। इसके बाद उसने लहार विधायक को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। पोस्ट ठाकुर आदित्य नाम की आईडी से शेयर हुई थी, लेकिन उस पर आरक्षक के फोटो लगे थे। जांच के बाद एसपी ने उसे निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद आरक्षक ने दूसरी पोस्ट में लहार एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी पर थाना प्रभारियों से लेन-देन के आरोप लगाए। आरक्षक ने अपनी पोस्ट के साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें लहार टीआई शिवसिंह यादव को 10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाने की जानकारी दिखाई गई थी। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। वहीं एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी का कहना है की आरक्षक ने रात में नशे की हालत में इस तरह की पोस्ट डाली होगी। वहीं टीआई का कहना है कि वह आरक्षक आलोक राठौड़ को नही जानते। सारे आरोप गलत हैं और वह मामले को लेकर उचित कार्रवाई करेगें।

स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदारों पर 54 करोड़ के घोटाले का आरोप, पीएफ राशि नहीं की जमा

भोपाल। स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों के नाम पर करीब 54 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है, चार ठेकेदार कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन से काटी गई पीएफ/ईपीएफ राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में जमा नहीं की। इससे कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा अधिकार प्रभावित हुए हैं.सरकारी खजाने से राशि लेकर पीएफ खाते पर जमा नहीं की है। मध्यप्रदेश में आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पहले भी एजेंसियों पर वेतन भुगतान में देरी तथा ईपीएफ-ईएसआईसी का लाभ नहीं देने के आरोप लगाए हैं। जबलपुर में कर्मचारियों ने सिग्मा इंफोटेक भोपाल और प्रकाश सिक्योरिटी ग्वालियर के खिलाफ ऐसी शिकायतें दर्ज कराई थीं। 54 करोड़ रुपये के आंकड़े और कथित चारों कंपनियों के नाम की स्वतंत्र आधिकारिक जाँच की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।जांच के बाद ही जिम्मेदार कंपनियों और अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट होगी।

सीहोर में खाद वितरण व्यवस्था 21 दिन में तीसरा बदलाव

-एक बार फिर ई-टोकन व्यवस्था हुई अनिवार्य

भोपाल। सीहोर सहित पूरे मध्य प्रदेश में खाद वितरण प्रणाली में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया गया है। पिछले 21 दिनों में कृषि विभाग ने तीन बार अपने आदेशों में संशोधन करते हुए अब ई-विकास 2.0 वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली के तहत ई-टोकन व्यवस्था को फिर से अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले, 29 जुलाई को किसानों के उग्र विरोध के बाद ई-टोकन की अनिवार्यता समाप्त कर हाइब्रिड मोड लागू किया गया था।

कृषि सचिव निशांत वरवड़े द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, विभाग का दावा है कि नए पोर्टल को किसानों के सुझावों पर पूरी तरह री-डिजाइन किया गया है, ताकि प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुलभ और त्वरित हो सके। किसानों को कुछ राहतें भी दी गई हैं, जैसे अब अनुशंसित मात्रा से अधिक खाद मांगने पर 50 शब्दों का लिखित कारण नहीं देना होगा, बल्कि ड्रॉप-डाउन मेन्यू से विकल्प चुनना होगा। साथ ही, मार्कफेड केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए प्रतिदिन 200 से अधिक टोकन जनरेट करने की सुविधा दी गई है।

यहां बताते चलें कि इस पूरे घटनाक्रम में 1 अप्रैल को ई-टोकन अनिवार्य हुआ, 29 जुलाई को अनिवार्यता खत्म हुई, 14 अगस्त को बिक्री पूरी तरह रोकी गई और 19 अगस्त को नए पोर्टल के साथ ई-टोकन फिर अनिवार्य कर दिया गया।

उमरिया में पानी पर बनेगा 220 मेगावॉट का सोलर प्लांट

भोपाल। मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा के विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। उमरिया जिले में स्थित संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन के कूलिंग पॉड में 220 मेगावॉट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। करीब 1,500 करोड़ रूपए की लागत वाली इस परियोजना को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की तैयारी है। इससे बनने वाली बिजली प्रदेश के नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे बिजली खर्च का आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

परियोजना के लिए नगरीय विकास कंपनी ने मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को नोडल एजेंसी बनाया है। अब जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के अनुसार फ्लोटिंग सोलर संयंत्र को लेकर तैयारियां चल रही हैं और जल्द टेंडर जारी किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के नगरीय निकायों में करीब 300 मेगावॉट बिजली की मांग रहती है। ऐसे में उमरिया की परियोजना से पैदा होने वाली बिजली निकायों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

ओंकारेश्वर के बाद दूसरी बड़ी परियोजना

मध्यप्रदेश पहले ही ओंकारेश्वर बांध पर देश की बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं में से एक विकसित कर चुका है। वहां पानी की सतह पर सोलर पैनल लगाकर करीब 275 मेगावॉट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अब उमरिया में 220 मेगावॉट की नई परियोजना शुरू होने से प्रदेश में पानी की सतह पर सौर ऊर्जा उत्पादन का दायरा और बढ़ेगा। फ्लोटिंग सोलर प्लांट में जमीन पर सोलर पैनल लगाने के बजाय पानी की सतह पर विशेष फ्लोटर्स लगाए जाते हैं। इन फ्लोटर्स को आपस में जोडक़र प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है और उस पर सोलर पैनल स्थापित किए जाते हैं। उत्पादित बिजली को केबल के माध्यम से ग्रिड तक पहुंचाया जाता है।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने रखा पेन डाउन

भोपाल। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में चयनित होने के बाद भी नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों के लोक शिक्षण आयुक्त के कक्ष में प्रवेश करने की घटना के विरोध में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने दो घंटे पेन डाउन रखा। इस दौरान शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय में कर्मचारियों ने काम नहीं किया। दो घंटे बाद कर्मचारी काम पर लौट आए। इधर, राज्य शिक्षा केंद्र में भी कर्मचारियों ने आयुक्त के कक्ष में प्रवेश की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने घटना पर नाराजगी जताते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं, दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। चयनित शिक्षक नीलम पार्क में जुटे हैं और पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है।

आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह के कार्यालय में गुरुवार शाम प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद नियुक्ति से वंचित उम्मीदवारों के एक समूह ने जबरन घुसकर नारेबाजी की थी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको आयुक्त के कक्ष से बाहर निकाला था। इसके बाद शिक्षक और कर्मचारी संगठनों ने इस घटना का विरोध करते हुए आज से आंदोलन और पेन डाउन करने की चेतावनी दी थी। शुक्रवार को राज्य शिक्षा केंद्र के बाहर संविदा कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इनके द्वारा आयुक्त के कक्ष में घुसने की कोशिश की निंदा करते हुए कार्यवाही की मांग की गई। मोर्चा के अध्यक्ष रमेश राठौर और अन्य कर्मचारियों ने इस तरह की घटनाओं की स्थिति में सरकारी कामकाज पर असर पडने़ की बात कही। राठौर ने कहा कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी आज प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं। अहिंसात्मक तरीके से लोग अपनी बात रख सकते हैं लेकिन इसके लिए हिंसा का रास्ता अपनाना कतई उचित नहीं है। अल्पवेतन भोगी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार साकल्ले ने भी इसके विरोध में साथी कर्मचारियों को लेकर प्रदर्शन किया है। आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय के कर्मचारी नेता मुकेश शर्मा ने बताया कि चूंकि कल घटना के बाद प्रदर्शन करने वाले चयनित शिक्षकों ने आयुक्त से माफी मांग ली थी। इसलिए आज दो घंटे तक पेन डाउन रखने के बाद सभी काम पर लौट आए हैं ताकि शासकीय काम काज प्रभावित न होने पाए।

नीलम पार्क में प्रदर्शन जारी

दूसरी ओर शिक्षक चयन परीक्षा में वर्ग 2 और वर्ग तीन के पदों में वृद्धि को लेकर नीलम पार्क में प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां आंदोलनरत चयनित शिक्षकों द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग से पदों में वृद्धि कर नौकरी देने की मांग की जा रही है। इनका कहना है कि लाखों पद रिक्त हैं लेकिन विभाग पद वृद्धि न करके चयन परीक्षा में पास होने के बाद भी नियुक्ति नहीं दे रहा है।

नगर निगम की चलित कोर्ट ने रेस्टोरेंट और बार में की कार्रवाई

भोपाल । भोपाल नगर निगम की म्युनिसिपल कोर्ट ने शुक्रवार को बंसल वन स्थित रेस्टोरेंट और बार में बड़ी कार्रवाई की। मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) तरुणेंद्र प्रताप सिंह ने रेस्टोरेंट-बार के किचन में जाकर लोगों को दिए जाने वाले फूड को देखा। जब जांच की गई तो कई जगहों पर कोल्ड्रिंक्स एक्सपायर मिले। वेन और नॉवेज खाना फ्रीज में एकसाथ रखा था। टीम ने ऑन स्पॉट जुर्माना किया। चलित न्यायालय ने दोपहर 1.30 बजे से कार्रवाई शुरू की, जो करीब दो घंटे तक चलती रही। इस दौरान फर्जी कैफे, रोमियो लेन, फ्लाइंग सोसर, रास्ता, माय बार, आयबरी, कव्वाली, संकल्प रेस्टोरेंट और बार में टीम पहुंची।

सरकारी स्कूलों की बदहाली को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस

भोपाल। मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने मोहन सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। पार्टी अब सरकारी स्कूलों की जमीनी स्थिति को अभियान का प्रमुख मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सरकारी स्कूलों का जायजा लेने और वहां की स्थिति को सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदेशभर के स्कूल-कॉलेजों में पहुंचेंगे। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की जाएगी।

जीतू पटवारी ने बताया कि शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस अब संभाग स्तर पर साइकिल रैलियां निकालेगी। इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा के बाद अब प्रदेश के सभी संभागों में साइक्लोथॉन आयोजित करने की तैयारी है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। इन रैलियों के जरिए कांग्रेस सरकारी स्कूलों की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता और सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाएगी। पार्टी का दावा है कि अभियान के दौरान सामने आने वाली समस्याओं और स्कूलों की स्थिति को सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर पर सामने रखा जाएगा।

पंचायत से ब्लॉक स्तर तक जिम्मेदारी

कांग्रेस ने इस अभियान को केवल प्रदेश और जिला स्तर तक सीमित नहीं रखने की रणनीति बनाई है। पार्टी के पंचायत कमेटी, ब्लॉक और मंडल स्तर के पदाधिकारियों को सरकारी स्कूलों तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं से स्कूलों में जाकर वहां की वास्तविक स्थिति देखने और उसे दस्तावेज के रूप में सामने लाने को कहा गया है। कांग्रेस का उद्देश्य सरकारी दावों और स्कूलों की जमीनी स्थिति के बीच अंतर को उजागर करना है। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और इसमें व्यापक सुधार की जरूरत है। उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। इसमें स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए काम, उपलब्धियां और कमियां सार्वजनिक की जाएं।

कैलारस शक्कर मिल दोबारा शुरू कराने की मांग

भोपाल। मुरैना जिले के कैलारस शक्कर कारखाने को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर जौरा से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय का 15 अगस्त से आमरण अनशन सातवें दिन की सुबह भी जारी रहा। विधायक के इस आंदोलन को प्रदेशभर से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल रहा है। जानकारी के अनुसार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी कैलारस जाकर अनशन में शामिल हो रहे हैं।

कांग्रेस विधायक के आमरण अनशन के बीच, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने भोपाल में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने कारखाने को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया और भविष्य की योजना सामने रखी है। उन्होंने दावा किया कि कारखाना शुरू होने से गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी और

क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कृषि मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कारखाने की जमीन का उपयोग उद्योगों की स्थापना और रोजगार बढ़ाने के लिए करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद इसे एमएसएमई विभाग को

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में किताबों का संकट

भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नया शिक्षण सत्र शुरू हुए चार महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन 15 लाख विद्यार्थियों के लिए जरूरी 65 लाख किताबों की छपाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है। कक्षा 5वीं के सभी विषयों और 7वीं की गणित पार्ट-2 व सामाजिक विज्ञान पार्ट-2 (हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू माध्यम) की किताबें अटकी हुई हैं।

राज्य शिक्षा केंद्र (आरएसके) ने मई 2026 (संभवत: 2023) में ही किताबों की मांग भेज दी थी और मप्र पाठ्यपुस्तक निगम (टीबीसी) ने 17 जून को छपाई के टेंडर भी जारी किए थे। हालांकि, तकनीकी बिड खुलने के बाद फाइनेंशियल बिड और वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो सका है। अधिकारियों के अनुसार, यदि वर्क ऑर्डर अब भी जारी होता है तो छपाई में दो महीने और वितरण में एक महीने का समय लगेगा, जिसका अर्थ है कि छात्रों को किताबें नवंबर से पहले मिलना मुश्किल है।

इस देरी का असर अगले शिक्षण सत्र पर भी पड़ने की आशंका है, जहां अगले सत्र की किताबें भी सितंबर 2027 (संभवत: 2024 या 2025) तक ही विद्यार्थियों को मिल पाने की संभावना जताई जा रही है। टीबीसी हर साल लगभग 8 से 9 करोड़ किताबें छापता है, जिस पर करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च आता है।

विधानसभा सचिवालय में भर्ती पर बड़ा बदलाव

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय में पिछले करीब तीन दशकों से विवादों में रही नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी है। अवर सचिव, उप सचिव और अतिरिक्त सचिव स्तर के महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती अब मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) के माध्यम से कराने पर विचार किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सचिवालय में प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रमुख पदों की भर्ती पीएससी के जरिए कराने पर विचार किया जा रहा है।

दरअसल, वर्ष 1993 से अब तक विधानसभा सचिवालय में बाबू से लेकर अपर सचिव और सुरक्षा अधिकारी तक की नियुक्तियां और पदोन्नतियां कई बार विवादों में रही हैं। आरोप लगते रहे हैं कि कुछ मामलों में निर्धारित नियमों और योग्यता को दरकिनार कर लोगों को नियुक्ति और पदोन्नति का लाभ दिया गया। बैकडोर एंट्री के अलावा डेप्युटेशन, अनिवार्य अर्हता के बिना पदोन्नति और क्षेत्रवाद जैसे आरोप भी समय-समय पर सामने आते रहे हैं।

तीन दशक में उठे कई सवाल

श्रीनिवास तिवारी के कार्यकाल में 1993 से 2003 के बीच नियुक्तियों और पदोन्नतियों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद सामने आए। सत्यनारायण शर्मा की नियुक्ति और कुछ ही महीनों में बाबू से अंडर सेक्रेटरी बनाए जाने पर सवाल उठे। इसी तरह सब-इंजीनियर रमेश तिवारी और वेयरहाउसिंग विभाग से आए देवेंद्र तिवारी को सीधे सहायक यंत्री बनाए जाने का मामला भी चर्चा में रहा। अस्थायी नियुक्ति और डेप्युटेशन के जरिए 25 से अधिक लोगों के समायोजन का मामला जांच, एफआईआर और बर्खास्तगी तक पहुंचा। ईश्वरदास रोहाणी के कार्यकाल में स्टेनो और सुरक्षा गार्डों की भर्ती में नियमों की अनदेखी के आरोप लगे। वहीं डॉ. सीतासरन शर्मा के कार्यकाल में सीधी भर्ती की प्रक्रिया कानूनी विवादों और अड़चनों में फंसी रही। गिरीश गौतम के कार्यकाल में रिश्तेदारों और करीबियों की नियुक्ति के आरोप सामने आए। पुष्पेंद्र गौतम सहित कुछ नियुक्तियों और पदोन्नतियों से जुड़े मामले हाई कोर्ट तक पहुंचे।

दैनिक वेतनभोगियों को भी मिला स्थायी लाभ

विधानसभा सचिवालय में बड़ी संख्या में दैनिक वेतनभोगियों को पहले छह-छह महीने की अवधि के लिए रखा गया। बाद में इनमें से कई को स्थायी कर दिया गया। इनमें से कुछ कर्मचारी पदोन्नति पाते-पाते अतिरिक्त सचिव जैसे वरिष्ठ पदों तक पहुंच गए। अब पीएससी के माध्यम से भर्ती की व्यवस्था लागू होने पर ऐसी नियुक्तियों पर रोक लगने की उम्मीद है। इससे चयन प्रक्रिया अधिक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी हो सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय नियमों में बदलाव और विधानसभा सचिवालय की भर्ती व्यवस्था में संशोधन के बाद ही स्पष्ट होगा।

आयुष्मान का कार्ड है, अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर नही

भोपाल। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का अधिकार तो मिला है, लेकिन हकीकत यह है कि इलाज देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं हैं। नतीजा यह है कि आदिवासी अंचलों के मरीजों को स्थानीय अस्पतालों में उपचार नहीं मिल पा रहा और उन्हें जिला अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों का रुख करना पड़ रहा है। इससे जिला अस्पतालों पर मरीजों का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा हाल ही में तैयार किए गए आंकड़े बताते हैं कि आदिवासी विकासखंडों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी बनी हुई है। यहां 684 स्वीकृत विशेषज्ञ पदों में से केवल 68 पर ही डॉक्टर कार्यरत हैं, यानी लगभग 90 प्रतिशत पद खाली हैं। इनमें भी नियमित विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बेहद सीमित है।

सबसे ज्यादा प्रभावंत आदिवासी ब्लॉक

प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सिविल अस्पतालों में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, सर्जन और फिजिशियन जैसे विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं। लेकिन अधिकांश अस्पताल बिना विशेषज्ञों के ही संचालित हो रहे हैं। ऐसे में गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर करना मजबूरी बन गई है। दूर-दराज के वन क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए यह स्थिति इलाज में देरी और अतिरिक्त आर्थिक बोझ दोनों बढ़ा रही है।

चिकित्सा अधिकारियों की भी कमी

विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ-साथ चिकित्सा अधिकारियों की भी कमी बनी हुई है। आदिवासी ब्लॉकों में स्वीकृत पदों के मुकाबले बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। कार्यरत डॉक्टरों में भी नियमित नियुक्ति वाले कम हैं, जबकि बड़ी संख्या संविदा या बंधपत्र के तहत सेवाएं दे रही है।

मातृ स्वास्थ्य पर सबसे अधिक असर

विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी का सबसे गंभीर प्रभाव मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। स्त्री रोग विशेषज्ञ और एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध नहीं होने से कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सीजेरियन डिलीवरी संभव नहीं हो पा रही है। जटिल प्रसव के मामलों में गर्भवती महिलाओं को जिला अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है, जिससे कई बार उपचार में महत्वपूर्ण समय निकल जाता है।

आयुष्मान योजना का लाभ भी सीमित

आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और निजी संबद्ध अस्पतालों की कमी के कारण योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर आयुष्मान से संबद्ध निजी अस्पताल भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में कार्ड होने के बावजूद मरीजों के सामने इलाज का विकल्प सीमित रह जाता है।

दूसरा टेस्ट कोलंबो में 23 से, भारत ने यहां 9 टेस्ट खेले, 3 जीते, 2 हारे, 4 ड्रॉ

भारतीय टीम के सामने अब बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग SSC की कठिन चुनौती

कोलंबो,एजेंसी। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा व अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो के एसएससी मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम की कोशिश मेजबान का क्लीन स्वीप करने की होगी। पहला मैच 165 रन से जीतने वाली भारतीय टीम के लिए डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचने का रास्ता काफी कठिन है और उसे गॉल से पूरी तरह अलग ड्रॉ मैचों के लिए मशहूर सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान (एसएससी) में मेजबानी टीम के विरुद्ध कुछ अलग करना होगा।

गॉल की पिच पर स्पिनरों को अच्छी खासी मदद मिली थी जबकि एसएससी की पिच को बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग माना जाता है। एससीसी में एक जैसे बाउंस के कारण बल्लेबाजों को अच्छी शुरूआत मिलती है। समय बीतने के बावजूद पिच ज्यादा खराब नहीं होती और बड़े-बड़े स्कोर बनते हैं।

SSC में भारत का प्रदर्शन

भारत ने 2017 में यहां अपने पिछले मैच में 622 रन बनाकर पारी घोषित की थी। भारत ने वह मैच पारी व 53 रन से जीता था। भारत के लिए एससीसी का मैदान ड्रॉ की जमीन में तब्दील हो चुका है। उसने यहां नौ टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें तीन जीते, दो हारे हैं और चार ड्रॉ हुए हैं। भारत ने 2010 में यहां पारी में 707 रन भी बना हैं। एससीसी में कुल 46 टेस्ट हुए हैं जिसमें 14 ड्रॉ हुए हैं। ऐसे में मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल को विशेष रणनीति बनानी होगी। टीम शुक्रवार को यहां अभ्यास करेगी और उसके बाद पता चलेगा कि वह किसी संयोजन के साथ यहां उतरेगी।

कोलंबो में दूसरे टेस्ट के लिए संतुलित पिच तैयार होने की उम्मीद

भारतीय बल्लेबाजों की स्पिन के खिलाफ परेशानी का फायदा उठाने के लिए भले ही धूल भरी पिच तैयार करने का लालच हो लेकिन यहां दूसरे टेस्ट के लिए सिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब (एसएससी) का विकेट गॉल की पिच जैसा हो सकता है जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मौके मिले थे। श्रीलंकाई अधिकारियों का मानना है कि जरूरत से ज्यादा स्पिन की मददगार पिच तैयार करना उलटा पड़ सकता है। श्रीलंका क्रिकेट के एक अधिकारी ने हा, फिलहाल सोच यही है कि गॉल जैसी संतुलित पिच तैयार की जाए। श्रीलंका के पास चांडी (दिनेश चांदीमल), कुसाल (मेंडिस) और (पथुम) निसांका जैसे कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी नहीं हैं इसलिए हमें अपने युवा बल्लेबाजों को भी मौका देना होगा।

WTC का रास्ता

गॉल में जीत से भारत का जीत का प्रतिशत 48.15 से बढ़कर 53.33 हो गया है लेकिन फाइनल में पहुंचने के लिए उसे अभी भी बहुत काम करना है। अगले डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले कुल 36 टेस्ट मैच खेले जाने हैं जिसमें भारत को आठ खेलने हैं। पिछले डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंची टीमों में दक्षिण अफ्रीका का जीत का प्रतिशत 69.44 और ऑस्ट्रेलिया का 67.54 रहा था। अगर भारत बचे आठ में से छह मैच जीतता और दो हारता है तो उसका जीत का प्रतिशत 62.96 हो जाएगा। सात जीत और एक हार के बाद यह 68.52% रहेगा।

कमिल मिशारा और सहान अराचीगे श्रीलंका की टीम में शामिल

श्रीलंका ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए स्क्वॉड में बदलाव किया है। श्रीलंकाई टीम ने कमिल मिशारा और ऑलराउंडर सहान अराचीगे को टीम में जोड़ा है। कुसल मेंडिस और दिनेश चांदीमल आगामी मैच से बाहर हो गए हैं और पथुम निसंका भी पूरी तरह फिट नहीं हैं। श्रीलंका के कोच गैरी कर्स्टन ने कन्फर्म किया था कि मेंडिस और चांदीमल चोट के कारण अगला मैच नहीं खेल पाएंगे। सहान अराचीगे ने अभी तक श्रीलंका के लिए टेस्ट नहीं खेला है।

मानव सुथार से बोले पुजारा, आईपीएल के लिए अपनी शैली न बदलें

मुम्बई । दिग्गज टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने उभरते हुए स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है कि उसे सीमित ओवरों के क्रिकेट खासकर आईपीएल को देखते हुए अपनी गेंदबाजी की मूल ताकत और शैली में बदलाव नहीं करना चाहिए। साथ ही कहा कि उसे टेस्ट के लिए बचाकर रखना चाहिए।

सुधार ने श्रीलंका के खिलाफ पहले ही टेस्ट में कुल 10 विकेट लिए थे। ये श्रीलंका की धरती पर किसी भारतीय गेंदबाज का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। वह श्रीलंका में एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले केवल तीसरे भारतीय गेंदबाज बने। उन्होंने विदेशी टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, जो इससे पहले दिग्गज भारतीय स्पिनर बिशन सिंह बेदी के नाम था।

पुजारा ने कहा कि आजकल सभी युवा खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से छोटे फॉर्मेट और आईपीएल में खेलना चाहते हैं पर सुथार जैसे विशेष प्रतिभा वाले खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उन्होंने टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं को भी सलाह दी है कि सुथार को टेस्ट क्रिकेट के लिए ही रखा जाये। पुजारा ने कहा, उसे बचाकर रखने करने की कोशिश करें। हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि युवा खिलाड़ी छोटे प्रारुप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत को उसे टेस्ट प्रारुप के लिए बचाकर रखना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सुथार को आईपीएल में खेलने का मौका मिलता है तो उन्हें जरूर खेलना चाहिए, लेकिन अपनी ताकत से समझौता नहीं करना चाहिए।

गौरतलब है कि मानव सुथार को गुजरात टाइटंस ने 2025 की मेगा नीलामी में उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये पर खरीदा था। उन्होंने 2024 में आईपीएल में डेब्यू किया था पर सफल नहीं रहे। साल 2025 के सीजन में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, जबकि 2026 के सीजन में चार मैच खेलने के बाद उन्होंने तीन पारियों में गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने 34 के औसत और 11.33 की इकॉनमी रेट से केवल 2 विकेट लिए। उनका पहला विकेट आरसीबी के रजत पाटीदार का था और बाद में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के डेवॉल्ड ब्रेविस को भी आउट किया। हालांकि, पंजाब किंग्स के सूर्यांश शेडगे के खिलाफ एक ओवर में 27 रन खर्च करने के बाद उन्हें उस सीजन में दोबारा मौका नहीं मिला। पुजारा की यह सलाह सुथार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें सफेद गेंद के क्रिकेट में अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए अपनी मूल शैली से हटना पड़ सकता है।

गाले टेस्ट में सुथार के शानदार प्रदर्शन के बीच, रविंद्र जडेजा की भूमिका एक सहयोगी गेंदबाज जैसी दिखी, और कुलदीप यादव को भी ज्यादा सफलता नहीं मिली। ऐसे में सुथार ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह को मजबूत कर लिया है। अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह सफेद गेंद के क्रिकेट में भी अपनी उपयोगिता साबित करें।

रुट एक रन से विराट के विशिष्ट क्लब में शामिल नहीं हो पाये

हैडिंग्ले। इंग्लैंड के कप्तान जो रुट पाकिस्तान के खिलाफ जारी पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में केवल एक रन से विराट कोहली के विशिष्ट क्लब में आने से रह गये। रुट ने पाक के खिलाफ दूसरे दिन अपने टेस्ट करियर का 68वां अर्धशतक लगाते हुए 66 रन बनाये। अपनी इस पारी के दौरान जो रूट एक असाधारण उपलब्धि हासिल करने से मात्र एक रन से रह गए। इससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के एक विशिष्ट क्लब में शामिल होने का सुनहरा अवसर उनके हाथ से फिसल गया। पाकिस्तान के खिलाफ इस महत्वपूर्ण पारी में उन्हें तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) मिलाकर कम से कम 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अपना औसत 50 या उससे अधिक तक पहुंचाने के लिए 67 रन बनाने की आवश्यकता थी। रूट ने 112 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके लगाए, लेकिन 66 के निजी स्कोर पर आउट हो जाने के कारण उनका औसत 49.99 ही रह गया। उससे वे इस मील के पत्थर को छूने से महज एक रन से रह गए।

अभी ये यह उपलब्धि केवल फिलहाल टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के नाम है। कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में 52.71 के शानदार औसत के साथ शीर्ष स्थान बनाये रखा है। वहीं रूट 67 रन बनाकर इस क्लब में आने वाले दूसरे बल्लेबाज बन सकते थे।

दलीप ट्रॉफी फाइनल अब बेंगलुरु की जगह चेन्नई में खेला जाएगा

मुम्बई । घरेलू क्रिकेट के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी 2026-27 के फाइनल का मैच स्थल बदल दिया गया है। अब फाइनल बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की जगह पर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने कहा है कि यह फैसला अधिक से अधिक क्रिकेट प्रेमियों को इस अहम मुकाबले को स्टेडियम में बैठकर देखने का अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है। ये खिताबी मुकाबला 6 से 10 सितंबर तक खेल जाएगा।

माना जा रहा है कि बोर्ड ने ये कदम घरेलू क्रिकेट को प्रशंसकों के करीब लाने के लिए उठाया है। इसका कारण ये है कि सीओईमुख्य रूप से प्रशिक्षण और विकास पर केंद्रित है और इसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता सीमित है। वहीं विपरीत, चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम बड़े आयोजनों की मेजबानी करने और हजारों दर्शकों को समायोजित करने में सक्षम है। इस बदलाव से न केवल खिलाड़ियों को एक बड़े और अनुभवी मैदान पर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, बल्कि प्रशंसकों को भी घरेलू क्रिकेट की भव्यता और उत्साह का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। फाइनल का स्थल बदल गया है पर टूर्नामेंट के अन्य मुकाबले अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही बेंगलुरु के सीओई में ही खेले जाएंगे। दलीप ट्रॉफी का यह सत्र 23 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें शुरुआती दिन पूर्वी क्षेत्र का सामना पूर्वोत्तर क्षेत्र से होगा, जबकि उत्तरी क्षेत्र की भिड़ंत पश्चिम क्षेत्र से होगी। यह आयोजन भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा मंच है, इसमें युवा प्रतिभाएं अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं और अनुभवी खिलाड़ी भी अपना प्रभाव दिखाते है। गौरतब है कि दलीप ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है, जिसने दशकों से कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को तैयार किया है। 2026-27 सत्र में यह टूर्नामेंट अपने पारंपरिक क्षेत्रीय प्रारूप में लौट आया है, जिसमें कुल छह टीमें भाग ले रही हैं। इन टीमों में मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल हैं। यह प्रारूप क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और प्रतिभा की पहचान को बढ़ावा देता है, जो भारतीय क्रिकेट की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्थल परिवर्तन को लेकर कहा, दलीप ट्रॉफी हमारे घरेलू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है। इसमें हमेशा उच्च स्तर का क्रिकेट देखने को मिलता है और हम चाहते हैं कि प्रशंसकों को फाइनल मुकाबला स्टेडियम में देखने का मौका मिले। सैकिया ने कहा, सीओई में दर्शकों की मौजूदगी को लेकर कुछ प्रतिबंध हैं। इसलिए हमें लगा कि फाइनल को ऐसे मैदान पर कराया जाना सही होगा, जहां प्रशंसक आकर इस मुकाबले का हिस्सा बन सकें। यह बयान बीसीसीआई की उस दूरदृष्टि को दर्शाता है, जिसमें खेल के साथ-साथ उसके दर्शकों को भी समान महत्व दिया जाता है।

दूसरे टेस्ट में कुलदीप की जगह सारांस को मिल सकता है अवसर

मुम्बई । पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा है कि रविवार को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ होने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में स्पिनर कुलदीप यादव को शायद ही शामिल करें। कैफ के अनुसार कुलदीप की जगह पर टीम प्रबंधन नए ऑफ स्पिनर सारांश जैन को अवसर दे सकता है। कैफ ने कहा कि भारतीय टीम को पहले टेस्ट में एक ऑफ-स्पिनर की कमी महसूस हुई थी। उन्होंने कहा कि इसी कारण भारतीय टीम को बीच-बीच में देवदत्त पडिक्कल जैसे वैकल्पिक गेंदबाजों से भी ओवर करवाने पड़े थे। इससे साफ है कि टीम के पास विशेषज्ञ ऑफ-स्पिनर की कमी हैं। कैफ ने कहा, मुझे एक खिलाड़ी की चिंता है और वह हैं कुलदीप यादव। हो सकता है कि वह अगला मैच न खेलें। ये इसलिए भी लगता है क्योंकि जब भी उन्हें गेंदबाजी दी गई, उन्हें छोटे स्पेल दिए गए। उन्हें लंबे स्पेल नहीं मिले। पडिक्कल तक गेंदबाजी करते दिखे क्योंकि बीच में ऑफ-स्पिनर की कमी दिख रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि गॉल में जब दो बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर थे, तो टीम एक ऑफ-स्पिनर की तलाश में थी, और कुलदीप यादव उस भूमिका में उतने प्रभावी नहीं दिखे।

गौरतलब है कि पहले टेस्ट की पहली पारी में कुलदीप ने कुल 14 ओवर फेंके, जिसमें 65 रन देकर केवल एक विकेट लिया। वहीं दूसरी पारी में भी उन्हें 11 ओवर में 38 रन देने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। यह आंकड़े कैफ की चिंता को और बल देते हैं, जो उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। कैफ ने साफ तौर पर कहा, गॉल में जब दोनों बांए हाथ के खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो भारतीय टीम को एक एक ऑफ-स्पिनर की जरुरत महसूस हुई। वहीं कुलदीप को कम गेंदबाजी दिना दिखाता है कि वह हटाये जा सकते हैं। कैफ के अनुसार, इस स्थिति में सारांश को दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव की जगह अंतिम ग्यारह में शामिल किया जा सकता है। सारांश जो एक ऑफ-स्पिनर और ऑलराउंडर हैं, उन्हें वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में शामिल किया गया था, हालांकि पहले मैच में उन्हें अवसर नहीं मिला था। सारांश के पास घरेलू क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है और वे लाल गेंद के प्रारूप पर विशेष ध्यान देते हैं। उनकी मौजूदगी टीम को ऑफ-स्पिन का विकल्प प्रदान करेगी, जिसकी कमी पहले टेस्ट में साफ महसूस की गई।

बीसीबी को हुआ 40 करोड़ का नुकसान, बीपीएल का आयोजन रुका

ढ़ाका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) आर्थिक संकटों में फंस गया है। इससे घरेलू टी20 प्रीमियर लीग (बीपीएल) का आयोजन भी रुक गया है। बीसीबी के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल ने भी माना है कि बोर्ड को नुकसान हुआ है। साथ ही कहा कि जब तक बोर्ड की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हो जाता लीग शुरु नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पिछले दो संस्करणों में हुए 40 करोड़ बांग्लादेशी टका का हमें नुकसान हुआ है। साथ ही कहा कि जब तक इसकी भरपाई नहीं हो जाती, तब तक बीपीएल का आयोजन संभव नहीं है। इससे उभरते हुए क्रिकेटरों का करारा झटका लगा है। तमीम ने कहा कि बोर्ड घाटे के साथ लीग की मेजबानी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा, मैंने कई बार कहा है कि मैं लीग को इस तरह से आयोजित नहीं करना चाहता। पिछले दो सालों में एक टूर्नामेंट में बीसीबी को लगभग 40 करोड़ टका का नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट से बोर्ड को पैसे कमाने चाहिए, न कि नुकसान झेलना चाहिए। उनका मानना है कि वर्तमान में कुछ गलत हो रहा है, जिसके कारण वित्तीय घाटा हो रहा है, और जब तक इन कारणों को ठीक नहीं कर लिया जाता, तब तक हर साल इस लीग के आयोजन का कोई मतलब नहीं है।

शादाब के ऑलराउंड प्रदर्शन से एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स जीती

एंटीगुआ। पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान के अच्छे प्रदर्शन से कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2026 में हुए एक रोमांचक मुकाबले में एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स ने सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स को तीन विकेट से हरा दिया। फाल्कन्स की टीम ने जीत के लिए मिले 188 रनों के लक्ष्य को 19.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। ये उसकी टूर्नामेंट में दूसरी जीत है। इस मैच में एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के कप्तान मोईन अली ने टॉस जीतकर सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। इन टीमों ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 187 रन बनाये। फाल्कन्स की ओर से शादाब ने चार ओवर की में सिर्फ 22 रन दिए और एक विकेट जबकि शामार स्प्रिंगर ने दो विकेट लिए। वहीं जायडन सिल्स और कप्तान मोईन अली को एक-एक विकेट मिला।

इसके बाद जीत के लिए मिले 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हुए एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स ने अच्छी शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज एविन लुईस ने 38 गेंदों पर पांच छक्कों की मदद से सर्वाधिक 48 रनों की पारी खेली, जिसने टीम को मजबूत आधार प्रदान किया। हसन नवाज ने भी 33 रनों का योगदान दिया। इसे बाद शादाब ने 12 गेंदों पर ही 30 रन बनाकर टीम को 19.3 ओवर में 7 विकेट पर 191 रन बनाकर जीत दिलाई।

अपनी किफायती गेंदबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए शादाब को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की सीजन के चौथे मैच में दूसरी जीत थी, जबकि सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स को चौथे मैच में तीसरी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ, अंक तालिका में एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स चौथे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स सातवें स्थान पर खिसक गई है।

श्रीलंका टीम में चांदीमल और कुसल की जगह कामिल और अराच्चिगे शामिल

गॉले। श्रीलंका ने भारतीय क्रिकेट टीम के हाथों पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में मिली करारी हार के बाद टीम में दो बड़े बदलाव किये हैं। अब भारतीय टीम के खिलाफ रविवार से शुरु होने वाले दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांदीमल और युवा कुसल मेंडिस की जगह कामिल मिशारा और सहन अराच्चिगे को शामिल किया गया है। इसके अलावा सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका के भी दूसरे टेस्ट में खेलने की संभावना कम है।

ये तीनों ही चोटिल है। निशंका के भी दूसरे टेस्ट तक फिट होने की कोई उम्मीद नहीं है।

टीम में शामिल नये खिलाड़ी सहन अराच्चिगे ने पिछले महीने भारत ए और श्रीलंका ए के बीच हुए टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। सीरीज के दूसरे मैच में अराच्चिगे ने 127 रनों की अच्छी पारी खेली थी।

वहीं, कामिल ने लंकाई प्रीमियर लीग 2026 के अपने पहले सत्र में ही अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा मेजर क्लब्स टी20 टूर्नामेंट में इस बल्लेबाज ने शतकीय पारी खेली थी।

मुख्य कोच कोच गैरी कर्स्टन ने कहा है कि कुसल मेंडिस को हैमस्ट्रिंग की गंभीर चोट लगी है और वह अगले कुछ समय तक टीम के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।

भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं वाटसन

सिडनी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने कहा है कि भारत उनके लिए दूसरे घर की तरह है क्योंकि यहां उनके देश से भी ज्यादा प्यार मिला है। वॉटसन ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है पर इसके बाद भी भारत में उन्हें अधिक अपनापन और समर्थन मिला। उन्होंने भारतीय प्रशंसकों की सराहना करते हुए कहा कि भारत में उनके प्रदर्शन को लेकर उन्हें कम परखा गया और अधिक प्रोत्साहित किया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया में खराब प्रदर्शन के दौरान उन्हें कड़ी आलोचन झेलनी पड़ती थी।

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट के लिए घोषित की अंतिम ग्यारह, वेदराल्ड की जगह रेनशॉ शामिल

सिडनी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने बांग्लादेश के खिलाफ शनिवार से डार्विन में खेले जाने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए अपनी अंतिम ग्यारह खिलाड़ियों की टीम घोषित कर ली है। इस टीम में एक बदलाव करते हुए मैथ्यू रेनशॉ को जेक वेदराल्ड की जगह पर शामिल कर लिया गया है।

इससे पहले कहा जा रहा था कि सीए स्पिनर नाथन लायन की जगह पर स्कॉट बोलैंड को दूसरे टेस्ट में अवसर दे सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। कप्तान पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लायन की अनुभवी चौकड़ी को टीम में बरकरार रखा गया है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पिछले साल गुलाबी गेंद के टेस्ट मैचों में दो बार ऑल-सीम अटैक खेला था, लेकिन नाथन लायन को लाल गेंद के टेस्ट के लिए फिट होने पर अंतिम एकादश से बाहर रखने का ऐसा आखिरी मौका 14 साल पहले पर्थ के डब्ल्यूएसीए ग्राउंड पर आया था।

वहीं मैथ्यू रेनशॉ ने अपना आखिरी टेस्ट 2023 में भारत में खेला था, जहाँ उन्होंने मध्यक्रम में बल्लेबाजी की थी। अब वह उसी ओपनिंग स्लॉट पर लौट आए हैं, जहाँ उन्होंने 2016-17 में पाकिस्तान के खिलाफ एक युवा 20 वर्षीय खिलाड़ी के तौर पर शतक लगाया था। 12 महीने में 20 टेस्ट खेलने के अपने सफर में ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट से जेक वेदराल्ड को बाहर कर दिया है और खराब फॉर्म से जूझ रहे मार्नस लाबुशेन को भी नंबर 3 पर अपनी जगह बनाए रखने का मौका दिया है।

ऑस्ट्रेलिया टीम- पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर

बांग्लादेश टीम- नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), मेहदी हसन मिराज (उपकप्तान), सौम्या सरकार, शादमान इस्लाम, तंज़ीद हसन तमीम, मोमिनुल हक शोराब, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास, अमित हसन, जैकर अली अनिक, तैजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, सैयद खालिद अहमद, एबादत हुसैन चौधरी, मुस्फिक हसन, लिटन दास, शोरीफुल इस्लाम

कार्यालय नगरपालिका परिषद वारासिवनी, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

दूरभाष-07633-254028,253028 E-Mail-cmowaraseoni@mpurbun.gov.in

क्रमांक / 2430/ लो.वि.वि./PMAY 2.0 /न.पा.प./ 2026 वारासिवनी तारीख 21/08/2026

सूचना

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) योजनान्तर्गत हितग्राहियों की सूची दाव आपत्ति आमंत्रण

मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा प्राप्त निर्देशों के परिपालन में नगरपालिका परिषद वारासिवनी अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) के तहत नवीन आवास निर्माण किये पांच दिवस के भीतर जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह आपत्ति कार्यालयीन समय पर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। समयावधी के पश्चात दावा आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।

संलग्न- पात्र एवं अपात्र हिग्राहियों की सूची

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् वारासिवनी
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद, लांजी, जिला – बालाघाट (म.प्र.)

(Phone : 07635-255202 Email : cmolanji@mpurban.gov.in)

प.क्र. 1026. /ई-टेंडर/2026-27 लांजी, दिनांक – 21-8-26

निविदा सूचना

निविदा आमंत्रित कार्य हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत निविदाकारों से ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

क्र. सं.	टेंडर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की सम्भावित पूर्व लागत	निविदा मूल्य का प्रपत्र भरें (रू.मं)	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	2026_UAD_530372_1 21.08.2026	आवासकालोनोंसार विभिन्न कार्यो हेतु भेटिगामवर/श्रमिक (ड्रायवद/ अर्धकुशल/ अकुशल), राजमिस्त्री, पाथर, ड्राईवर, सम्भावित इत्यादि उपलब्ध कराने का कार्य।	12 माह 8000000.00	10000.00 80000.00	24.09.2026

नोट – निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन या प्रकाशन ऑनलाईन http://www.mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

(श्रीमति रेखा ताराम्चद कावलेसे) अध्यक्ष नगर परिषद, लांजी

(श्री दिनेश कचवाहे) सदस्य लोक निर्माण शाखा नगर परिषद, लांजी

(श्री मधुर बहाने) मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद, लांजी

नगरवाड़ा स्टेशन पर इंटरसिटी के ठहराव और अतिरिक्त पैसेंजर ट्रेन की मांग

जनप्रतिनिधियों ने रेलवे अधिकारियों के नाम स्टेशन मास्टर को सौंपा ज्ञापन

पद्मेश न्यूज़। चांगोटोला। जिले के नगरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर जबलपुर-रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव सहित क्षेत्र की रेल सुविधाओं से जुड़ी तीन प्रमुख मांगों को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने 21 अगस्त को रेलवे अधिकारियों के नाम स्टेशन मास्टर नगरवाड़ा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर एवं मंडल रेल प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के नाम प्रस्तुत किया गया।

जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन के माध्यम से नगरवाड़ा रेलवे स्टेशन सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रेल सुविधाओं की कमी की ओर रेलवे प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी पर्याप्त नहीं होने के कारण दैनिक यात्रियों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों, मजदूरों और मरीजों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बसों का किराया अधिक होने तथा वर्तमान ट्रेनों के समय स्थानीय जरूरतों के अनुरूप नहीं होने से आम नागरिकों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है।

इंटरसिटी का कम से कम दो मिनट हो ठहराव

ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग जबलपुर-रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के नगरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर ठहराव की रखी गई है।

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यह ट्रेन इस रेलमार्ग के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन नगरवाड़ा में इसका ठहराव नहीं होने से क्षेत्र के लोगों को जबलपुर, रायपुर सहित अन्य प्रमुख स्थानों की यात्रा के लिए सुविधाजनक और तेज रेल सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन्होंने मांग की कि इंटरसिटी एक्सप्रेस का नगरवाड़ा स्टेशन पर कम से कम दो मिनट का ठहराव निर्धारित किया जाए, ताकि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके।

छोटे स्टेशनों को जोड़ते हुए चले अतिरिक्त पैसेंजर ट्रेन

दूसरी प्रमुख मांग इस रेलमार्ग पर एक अतिरिक्त पैसेंजर ट्रेन शुरू करने की है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि क्षेत्र के गरीब मजदूर, दैनिक वेतनभोगी, नौकरीपेशा लोग, दूध विक्रेता, सब्जी व्यापारी और विद्यार्थी नियमित रूप से आवागमन करते हैं। वर्तमान रेल सेवाएं सीमित होने के कारण उन्हें मजबूरी में महंगी बस सेवा का सहारा लेना पड़ता है ज्ञापन में मांग की गई कि ऐसी अतिरिक्त पैसेंजर ट्रेन संचालित की जाए जो नगरवाड़ा सहित मार्ग के सभी छोटे-बड़े स्टेशनों पर ठहराव दे। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कम किराए में दैनिक आवागमन की सुविधा मिल सकेगी और रोजगार, शिक्षा तथा व्यापार के अवसरों तक उनकी पहुंच आसान होगी।

नगरवाड़ा में शुरू हो पैसेंजर रिजर्वेशन सुविधा

जनप्रतिनिधियों ने तीसरी मांग के रूप में नगरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की सुविधा शुरू करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र की आबादी करीब एक लाख है और यहां के लोगों को दूरदराज की यात्रा के लिए आरक्षण कराने जिला मुख्यालय बालाघाट या नैनपुर जाना पड़ता है। नगरवाड़ा से बालाघाट करीब 60 किलोमीटर तथा नैनपुर करीब 30 किलोमीटर दूर होने के कारण ग्रामीणों को आरक्षण के लिए अतिरिक्त समय और धन खर्च करना पड़ता है जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि नगरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर आरक्षण खिड़की शुरू की जाती है तो इससे क्षेत्रवासियों को बड़ी सुविधा मिलेगी और रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

25 पंचायतों के ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ

ज्ञापन में कहा गया कि नगरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी का ठहराव और अतिरिक्त पैसेंजर ट्रेन शुरू होने से आसपास की करीब 25 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को कॉलेज जाने, मरीजों को जिला अस्पताल पहुंचने नौकरीपेशा लोगों को जिला मुख्यालय जाने तथा छोटे व्यापारियों को अपने व्यवसाय के सिलसिले में आवागमन करने में काफी सुविधा होगी इसके अलावा क्षेत्रवासियों ने नगरवाड़ा से डोंगरगढ़ के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू किए जाने की मांग को भी उपयोगी बताया है। उनका कहना है कि डोंगरगढ़ सहित अन्य प्रमुख स्थानों के लिए सीधी रेल सुविधा मिलने से क्षेत्र के लोगों को यात्रा में काफी राहत मिलेगी।

रेलवे प्रशासन से सहानुभूतिपूर्वक विचार की मांग

जनप्रतिनिधियों ने रेलवे प्रशासन से क्षेत्र की भौगोलिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नगरवाड़ा में इंटरसिटी का ठहराव अतिरिक्त पैसेंजर ट्रेन तथा रिजर्वेशन सुविधा केवल किसी एक गांव की मांग नहीं बल्कि आसपास के बड़े ग्रामीण क्षेत्र की जनहित से जुड़ी आवश्यकता है ज्ञापन सौंपते समय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि रेलवे प्रशासन यात्रियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए नगरवाड़ा स्टेशन की यात्री सुविधाओं में विस्तार करेगा और क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही रेल सुविधाओं की मांगों को शीघ्र पूरा करने की दिशा में सकारात्मक पहल करेगा।

ग्राम पंचायत डोंगरिया में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डोंगरिया के सभा हाल में 20 अगस्त को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने स्व. राजीव गांधी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया कार्यक्रम में ग्राम पंचायत की सरपंच हस्तरेखा वारके, उपसरपंच दयाराम बाजनघाटे सहित

पंचगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिक उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के व्यक्तित्व एवं देश के विकास में उनके योगदान को स्मरण किया इस अवसर पर ग्रामीणों के बीच स्वल्पाहार का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि स्व. राजीव गांधी की जयंती उनके विचारों और देश के प्रति योगदान को याद करने का अवसर है।

शंकरघाट से गुप्तेश्वर महादेव डोंगरगांव के लिए कल निकलेगी भव्य कांवड़ यात्रा

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। सावन के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बब्बर सेना के तत्वाधान में गुप्तेश्वर महादेव डोंगरगांव के लिए भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जावेगी। ये कांवड़ यात्रा शंकरघाट शिवमंदिर से प्रारंभ होगी। इस संबंध में बब्बर सेना प्रमुख हितेश माहुले ने बताया कि कांवड़ यात्रा 23 अगस्त रविवार को शहर मुख्यालय के वैनगंगा तट शंकर घाट धाम से सुबह 10 बजे निकलेगी। जो शहर के प्रमुख मार्गो का भ्रमण करते हुए कोसमी, नवेगांव, नैतरा, लिंगा होते हुए हट्टा पहुंचेगी। हट्टा में रात्रि भोजन एवं विश्राम किया जाएगा। उसके बाद 24 अगस्त की सुबह 4 बजे कांवडिया डोंगरगांव के लिए रवाना होंगे। डोंगरगांव में गुप्तेश्वर महादेव पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की जाएगी। डोंगरगांव में सभी कांवडियों व श्रद्धालु भक्तों के लिए भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इस कांवड़ यात्रा में हर वर्ष जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से कांवडियां शामिल होते है। इस अवसर पर बब्बर सेना के सभी पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अधिकाधिक उपस्थिति का आव्हान किया है।

हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजेगा कायदी से बालाघाट मार्ग

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। वारासिवनी। सावन मास के पावन अवसर पर धर्म और आस्था की अविरल धारा बहने वाली है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर ग्राम कायदी से आगामी 23 अगस्त को श्रद्धालुओं की भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। बब्बर सेना के तत्वावधान में आयोजित इस धार्मिक यात्रा को लेकर शिवभक्तों में विशेष उत्साह और उमंग का वातावरण है। कांवड़ यात्रा के दौरान हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा मार्ग शिवमय होने की संभावना है ग्राम कायदी से श्रावण मास के अवसर पर कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा पिछले करीब पांच वर्षों से चली आ रही है। इसी धार्मिक एवं आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी बड़ी संख्या में शिवभक्त कांवड़ लेकर

भगवान भोलेनाथ के धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। यात्रा को लेकर ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 23 अगस्त को सुबह 8 बजे कांवड़ यात्रा ग्राम कायदी से प्रारंभ होकर बालाघाट स्थित बैनगंगा नदी के शंकर घाट पहुंचेगी। यहां शिवभक्त विधि-विधान और श्रद्धाभाव के साथ मां बैनगंगा के पवित्र जल का पूजन करेंगे और उसे कांवड़ में धारण कर आगे की धार्मिक यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। पवित्र जल लेकर कांवडिए गुप्तेश्वर धाम महादेव, डोंगरगांव पहुंचेंगे। जहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और सुख-समृद्धि की कामना करेंगे।

श्रद्धा, सेवा और संकल्प का पर्व है कांवड़ यात्रा - रुद्रसिंह लिल्हारे

शिवभक्त रूद्रसिंह लिल्हारे ने बताया कि बब्बर सेना के तत्वावधान में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा को लेकर शिवभक्तों में विशेष उत्साह है और अधिक से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। कायदी से निकलने वाली यह यात्रा भी श्रद्धालुओं के लिए भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है 23 अगस्त को जब ग्राम कायदी से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ होगा तब श्रद्धालुओं के कदम भगवान भोलेनाथ की भक्ति में आगे बढ़ेंगे और हर-हर महादेव के जयघोष से यात्रा मार्ग गुंजायमान होगा। पवित्र जल लेकर गुप्तेश्वर धाम पहुंचने के बाद भगवान महादेव के जलाभिषेक के साथ यह धार्मिक यात्रा श्रद्धा और आस्था के पावन संकल्प को पूर्ण करेगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिठाई दुकानों की जांच में लिए नमूने और एक्सपायरी सामग्री नष्ट

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। रक्षाबंधन त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन बालाघाट द्वारा मिठाई दुकानों, होटल एवं रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए तथा एक्सपायरी एवं दूषित खाद्य सामग्री का मौके पर ही विनष्टीकरण कराया गया।

खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा मां शक्ति वैशाली बीकानेर स्वीट्स की जांच की गई। इस दौरान खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के साथ दुकान की साफ-सफाई और स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कलाकंद एवं रसगुल्ला के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। मल्लिकार्जुन होटल के सामने स्थित राजेश मिष्ठान भंडार का भी निरीक्षण किया गया। जांच के

दौरान लगभग 2,000 रुपये मूल्य की आउटडेटेड खाद्य सामग्री पाई गई, जिसका मौके पर ही विनष्टीकरण कराया गया। इसके अलावा मलाई पेड़ा एवं मलाई बर्फी के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं।

बालाघाट बस स्टैंड क्षेत्र स्थित होटल एवं रेस्टोरेंट में भी खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निरीक्षण एवं नमूना कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यश बेकरी एवं शिवाय आइसक्रीम हब की जांच की गई। यश बेकरी से मावा पेड़ा एवं मलाई पेड़ा के नमूने जांच के लिए लिए गए। जांच के दौरान शिवाय आइसक्रीम हब बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के संचालित पाया गया। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा प्रकरण तैयार किया गया तथा मौके पर ही खाद्य कारोबार बंद कराया गया। दुकान में लगभग 1,500 रुपये मूल्य की दूषित एवं एक्सपायरी खाद्य सामग्री पाई गई, जिसका मौके पर विनष्टीकरण कराया गया।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध आगामी कार्रवाई की जाएगी। रक्षाबंधन त्यौहार के मद्देनजर खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच और नमूना कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

तेलंगाना सीएम को केंद्र ने नहीं दी अमेरिका जाने की मंजूरी, सीएमओ ने दी जानकारी

हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है। सीएमओ ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। सीएमओ के मुताबिक सीएम रेड्डी के नेतृत्व वाला तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधिमंडल अमेरिका दौरा नहीं कर सकेगा। विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक आधार पर क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया है। रेवंत रेड्डी फिलहाल लंदन में हैं। उन्हें अमेरिका के बोस्टन जाना था और 30 अगस्त को हैदराबाद लौटना था, लेकिन अब वे 23 अगस्त को हैदराबाद आएंगे। हालांकि सीएम रेड्डी ने अधिकारियों को अमेरिका जाए, बिना वहां के संस्थानों के साथ सभी एमओयू और साझेदारी समझौते पूरे करने के निर्देश दिए हैं।

आंसर की के लिए फीस लेना पैसा कमाना नहीं है, आपत्ति सही तो पैसे होंगे वापस

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा के बाद जारी आंसर की को चैलेंज करने वाली फीस पर सफाई दी। एनटीए ने कहा कि आंसर की में अगर किसी सवाल का जवाब गलत लगता है तो उम्मीदवार चैलेंज कर सकता है। इसके लिए हर सवाल पर 200 रुपए फीस देनी होगी। एजेंसी ने कहा कि फीस इसलिए है, ताकि बेवजह की आपत्तियां न आएं। इसका मकसद छात्रों से पैसे कमाना नहीं है। अगर आपको सच में आंसर की में गलती मिली है और आपकी आपत्ति सही है तो पैसे भी वापस मिलेंगे और लाखों छात्रों का रिजल्ट सही हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनटीए ने 16 अगस्त को यूजीसी-नेट के 84 सब्जेक्ट के परीक्षा की आंसर की जारी की थी। हालांकि उसी दिन एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। एनटीए ने माना कि इन विषयों के प्रश्न पत्र में सिक्योरिटी और प्रिंटिंग की गलतियां थीं। एनटीए ने कहा कि पेपर्स में पहले पूछे जा चुके सवाल दोहराए गए थे। आंसर-की जारी करने के बाद छात्रों ने गड़बड़ियों का जिक्र किया था। इन्हें केवल सवाल हटाकर ठीक नहीं किया जा सकता था। एनटीए ने तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा की तारीख जारी की है। अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं अब 9 और 10 सितंबर को होंगी। एनटीए ने पहले 22 से 30 जून तक यूजीसी-नीट परीक्षा कराई थी। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी।

इस बार राखी की मिठास बिगाड़ेगी महंगाई

- शकर, गुड़, नारियल, तेल, दालें और अन्य खाद्य सामग्री के भावों में भारी तेजी

- बहनें असमंजस में, भाइयों के यहां राखी बांधने जाना भी महंगा पड़ेगा

भोपाल। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व इस बार महंगाई को लेकर फीका रह सकता है। बसों और परिवहन किराया से लेकर शकर, गुड़, नारियल, तेल, दालें और अन्य खाद्य सामग्री के भावों में भारी तेजी से आम उपभोक्ता का बजट बिगड़ गया है।

रक्षाबंधन का त्योहार 7 दिन दूर है और पर्व के उत्साह पर महंगाई का असर साफ देखने को मिल रहा है। त्योहारी सीजन शुरू होते ही रसोई के बजट से लेकर बाजार की हर खाद्य-सामग्री के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। रक्षाबंधन से ठीक पहले चीनी के दाम खेरची में 64 से 65 रुपए प्रतिकिलो तक पहुंच गए हैं। कई इलाकों में इसके 75 रुपए तक तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इसका सीधा असर हलवाइयों के लिए मिठाई बनाने की लागत (मेकिंग कॉस्ट) बढ़ गई है, वहीं चीनी के साथ-साथ दूध, मावा और ड्राई फ्रूट्स (जैसे किशमिश और काजू) की कीमतों में तेजी आई है। काजू कतली, गुलाब जामुन और रसमलाई जैसी पारंपरिक मिठाइयों के दाम भी बढ़ गए हैं। रक्षाबंधन की थाली के रेशमी धागे, फैंसी राखियां, पूजा की थाली महंगी हो गई, वहीं नारियल भी इस बार 35 से 40 रुपए का हो गया है। अब बढ़ी हुई कीमतों के कारण लोग इस बार मिठाइयों और उपहार बेहद सोच-समझकर सीमित मात्रा में ही खरीद रहे हैं।

व्यवसायी मिठाई के दाम बढ़ाने के पक्ष में नहीं

इस बार चीनी, रिफाइंड ऑयल, मैदा, बेसन समेत अन्य खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से मिठाई की लागत जरूर बढ़ी है, लेकिन कई कारोबारी त्योहार के मौके पर मिठाइयों के दाम बढ़ाकर बहनों पर अतिरिक्त बोझ डालने के पक्ष में नहीं हैं। भाई-बहन के इस पर्व पर राखी के साथ मिठाई खरीदने की परंपरा होने के कारण दुकानदारों के सामने लागत और बिक्री के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी है। कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। फिलहाल कीमतों को यथावत रखने का प्रयास मिठाई निर्माताओं का रहेगा।

20 रुपए की रिश्वत का 30 साल चला मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने किया आरोपियों को बरी

नई दिल्ली। 20 रुपए की रिश्वत लेने पर दो लोगों को ट्रायल कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई थी। हालांकि करीब 30 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। पूरा मामला इनकम सर्टिफिकेट जारी करने से जुड़ा है। आरोप है कि इसके लिए 20 रुपए की रिश्वत ली गई थी। अब 30 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के इस मामले में दो सरकारी कर्मचारियों को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस मामले में एक साल की जेल की सजा सुनाई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन्हें तीन दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सभी सबूतों पर गौर करने के बाद हमने पाया कि ये दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप को बिना किसी शक के साबित करने के लिए काफी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत की मांग एक जरूरी बात है, जो इस मामले में नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब रिश्वत की कोई मांग साबित नहीं हुई, जैसा कि दोनों अदालतों ने माना है।

पानी समुद्र में बहे और किसान बूंद-बूंद को तरसे ये ठीक नहीं - शाह

- दो राज्यों के जल विवाद पर अमित शाह ने दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंतरराज्यीय जल विवादों को बातचीत से सुलझाने के सुझाव को दक्षिण भारत के राज्यों ने समर्थन दिया है। गुरुवार को दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा, जहाँ लोकसभा सीटों के परिसीमन पर भी गहन चर्चा हुई। अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अपने राज्य के हितों की रक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर पानी की कमी के कारण किसी राज्य को वर्षों तक वंचित रहना पड़े और पानी समुद्र में बहता रहे, तो यह किसी के हित में नहीं है।

शाह ने भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी से बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र से कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने का सुझाव दिया, जिससे कई जलमार्ग भी विकसित हो सकते हैं। उन्होंने उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे के आठ में से पांच ब्रिटिश-पूर्व विवादों के सफल समाधान का उदाहरण दिया, जहां पांच महीने पहले अंतिम समझौता हुआ था। हालांकि, बैठक में लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा विवाद का विषय बन गया। दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान की आशंका जताई। कर्नाटक और तमिलनाडु ने मांग की कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें अगले 25 वर्षों तक बनी रहें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने परिषद से प्रस्ताव पारित

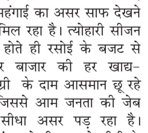

कर केंद्र से 1971 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाए रखने और महिलाओं के आरक्षण को मौजूदा सीटों के भीतर ही लागू करने की मांग की।

अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपनी चिंताओं के साथ सामने आए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु को मेकेदातु बांध परियोजना से उनके हितों की रक्षा का आश्वासन दिया, हालांकि तमिलनाडु के मंत्री ने स्पष्ट किया कि कावेरी जल विवाद पर बैठक में चर्चा नहीं हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कुप्पम के रास्ते आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और अमरावती-बेंगलुरु-चेन्नई ट्रांजिट नेटवर्क का प्रस्ताव रखा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे के मामलों को गृह मंत्रालय के साथ सुलझाने पर सहमति जताई। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने मुल्लापेरियार बांध का मुद्दा उठाया और स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहकारी संघवाद पर जोर दिया। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमरका ने कृष्णा नदी के पानी पर राज्य के अधिकारों की सुरक्षा और सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहयोग मांगा, जबकि पुडुचेरी ने सालभर पानी की उपलब्धता के लिए केंद्र और तमिलनाडु से सहयोग की अपील की।

वंदे मातरम् पर पूछा, क्या मोदी ने गाया पूरा राष्ट्रगीत?

कपिल सिब्बल का अमित शाह पर पलटवार

नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने वंदे मातरम् के केवल दो अंतरे गाने के कांग्रेस के फैसले को राष्ट्र-विरोधी बताने संबंधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर तीखा पलटवार किया है। शुक्रवार को सिब्बल ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए वंदे मातरम् का पूरा संस्करण गाया था।

निर्दलीय सांसद सिब्बल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी पोस्ट में पूछा, अमित शाह ने वंदे मातरम् के दो अंतरे गाने के कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के फैसले को राष्ट्र-विरोधी बताया। मेरा सवाल है क्या भाजपा ने 1950 से निजी या आधिकारिक कार्यक्रमों में इसके सभी अंतरे गाए? क्या मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते ऐसा किया? क्या वाजपेयी ने ऐसा किया? उन्होंने आगे कहा, तो क्या आप उस समय राष्ट्र-विरोधी थे? यह आपकी वोट बैंक की राजनीति को उजागर करता है। अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि पार्टी का वंदे मातरम् के केवल दो अंतरे गाने का फैसला राष्ट्र-विरोधी है और इसका मकसद कानून की खुली अवहेलना कर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण करना है। कांग्रेस ने शाह के इस बयान पर पहले भी पलटवार करते हुए कहा था कि भाजपा छात्रों और राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी जैसे मामलों से ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रगीत को लेकर विवाद खड़े करना चाहते है, जबकि उसके (भाजपा के) नेता झूठे और नकली राष्ट्रवादी हैं। यह जुबानी जंग कांग्रेस कार्य समिति के बुधवार को लिए गए उस फैसले के बाद शुरू हुई, जिसमें वंदे मातरम् का पूरा संस्करण गाने के बजाय केवल दो अंतरे गाने का निर्णय लिया गया था।

पद्मेश न्यूज़
शहर | समाज | गांव

12

बालाघाट एक्सप्रेस

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

न्यूज गैलरी

बालाघाट में 23 से 26 अगस्त तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

आंधी-तूफान, तेज हवाओं और बिजली कड़कने की भी संभावना

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से प्राप्त 5 दिवसीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 23 से 26 अगस्त 2026 के दौरान बालाघाट जिले में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। पूर्वानुमान के अनुसार इस दौरान आंधी-तूफान, तेज हवाएं चलने तथा बिजली कड़कने की भी संभावना है। आसमान में भारी बादल छाए रह सकते हैं और कई स्थानों पर तेज बारिश की स्थिति बन सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 27.1 से 27.8 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22.2 से 22.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 98 से 99 प्रतिशत तथा दोपहर में 79 से 82 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। हवा की गति लगभग 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे रहने और हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिलेवासियों से सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। विशेष रूप से आंधी एवं बिजली कड़कने के समय खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है। किसानों एवं ग्रामीणों से भी मौसम की स्थिति पर नजर रखने और आवश्यक सावधानियां बरतने का आग्रह किया गया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से मौसम संबंधी नवीनतम विभागीय अपडेट पर नजर रखने की अपील की है।

बिरसा में बच्चों की मौत के मामले में आदिवासी समाज का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

जनपद पंचायत के सामने टेंट लगाकर बैठे युवा, मृत बच्चों के परिजनों को 25-25 लाख की सहायता और जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन की मांग

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

बिरसा क्षेत्र में बच्चों की मौत के मामले ने अब आंदोलन का रूप ले लिया है। मृत बच्चों के परिजनों को सहायता राशि और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर समस्त आदिवासी समाज के युवाओं ने 21 अगस्त से जनपद पंचायत के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। युवाओं ने जनपद पंचायत के सामने टेंट लगाकर आंदोलन शुरू किया और शासन-प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अपनी मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग की। धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि बिरसा क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में बीमारी के चलते अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ने की बात सामने आ रही है। आंदोलनकारियों ने मृत बच्चों के प्रत्येक परिवार को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि देने, मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल निलंबित करने तथा प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुधारने की मांग की है।

धरने पर बैठे संजय धुर्वे ने बताया कि बिरसा क्षेत्र में बच्चों की मौत का सिलसिला गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अभी तक अलग-अलग गांवों में 24 बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर कदम उठाए जाते तो स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के इस्तीफे और मृत बच्चों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। सत्येंद्र इनवाती ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले की जानकारी पहले ही सांसद भारती पारधी को दी गई थी, लेकिन जनवरी से अगस्त तक इस मामले में अपेक्षित संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था और जिला प्रशासन को बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन को इस मामले की जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि मृत बच्चों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए और जिला मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. परेश उपलव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय रहते पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखाई गई। आंदोलन में शामिल ललित उइके और मोहन मरकाम ने भी मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। ललित उइके ने आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब नेता और मंत्री क्षेत्र में आते हैं तो आदिवासी समाज के बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नृत्य के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जब इन्हीं आदिवासी बच्चों के सामने स्वास्थ्य जैसी गंभीर समस्या खड़ी होती है तो उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्व या सामाजिक-सांस्कृतिक आयोजनों में बच्चों की सहभागिता अपनी जगह है, लेकिन केवल नेताओं और मंत्रियों के स्वागत के लिए आदिवासी बच्चों को नृत्य करवाना और दूसरी ओर उनके गांवों में स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहना उचित नहीं है। उन्होंने इस व्यवस्था की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। मोहन मरकाम ने कहा कि देश को आजाद हुए करीब 80 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन बैगा आदिवासी समाज के उत्थान की स्थिति आज भी चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में लोग आज भी नदी-नालों के पानी पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। उन्होंने बैगा विकास से जुड़े विभाग और व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि जिस व्यवस्था का लाभ सीधे आदिवासी समाज तक पहुंचना चाहिए, वह प्रभावी रूप से जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। आंदोलनकारियों ने कहा कि उनका धरना तब तक जारी रहेगा, जब तक शासन उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेता। युवाओं ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन से आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। मृत बच्चों के परिवारों को आर्थिक सहायता, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था को लेकर शासन को स्पष्ट निर्णय लेना होगा।

गर्रा में लालबर्रा रोड पर कार मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार -दो व्यक्ति घायल

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम गर्रा से लालबर्रा मार्ग पर गुरुवार रात एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को डायल-112 की मदद से जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचाया गया।दोनो घायल बृजकिशोर पिता नंदकिशोर यादव 42 ग्राम पनबिहरी, थाना लालबर्रा और नंदलाल पिता संतलाल यादव 42 निवासी ग्राम चाचेरी थाना लामता निवासी है। दोनों का उपचार जिला अस्पताल बालाघाट में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार घायल बृजकिशोर यादव और नंदलाल यादव मजदूरी करते हैं। 20 अगस्त की दोपहर बृजकिशोर यादव और नंदलाल यादव मोटरसाइकिल से गोंदिया गए थे। गोंदिया से काम निपटाने के बाद देर शाम मोटरसाइकिल से वापस पनबिहरी लालबर्रा लौट रहे थे। मोटरसाइकिल बृजकिशोर यादव चला रहे थे।बताया गया कि रात करीब 8:30 बजे जब दोनों ग्राम गर्रा के आगे लालबर्रा की ओर जा रहे थे तभी सड़क किनारे एक सफेद रंग की कार खड़ी थी। कार के पास कुछ लोग शराब पी रहे थे। बृजकिशोर यादव मोटरसाइकिल लेकर कार को पार कर आगे बढ़े। इसके कुछ देर बाद कार चालक ने तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ समय के लिए बेहोश हो गए। दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।घटना की सूचना मिलने पर डायल112 मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचाया गया। उपचार के बाद दोनों को होश आया। फिलहाल दोनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दुर्घटना की जांच कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही है।

बालाघाट में प्रशासनिक फेरबदल, अभिषेक सराफ का तबादला, तनुश्री मीणा होंगी नई जिला पंचायत सीईओ

वारासिवनी एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल श्योपुर जिला पंचायत सीईओ बने, पेटलावद एसडीएम तनुश्री मीणा को बालाघाट जिला पंचायत की कमान

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव के आदेश पर प्रदेश के करीब 32 आईएएस अधिकारियों के

स्थानांतरण की सूची जारी की गई है। इस प्रशासनिक फेरबदल में बालाघाट जिले के कई अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बालाघाट जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ का स्थानांतरण नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में अपर आयुक्त के पद पर किया गया है। उनके स्थान पर सुश्री तनुश्री मीणा को बालाघाट जिला पंचायत का नया मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। तनुश्री मीणा वर्ष 2022 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में झाबुआ जिले के पेटलावद में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पद पर सेवाएं दे रही थीं। शासन के नए आदेश के बाद अब उन्हें बालाघाट जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके सामने जिले में ग्रामीण विकास, पंचायत स्तर की योजनाओं के क्रियान्वयन और जिला पंचायत से जुड़े कार्यों को गति देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। प्रशासनिक फेरबदल के तहत वारासिवनी एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल का भी स्थानांतरण किया गया है। उन्हें जिला पंचायत श्योपुंर का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। कार्तिकेय जायसवाल के स्थानांतरण के बाद फिलहाल वारासिवनी एसडीएम के पद पर किसी नए अधिकारी की पदस्थापना नहीं की गई है। ऐसे में अब प्रशासन की ओर से इस महत्वपूर्ण अनुविभाग की जिम्मेदारी किस अधिकारी को सौंपी जाती है। यह अभी स्पष्ट नही हुआ हैं , इसी क्रम में बालाघाट में सहायक कलेक्टर के रूप में सेवाएं दे रहे आकाश अग्रवाल का भी स्थानांतरण किया गया है। उन्हें जिला सीधी में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं बैहर एसडीएम अर्पित गुप्ता को जिला बड़वानी में जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। उनके स्थान पर अब बैहर एसडीएम की जिम्मेदारी नए अधिकारी को सौंपी गई है। शासन की तबादला सूची में वर्ष 2024 बैच के आईएएस अधिकारी अनिकेत शांडिल्य को भी बालाघाट जिले में नई जिम्मेदारी मिली है। अनिकेत शांडिल्य वर्तमान में सहायक कलेक्टर जिला सतना के पद पर कार्यरत थे। अब उन्हें बैहर का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बनाया गया है। नई पदस्थापना के बाद वे बालाघाट जिले में बैहर एसडीएम के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। एक साथ जिले के कई प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण से बालाघाट के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव आया है। जिला पंचायत सीईओ, वारासिवनी एसडीएम, बैहर एसडीएम और सहायक कलेक्टर स्तर पर हुए इन तबादलों के बाद अब नई पदस्थापनाओं के साथ प्रशासनिक कामकाज आगे बढ़ेगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमेश बागरेचा द्वारा पद्मेश पब्लिकेशन, वार्ड नं.9, गुजरी चौक, बालाघाट (म.प्र.) से मुद्रित कराकर दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय, काली पुतली चौक, बालाघाट(म.प्र.) से प्रकाशित,
प्रधान संपादक : उमेश बागरेचा, मो.नं. :9425138710, , ई-मेल- balaghatexpress@gmail.com पंजीयन क्रं. MPHIN/2009/32311, न्यायालयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट